



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ७] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 15, 1986/माघ 26, 1907

No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 15, 1986/MAGHA 26, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Faging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(यहां संशोधन को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए लौकिक आदेश और अधिसूचनाएं
statutory orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1986

सूचनाएं

का. भा. 541—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में संशोधन प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री एम. आर्षी हवा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे अहमदाबाद (गुजरात) व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आवेदन इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(61)/85-न्या.]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 27th January, 1986

NOTICE

S.O. 541.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri M. I. HAVA Advocate, for appointment as a Notary to practice in Ahmedabad.

1403 G/7/85—1

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(61)/85-Judl.]

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1986

का. भा. 542—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में संशोधन प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री अल्लार्क एम. शेख, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकरण को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे गांधीनगर मेहसाना, अहमदाबाद (गुजरात) व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आवेदन इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(22)/86-न्या.]

New Delhi, the 28th January, 1986

S.O. 542.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Allarkh M. Shaikh Advocate for appointment as a Notary to practice in Gandhinagar Mehsana, Ahmedabad.

2. Any objection to the appointment of the said persons as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(22)/86-Judl.]

का. प्रा. 543—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री मोती लाल सैन, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे बाली (राजस्थान) व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5 (19)/86-न्या.]

S.O. 543.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Moti Lal Sain Advocate, for appointment as a Notary to practise in Bali (Rajasthan).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(19)/86-Judl.]

का. प्रा. 544—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री मूल चन्द गंधी, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे अलवर (राजस्थान) व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5 (17)/86-न्या.]

S.O. 544.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Mool Chand Gandhi, Advocate, for appointment as a Notary to practise in Alwar;

2. Any objection to the appointment of the said persons as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(17)/86-Judl.]

का. प्रा. 545—नोटरीज नियम 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री एन. द्वारकानाथ (एडवोकेट) ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे मैसूर (कर्नाटक) व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5 (8)/86-न्या.]

S.O. 545.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri H. Dwarakanath, Advocate, for appointment as a Notary to practise in Mysore.

2. Any objection to the appointment of the said persons as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(6)/86-Judl.]

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1986

का. प्रा. 546—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्रीमती निर्मला सिंह नय्यर, एडवोकेट, नीति बाग, नई दिल्ली, ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे नई दिल्ली में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5 (52)/85-न्या.]

New Delhi, the 29th January, 1986

S.O. 546.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Mrs. Nirmala Singh Nayyar, Advocate, Nitibagh, New Delhi for appointment as a Notary to practise in New Delhi;

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(52)/85-Judl.]

का. प्रा. 547—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, जयपुर 1 ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे जयपुर 1 व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. प्रा. 5/41/85-न्या.]

S.O. 547.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Ramesh Chandra Agarwal, Advocate, Jaipur-1 for appointment as a Notary to practise in Jaipur.

2. Any objection to the appointment of the said persons as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(41)/85-Judl.]

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1986

का. प्रा. 548—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री हनुमान सिंह, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे रायसिंह नगर (राजस्थान) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाये।

[सं० 5(53)/85-न्या०]

श्री० एन० पोट्टार, सक्षम प्राधिकारी

New Delhi, the 31st January, 1986

S.O. 548.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority under rule 4 of the said Rules, by Shri Iqbal Singh, Advocate, for appointment as a Notary to practise in Rai Singh Nagar (Rajasthan).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(53)/85-Indl.]

R. N. PODDAR, Competent Authority

कार्मिक लोक शिक्षण तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1986

का. घा 549.—केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली के न्यायालय में श्री राजेन्द्र सिंह सेठिया और अन्य के विरुद्ध दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना नियमित मामला सं. 1/85-सी-आई-यू-(2) के अभियोजन के संचालन के लिए श्री कृष्ण नारायण, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. 225/2/86-ए.बी.डी.-II]

के.आर गोपाल राव, सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSION

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 29th January, 1986

S.O. 549.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Krishan Narain, Advocate, as a Special Public Prosecutor for conducting the prosecution of Delhi Special Police Establishment Regular Case No. 1/85-CIU(II) against Shri Rajendra Singh Sethia and others in the Court of the Chief Metropolitan Magistrate, Delhi.

[No. 225/2/86-AVD. II]

K. R. GOPAL RAO, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1986

भाषण

का. घा. 550.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित, धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 120-ब, 420, 468, 468 और 471 के अधीन पुलिस थाना झलीपुर, 24 परगना, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकृत प्रथम इतिहास रिपोर्ट सं. 1985 का 33 तारीख 29-1-85 जो दण्डिक घरील सं. 1984 का 275 और 1984 का 276 में तारीख 21-12-1984 की माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दायित्व तात्परित कूटस्थता आदेश के आधार पर प्रथम प्रतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, झलीपुर 24 परगना, कलकत्ता द्वारा जगतार सिंह और नीलमणि घोष उर्फ मोना को निर्मुक्त किये जाने से संबंधित है, को वाजत भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120-ब, 420, 468, 468 और

और 471 के अधीन दण्डनीय अपराधों और उन्हीं अपराधों और उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले ऐसे ही सम्पत्ति के अनुकूल में किये गए किसी अन्य अपराध के संबंध में या उनसे सम्बन्धित प्रकरणों, दुष्परणों और पड़ोशों के अन्वेषण के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार को सहमति से, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल राज्य पर करती है।

[संख्या 225/29/85-ए. बी. डी. (II)]

एस. के. मिश्र, निदेशक

New Delhi, the 30th January, 1986

ORDER

S.O. 550.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the Government of West Bengal hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of West Bengal for the investigation of offences punishable under sections 120-B, 420, 466, 468 and 471 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offences and any other offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts, in regard to the FIR No. 33 of 1985 dated 29-1-1985 registered at PS. Alipore, 24 Parganas, Calcutta under section 120-B, 420, 466, 468 and 471. Indian Penal Code relating to the release of Jagtar Singh and Nilomani Ghosh also: Mona by the Court of 1st Additional District and Sessions Judge, Alipore, 24 Parganas, Calcutta on the basis of forged orders purported to have been passed by the Hon'ble Supreme Court of India on 21-12-1984 in Criminal Appeal Nos. 275 of 1984 and 276 of 1984 respectively.

[No. 228/29/85-AVD. II]

S. K. MISRA, Director

विश्व मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1986

भाषण

का. घा. 551.—परिचालन की जानकारी के लिए, एतद्वारा अधिभूतिन दिया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विशाल और प्राधिकारी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 8 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के छह (ii) पैरा/एक/दो के प्रयोजनों के लिए "विश्व विद्यालय" प्रयोग के अर्हत निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

- (i) यह कि गुलबर्ग विश्वविद्यालय, गुलबर्ग अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उक्त द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक् लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त विश्वविद्यालय अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणों, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए पद्धतिबद्ध किया जाये और सूचित किया जाये।
- (iii) यह कि उक्त "विश्व विद्यालय" अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियों, वेतनदरियाय दर्शाते हुए गुलबर्ग पत्र की एक एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त "विश्वविद्यालय" केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त विभाग (राजस्व विभाग) नई दिल्ली की अनुमोदन की

समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र खर्द कर लिया जाएगा।

संस्था

"तुलसी विष्णु विद्यालय, प्रशासनिक कार्यालय, गुलबर्गा"

यह अधिसूचना 10-9-1985 से 31-3-1987 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[संख्या. 6553 (फा.सं. 203/1986/84-आ. क. नि. II)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 2nd January, 1986

INCOME-TAX

S.O. 551.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 (Thirty five) one/two of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "University" subject to the following conditions :—

- That the Gulbarga University, Gulbarga will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- That the said University will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- That the said University will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
- That the said University will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months, in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Gulbarga University, Administrative Officer, Gulbarga.

This Notification is effective for a period from 10-9-1985 to 31-3-1987.

[No. 6553 (F. No. 203/1996/84-ITA. (II)]

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1986

आयकर

क्र.सं. 552—इस कार्यालय की दिनांक 7-4-1984 की अधिसूचना सं. 5750 (फा.सं. 203/86/84-आ.क.नि. 3) के शिलशिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रायोगिक विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के भाग पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिये "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात्,—

- यह कि एस्कोर्ट्स हार्ट इंस्टिट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(ii) यह है कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी किया कलापों की वार्षिक विवरणों, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रमोशन के लिये अधिकृत किया जाये और उसे सूचित किया जाये।

(iii) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय वर्षांत द्वारा अपने संपरिचित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिभाषित, देनदारियों वर्षांत द्वारा तुलना-पत्र को एक-एक प्रति, प्रत्येक 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगी।

(iv) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समर्पित से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिये आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र खर्द कर दिया जायेगा।

संस्था

"एस्कोर्ट्स हार्ट इंस्टिट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर, एच-2, कनाट सर्कस, नई दिल्ली"

यह अधिसूचना 1-4-1985 से 31-12-1986 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

[सं. 6552 (फा.सं. 203/43/85-आ.क.नि. II)]

New Delhi, the 2nd January, 1986

INCOME-TAX

S.O. 552.—In continuation of this Office Notification No. 5750 (F. No. 203/86/84-ITA. II) dated 7-4-1984, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five) One/Two of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions :—

- That the Escorts Heart Institute & Research Centre, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.
- That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Escorts Heart Institute & Research Centre, H-2, Connaught Circus, New Delhi.

This Notification is effective for a period from 1-4-1985 to 31-12-1986.

[No. 6552 (F. No. 203/43/85-ITA. II)]

नई दिल्ली 3 जनवरी, 1986

(आयकर)

क्र. आ. 553:—इस कार्यालय की दिनांक 26-12-1980 की अधिसूचना सं. 3769 (फ. सं. 203/267/80 आ. क. नि. -II) के सिद्धान्त में, भंडारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) पेंसीस/एक/बो के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है:

- (i) यह कि अनुप्रयोग-जट वाजिबल एण्ड इक्विब्रिमीट्रिक सोसायटी आफ इंडिया, नई दिल्ली अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उचित द्वारा प्राप्तिराशि का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणा, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्रत्येक में प्रस्तुत करेगी जो उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जाए और उसे भूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने वार्षिक वार्षिक लेखों को तथा अपने परिसंपत्तिया, वित्तवर्षों दर्शाते हुए वृत्त-पत्र को एक एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी। तथा इन वृत्तवर्षों में से प्रत्येक की एक एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगी।
- (iv) यह कि उक्त संस्था केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तान माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगी। आवेदन प्रस्तुत करने में काला प्रकार की देरी होने पर प्राप्तिराशि पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"न्युप्रोगे आइलार्जिकल एण्ड इक्विब्रिमीट्रिक साइन्स सोसायटी आफ इंडिया (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान), नई दिल्ली।"

यह अधिसूचना 18-9-1983 से 31-12-1986 तक की अवधि के लिए प्रवर्तनी है।

[संख्या 6557 (फ. सं. 203/198/85 आ. क. नि. II)]

New Delhi, the 3rd January, 1986

INCOME-TAX

S.O. 553.—In continuation of this Office Notification No. 3760 (F. No. 203/267/80-ITA, II) dated 26-12-1980, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:—

- (i) That the Neuro Otological & Equilibrimetric Society of India, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific Research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension, Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"Neuro-Otological & Equilibrimetric Society of India (All India Institute of Medical Sciences) New Delhi."

This Notification is effective for a period from 18-9-1983 to 31-12-1986.

[No. 6557 (F. No. 203/198/85-ITA, II)]

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1985

गति पत्र

अयकर

क्र. आ. 554:—राजधारा की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि "रघुवेंद्र इण्डस्ट्रियल रिसर्च फाउंडेशन" किरा के नाम दिनांक 28-8-1981 से "पंजाब रिसर्च इन्स्टिट्यूट" में बदल दिया जाने के परिणामस्वरूप वित्त मंत्रालय राजस्व एवं बीमा विभाग की दिनांक 1-6-1981 की अधिसूचना सं. 3993 में इस संस्थान का नाम उठा कर जो "रघुवेंद्र इण्डस्ट्रियल रिसर्च फाउंडेशन" के स्थान पर "पंजाब रिसर्च इन्स्टिट्यूट" पढ़ा जाय।

[सं. 6537 (फ. सं. 203/87/81 आ. क. नि-II)]

(Central Board of Direct Taxes)

New Delhi, the 19th December, 1985

CORRIGENDUM

INCOME-TAX

S.O. 554.—It is hereby notified for general information that consequent upon the change in the name of "Raghendra Industrial Research Foundation", Delhi, to "Punjab Research Institute" with effect from 28-8-1981, the name of the Institution in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) Notification No. 3993 (F. No. 203/87/81-ITA, II) dated 1-6-1981 may be read as "Punjab Research Institute" for "Raghendra Industrial Research Foundation" from that date.

[No. 6537 (F. No. 203/87/81-ITA, II)]

आयकर

क्र. आ. 555:—सर्वसंधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विद्युत अनुसंधान एवं विकास संस्था (इलेक्ट्रिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन) को, वित्त मंत्रालय (राजस्व एवं बीमा विभाग) की दिनांक 26-8-1974 की अधिसूचना सं. 710 (फ. सं. 203/48/74 आ. क. नि-II) द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1)(ii) के तहत निर्धारित तथा अनुमोदित एतद्वारा 31-3-1984 तक प्रतिवर्षित किया जाता है।

[सं. 6538 (फ. सं. 203/30/81-आ. क. नि-II)]

वित्त एवं, अयकर सचिव

INCOME-TAX

S.O. 555.—It is notified for general information that the approval granted under section 35 (1)(ii) of the Income-tax Act 1961 to Electrical Research and Development Association vide Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) Notification No. 710 (F. No. 203/

48/74-ITA. II) dated 26-8-1974 is hereby restricted upto 31-3-1984.

[No. 6538 (F. No. 203/30/81-ITA. II)]
GIRISH DAVE, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1986

का० आ० 556:—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 193 के परन्तुक के खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 5651, दिनांक 4 दिसम्बर, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "जिन पर ब्याज किसी राष्ट्रीयकृत बैंक," शब्दों से आरम्भ होने वाले और "प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है" शब्द पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:—

"जिन पर ब्याज,—

- (क) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित स्टेट बैंक, और
- (ख) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 2 के खण्ड (ट) में यथापरिभाषित किसी समनुषंगी बैंक; या
- (ग) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, अर्थात् क्रमशः बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) और बैंककारी कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 2 में यथापरिभाषित तत्स्थानी नये बैंक, को संदेय है, उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।"

[सं० 6584/का०सं० 275/65/85-आई०टी०(बी)]

बी० नागराजन, उप-सचिव

New Delhi, the 29th January, 1986

S.O. 556.—In exercise of the powers conferred by clause (iii) of the proviso to section 193 of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. S.O. 5651, dated the 4th December, 1985, namely:—

In the said notification, for the portion beginning with the words "the interest on which is payable to any nationalised bank" and ending with the words "for the purposes of the said clause", the following shall be substituted, namely:—

"the interest on which is payable to—

- (a) the State Bank as defined in clause (g) of section 2 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955); or
- (b) any subsidiary bank as defined in clause (k) of Section 2 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959); or
- (c) any nationalised bank, that is to say, a corresponding new bank as defined in section 2 of

the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) respectively, for the purposes of the said clause".

[No. 6584/F. No. 275/65/85-IT(B)]
B. NAGARAJAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1986

आदेश

का. आ. 557:—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का सं. 673/115/85-सी. शु. VIII, तारीख 29-10-1985 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री बी. एम. पार्कर, 23, पहली मंजिल, सुलेमान बिल्डिंग, आगरा रोड, कुरला, बम्बई को केन्द्रीय कारागार, बम्बई में निरुद्ध कर लिया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य करने से निवारित किया जा सके, जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके, और

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[का. सं. 673/115/85-सी. शु.-VIII]

New Delhi, the 10th February, 1986

ORDERS

S.O. 557.—Whereas the Joint Secretary of the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/115/85-Cus. VIII, dated 29-10-1985 under the said sub-section directing that Shri Ahmed B. M. Parker, 23, 1st Floor, Suleman Building, Agra Road, Kurla, Bombay be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (a) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/115/85-Cus. VIII]

आदेश

का. आ. 558:—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का सं. 673/116/85-सी. शु. -VIII तारीख 5-11-1985 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री सुभाष शर्मा, काले, 115/3953, गीत गोविंद सोसाइटी, तिलकनगर, चैम्बर, बम्बई को केन्द्रीय कारागार, बम्बई में निरुद्ध कर लिया

जाय और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य करने से निवारित किया जा सके, जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके; और

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस प्रायुक्त, बम्बई के समक्ष हजरि हो।

[फा. सं. 673/116/85-सी. गु. -VIII]

S.O. 558.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), issued order F. No. 673/116/85-Cus. VIII, dated 5-11-1985 under the said sub-section directing that Shri Subhash R. Kale, 115/3953, Geeta Govind Society, Tilak Nagar, Chembur, Bombay be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/116/85-Cus.VIII]

का. आ. 559:—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अर्थात् विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अर्थात् आदेश फा. सं. 673/117/85-सी. गु. -VIII, तारीख 5-11-1985 यह निदेश देते हुए जारी किया कि श्री संजय रामचन्द्र काले, 115/3953, गीता गोविंद सोसायटी, तिलाक नगर, चैम्बूर, बम्बई को केन्द्रीय कारागार बम्बई में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य करने से निवारित किया जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके; और

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस प्रायुक्त, बम्बई के समक्ष हजरि हो।

[फा. सं. 673/117/85-सी. गु. -VIII]

S.O. 559.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/117/85-Cus. VIII, dated 5-11-1985 under the said sub-section directing that Shri Sanjay Ramachandra Kale, 115/3953, Geeta Govind Society, Tilak Nagar, Chembur, Bombay be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/117-35-Cus.VIII]

का. आ. 559:—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अर्थात् विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अर्थात् आदेश फा. सं. 673/119/85-सी. गु. -VIII, तारीख 29-10-1985 यह निदेश देते हुए जारी किया कि श्री श्री टी. एन. उन्निकृष्णन्, पुत्र श्री एम. के. नानु, द केपुराकल हाउस, चिप्पियराम, त्रिचुर डिस्ट्रिक्ट, केरला को केन्द्रीय कारागार बम्बई में निरुद्ध कर लिया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य करने से निवारित किया जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन में बाधक हो।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके; और

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस प्रायुक्त, त्रिवेन्द्रम के समक्ष हजरि हो।

[फा. सं. 673/119/85-सी. गु. VIII]

S.O. 560.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/119/85-Cus. VIII, dated 29-10-1985 under the said sub-section directing that Shri T. N. Unnikrishnan, son of C. K. Nannu, The Kepurackal House, P.O. Chiyaram, Trichur Dist., Kerala be detained and kept in custody in the Central Prison, Trivandrum with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Trivandrum within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/119/85-Cus. VIII]

का. आ. 560:—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अर्थात् विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अर्थात् आदेश फा. सं. 673/119/85-सी. गु. VIII, तारीख 29-10-1985 यह निदेश देते हुए जारी किया कि श्री जगदीश प्रसाद मोदीय, --हमकूरिया, प्रसाद लेन, कलकत्ता को प्रेमीडेंसी जेल, ब्रह्मपुर, कलकत्ता में निरुद्ध कर लिया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करों के साथ को लाने-ले-जाने और उसे छिपाने के प्रयासों तस्करी के माध्यम को रोकने और समाप्त करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके; और

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/133/85-सी. गु.-VIII]

S.O. 561.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/133/85-Cus. VIII, dated 29-10-1985 under the said sub-section directing that Shri Jagdish Prasad Soni, 8, Hanspukuria, 1st Lane, Calcutta be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Alipore, Calcutta with a view to preventing him from engaging in keeping smuggled goods and dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting and concealing smuggled goods.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Calcutta within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/133/85-Cus.VIII]

का. भा. 562.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/134/85-सी. गु., VIII तारीख 29-10-85 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री जीवन मल सोनी, निवासी सवर रोड, फोरबेसगंज, बिहार को प्रेसीडेंसी जेल, अलीपुर, कलकत्ता में निरुद्ध कर लिया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी के माल को लाने-ले-जाने और उसे छिपाने के अलावा तस्करी के माल को रखने का धंधा करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके; और

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/134/85-सी. गु.-VIII]

S.O. 562.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/134/85-Cus. VIII, dated 29-10-1985 under the said sub-section directing that Shri Jeewanmull Soni, Sardar Road, Forbesguni, Bihar be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Alipore, Calcutta with a view to preventing him from engaging in keeping smuggled goods otherwise than by engaging in transporting and concealing smuggled goods

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Inspector General of Police, West Bengal, Calcutta within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/134/85-Cus.VIII]

का. भा. 563.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/145/85-सी. गु., -VIII, तारीख 19 नवम्बर, 1985 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री कनिराम सिंघी, पुत्र स्वर्गीय तेजमल सिंघी, 7/2, बाबू लाल लेन (तीसरा तल), कलकत्ता को प्रेसीडेंसी जेल, अलीपुर, कलकत्ता में निरुद्ध कर लिया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी के माल को लाने-ले-जाने के अलावा तस्करी के माल को छिपाने, उसे रखने तथा उसका धंधा करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके; और

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/145/85-सी. गु.-VIII]

आर. के. निवारण, उप सचिव

S.O. 563.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/145/85-Cus. VIII, dated 19th November, 1985 under the said sub-section directing that Shri Kaniram Singhi, son of Late Tejmal Singh, 7/2, Babu Lal Lane (3rd Floor), Calcutta be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Alipore, Calcutta with a view to preventing him from engaging in concealing and keeping smuggled goods and dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting smuggled goods.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Calcutta within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/145/85-Cus.VIII]

R. K. TEWARI, Dy. Secy.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1986

सं. 35/86 सीमा-शुल्क

का. भा. 564.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य के पंचमहल जिले के हपोल को आण्डापर स्टेशन घोषित करना है

[फा. सं. 473/354/85 सीमा-शुल्क-VIII]

संजीव जोशी, धवर सचिव

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 15th February, 1986

No. 35/86-CUSTOMS

S.O. 564.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise Customs hereby declare Halol in Panchmahal District in the State of Gujarat to be a warehousing station.

[F. No. 473/354/85-CUS.VII]
SANDEEP JOSHI, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1986

का. प्रा. 565.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा II की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एम. के. बन्धोपाध्याय को रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रांची (बिहार) का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 19-12-85 से प्रारम्भ होकर 31-12-1988 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री एम. के. बन्धोपाध्याय अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एक. 2-72/85-प्रार. प्रार. बी.]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 15th January, 1986

S.O. 565.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri S. K. Bandyopadhyaya as the Chairman of the Ranchi Kshetriya Gramin Bank, Ranchi (Bihar) and specifies the period commencing on the 19-12-85 and ending with the 31-12-1988 as the periods for which the said Shri S. K. Bandyopadhyaya shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-72/85-RRB]

का. प्रा. 566.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री सुब्रत गुप्त को त्रिपुरा ग्रामीण बैंक अग्रतला का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 14-12-85 से प्रारम्भ होकर 31-12-1988 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री सुब्रत गुप्त अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एक. 2-37/82-प्रार. प्रार. बी]

S.O. 566.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Subrata Gupta as the Chairman of the Tripura Gramin Bank, Agartala and specifies the period commencing on the 14-12-85 and ending with 31-12-88 as the period for which the said Shri Subrata Gupta shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-37/82-RRB]

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1986

का. प्रा. 567.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा II की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एच. बी. मल्लया को प्रथम बैंक, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) का अध्यक्ष नियुक्त करती है और 29-10-1985 को प्रारम्भ होने वाली और 30-9-1988 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री एच. बी. मल्लया अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं. एक. 2-16/85-प्रार. प्रा. बी]

का. बा. मीरखाना, निदेशक

New Delhi, the 16th January, 1986

S.O. 567.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri H. V. Mallya, Chairman, Prathma Bank, Moradabad (UP) and specifies the period commencing on the 29-10-1985 and ending with 30-9-1988 as the period for which the said Shri H. V. Mallya shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-16/85-RRB]

C. W. MIRCHANDANI, Director

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1986

का. प्रा. 568.—केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 21 की उपधारा (2) के अनुसरण में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बोर्ड क सफाई पर उक्त निगम द्वारा 3, 4 तथा 5 मार्च, 1986 को जारी बिलों पर बिले और 3, 4 तथा 5 मार्च, 1999 को परिपक्व होने वाले बिलों पर देय ब्याज की दर एतद्वारा 9.75% (नौ दस प्रतिशत) वार्षिक निर्धारित करती है।

[फाइल सं. 6/7/85-प्राई. एक-1]

प्रवीण कुमार, उप-सचिव

New Delhi, the 5th February, 1986

S.O. 568.—In pursuance of Sub-section 2 of Section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948), the Central Government, on the recommendation of the Board of Directors of the Industrial Finance Corporation of India, hereby fixes 9.75 per cent (nine and three quarters) per annum as the rate of interest payable on the bonds to be issued by the said Corporation on 3rd, 4th and 5th March, 1986 and maturing on 3rd, 4th and 5th March, 1999.

[F. No. 6(7)/85 IFI]

PRADEEP KUMAR, Dy. Secy.

(बीमा प्रभाग)

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1986

का. प्रा. 569.—जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री प्रार. नारायणन को भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रबन्ध निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उनके 1 जुलाई 1989 को सेवा निवृत्त होने तक की अवधि के लिए निगम के सर्वस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फाइल सं. 108/5/85 ईश्वरस-4]

प्रार. एन. भट्टाचार्य, निदेशक

(Insurance Division)

New Delhi, the 30th January, 1986

S.O. 569.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Life Insurance Corporation Act, 1956,

(31 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri R. Narayanan as Member of the Board of Life Insurance Corporation of India from the date of assumption of charge as Managing Director of the Corporation and till his superannuation on 1st July, 1989.

[File No. 108/5/85-Ins. IV]

R. N. BHATTACHARYA, Director

आयकर आयुक्त कार्यालय

विषय

नागपुर, 11 नवम्बर, 1985

क्र.प्र. 570 :—विस्तृत वर्ष 1984-85 की अवधि के लिए उन निर्धारितियों के नाम एवं अन्य विवरण की सूची नीचे दी गई अनुसूची-I में, वे व्यक्ति तथा हिन्दु अधिभक्त कुटुम्ब हैं जिनका 2 लाख से अधिक आय पर निर्धारण किया गया हो, तथा अनुसूची-II में, वे फर्म, व्यक्तियों के समुदाय तथा कम्पनी जिनका 10 लाख से अधिक आय पर निर्धारण किया गया हो; (1) प्रस्थिति—व्यक्तियों के लिए “व्य”, हिन्दु अधिभक्त कुटुम्ब के लिए “हि”, पंजीकृत फर्म के लिए “फ”, व्यक्तियों के समुदाय के लिए “व्यसमु”, तथा कम्पनी के लिए “क” (2) निर्धारण वर्ष (3) विवरणों में दर्शायी आय (4) निर्धारित की गयी आय (5) देय कर (6) निर्धारितों द्वारा भरा किया गया कर बर्शाता है :—

अनुसूची-I

1. श्री शांतिलाल खेजपाल प्रो. मैसर्स विजय ट्रेडिंग कं. सीताबर्ही, नागपुर (1) व्य (2) 1983-84 (3) 2,58,890 (4) 2,59,700 (5) 1,49,210 (6) 1,49,210
2. श्री शांतिलाल खेजपाल प्रो. मैसर्स विजय ट्रेडिंग कंपनी, सीताबर्ही, नागपुर (1) व्य (2) 1984-85 (3) 2,24,250 (4) 2,68,250 (5) 1,58,147 (6) 92,312
3. श्री विजय के. खेजपाल प्रो. मैसर्स विजय ट्रेडिंग कंपनी, सीताबर्ही, नागपुर (1) व्य (2) 1984-85 (3) 2,24,250 (4) 2,24,250 (5) 1,28,447 (6) 51,962
4. श्री अजय के. खेजपाल प्रो. मैसर्स विजय ट्रेडिंग कंपनी, सीताबर्ही, नागपुर (1) व्य (2) 1984-85 (3) 2,24,550 (4) 2,24,250 (5) 1,28,785 (6) 91,962
5. श्री मो.जी. पटेल, चंपूर (1) व्य (2) 1984-85 (3) 1,96,878 (4) 2,08,030 (5) 1,17,325 (6) 1,17,325
6. श्री के.जे. जार्ज, बैरमजी टाउन, नागपुर (1) व्य (2) 1984-85 (3) 2,70,130 (4) 2,79,130 (5) 1,65,491 (6) 1,76,404
7. स्वर्गीय श्रीमती नाबोजीदेवी अग्रवाल द्वारा श्रीमती संदादेवी सराफ, नागपुर (1) व्य (2) 1974-75 (3) ——— (4) 9,02,018 (5) 12,90,553 (6)
8. श्री नारायणदास सराफ, तुमसर (1) व्य (2) 1982-83 (3) 45,540 (4) 4,55,859 (5) 3,73,528 (6) 14,315
9. श्री. भगवानबास पुरोहित, घाट रोड, नागपुर (1) व्य (2) 1982-83 (3) 6,08,800 (4) 6,44,370 (5) 4,03,206 (6) 3,79,616
10. श्री बनबारीलाल पुरोहित, घाट रोड, नागपुर (1) व्य (2) 1982-83 (3) 5,28,498 (4) 5,72,990 (5) 3,55,293 (6) 3,25,840
11. श्रीमती उमादेवी अग्रवाल, वर्धा (1) व्य (2) 1982-83 (3) 2,57,080 (4) 2,57,080 (5) 1,46,806 (6) 1,46,806
12. श्री शिशिरकुमार बजाज, वर्धा (1) व्य (2) 1982-83 (3) 5,49,600 (4) 5,50,670 (5) 3,40,562 (6) 3,40,562
13. श्री राहुलकुमार बजाज, वर्धा (1) हि (2) 1982-83 (3) 3,21,400 (4) 3,23,420 (5) 1,98,761 (6) 1,98,761
14. श्री मधु कुमार बजाज, वर्धा (1) हि (2) 1982-83 (3) 2,19,990 (4) 2,22,490 (5) 1,32,147 (6) 1,32,147
15. श्री मो.जी. धोले द्वारा मैसर्स प्रमोद एजेन्सीज, अकोला (1) व्य (2) 1982-83 (3) 2,03,330 (4) 2,15,070 (5) 1,19,066 (6) 1,11,318
16. श्री इकबाल हुसैन अंसारखली, नागपुर (1) व्य (2) 1982-83 (3) 2,01,332 (4) 2,16,730 (5) 1,20,162 (6) 1,09,999
17. श्री अंसारखली हुसैन, नागपुर (1) व्य (2) 1982-83 (3) 3,49,180 (4) 4,10,220 (5) 2,47,865 (6) 2,07,579
18. श्री अब्दुल्लाभाई हुसैनखली, नागपुर (1) व्य (2) 1982-83 (3) 3,37,841 (4) 4,18,570 (5) 2,53,376 (6) 2,00,094
19. श्री अब्दुल हुसैन अंसारखली, नागपुर (1) व्य (2) 1983-84 (3) 2,04,360 (4) 2,06,550 (5) 1,14,131 (6) 1,12,886
20. श्री अंसारखली हुसैन खली, नागपुर (1) व्य (2) 1983-84 (3) 5,46,290 (4) 5,56,280 (5) 3,48,362 (6) 3,38,368
21. श्री इकबाल हुसैन अंसारखली, नागपुर (1) व्य (2) 1983-84 (3) 2,55,960 (4) 2,64,660 (5) 1,52,572 (6) 1,46,740
22. श्री अब्दुल्लाभाई हुसैनखली, नागपुर (1) व्य (2) 1983-84 (3) 6,11,020 (4) 6,76,590 (5) 4,28,571 (6) 4,10,630
23. श्री ऐ. वाय. खरे, नागपुर (1) व्य (2) 1982-83 (3) 74,300 (4) 4,08,850 (5) 3,35,648 (6) 13,575
24. श्री. अब्दुलकरीम दिवान, नागपुर (1) व्य (2) 1981-82 (3) 20,080 (4) 2,21,240 (5) 2,18,923 (6) 2,200
25. श्री मुकेश पी. बुराडे, नागपुर (1) व्य (2) 1982-83 (3) 60,440 (4) 3,77,130 (5) 3,01,408 (6) 19,712
26. श्री सुरेन्द्रकुमार डी. शर्मा, नागपुर (1) व्य (2) 1982-83 (3) 72,400 (4) 2,05,390 (5) 2,81,419 (6) 12,262
27. श्री दीनानाथ के. शर्मा, नागपुर (1) व्य (2) 1982-83 (3) 92,310 (4) 2,27,610 (5) 2,07,524 (6) 18,513

28. श्री बेनीप्रसाद बी. कनौरिया, नागपुर
(1) हि (2) 1982-83 (3) 1,71,074 (4) 2,09,660
(5) 1,37,073 (6) 1,04,112
29. श्री अक्षय परबेज धनगराणी, नागपुर
(1) व्य (2) (1984-85) (3) 2,58,930 (4) 2,64,650
(5) 1,55,124 (6) 1,53,282
30. श्री सुरेश हरीभाऊ राहाटे, नागपुर
(1) व्य (2) 1978-80 (3) 25,820 (4) 25,63,340
(5) 11,08,188 (6) 1,36,605
31. श्रीमती सुमन रमेश राहाटे, नागपुर
(1) व्य (2) (1981-82) 31,210 (4) 8,29,553 (5)
8,14,686 (6) 2,478
32. श्रीमती इंदिराबाई हरिभाऊ राहाटे, नागपुर
(1) व्य (2) 1981-82 (3) 21,210 (4) 8,29,550 (5)
8,14,686 (6) 2,478
33. श्री सुरेश हरिभाऊ राहाटे, नागपुर
(1) व्य (2) 1981-82 (3) 47,940 (4) 11,36,960
(5) 10,35,365 (6) 13,086
34. श्री सोहनलाल कमललाल कालाश, गांधीबाग, नागपुर
(1) व्य (2) 1982-83 (3) 27,090 (4) 3,29,110
(5) 2,62,084 (6) 7,371
35. श्रीमती सुमन रमेश राहाटे, नागपुर
(1) व्य (2) 1982-83 (3) (—) 2,140 (4)
2,68,260 (5) 2,14,66 (6) —
36. श्रीमती इंदिराबाई हरिभाऊ राहाटे, नागपुर
(1) व्य (2) 1982-83 (3) (—) 27,140
(4) 2,63,260 (5) 2,10,061 (6) —
37. श्री सुरेश हरीभाऊ राहाटे, नागपुर
(1) व्य (2) 1980-81 (3) 42,620 (4) 6,82,460
(5) 6,36,733 (6) 11,698
38. श्री सुरेश हरीभाऊ राहाटे, नागपुर
(1) व्य (2) 1982-83 (3) (—) 1,720 (4)
3,44,790 (5) 2,64,369 (6) 2,600
39. श्री महादेव बापू बाकेकार, नागपुर
(1) व्य (2) 1983-84 (3) — (4) 2,17,030 (5)
1,71,095 (6) —
40. श्री चांदमल जी. अग्रवाल, गोविंदा
(1) हि (2) 1982-83 (3) 35,510 (4) 4,33,950
(5) 3,91,166 (6) 7,595
41. मेसर्स रवी ग्रार्स स्टोर, प्रो. श्रीमती कबीला एस. जेतवानी,
नागपुर
(1) व्य (2) 1980-81 (3) 14,980 (4) 9,86,900
(5) 10,35,264 (6) —
42. मे. रवी ग्रार्स स्टोर प्रो. श्रीमती कबीला एस. जेतवानी,
नागपुर
(1) व्य (2) 1982-83 (3) 22,940 (4) 18,63,580
(5) 19,39,389 (6) —
43. मेसर्स फिरो अलीदज काप्रोवेशन, श्रीराम भवन, तुमसर
(1) क (2) 1981-82 (3) 6,10,62,903 (4) 6,16,49,669
(5) 3,84,67,718 (6) 3,61,29,277
44. मेसर्स फिरो अलीदज काप्रोवेशन, श्रीराम भवन, तुमसर
(1) क (2) 1982-83 (3) 3,63,09,270 (4) 3,89,49,240
(5) 2,19,57,633 (6) 2,04,69,353
45. महाराष्ट्र स्टेट मार्किंग काप्रोवेशन लि., नागपुर
(1) क (2) 1982-83 (3) — (4) 32,27,500 (5)
22,47,633 (6) —
46. मेसर्स पुरोहित ग्रन्थ कंपनी, घाट रोड, नागपुर
(1) पफ (2) 1982-83 (3) 14,97,530 (4) 15,89,060
(5) 4,04,110 (6) 3,80,460
47. एस. जी. ग्लाम बक्स प्रा. लि. चंद्रपुर
(1) क (2) 1982-83 (3) 11,70,970 (5) 18,99,110
(5) 12,90,217 (6) 17,46,341
48. बजाज स्टिल इन्स्ट्रुज प्रा. लि. नागपुर
(1) क (2) 1982-83 (3) 17,39,020 (4) 21,33,170
(5) 13,92,749 (6) 10,69,497
49. जायका आटोमोबाईल्स प्रा. लि., नागपुर
(1) क (2) 1982-83 (3) 63,870 (4) 10,11,400
(5) 8,57,907 (6) 42,554
50. बलारपुर इंडस्ट्रीज लि., बलारपुर
(1) क (2) 1982-83 (3) 9,64,21,440 (4) 10,15,48,190
(5) 5,72,47,792 (6) 5,55,99,781
51. वि सेंट्रल प्राविन्सेस मंगनीज ओर के., नागपुर
(1) क (2) 1982-83 (3) (—) 25,67,590 (4) 17,67,770
(5) 14,33,264 (6) —
52. मंगनीज ओर इंडिया लि., नागपुर
(1) क (2) 1982-83 (3) 76,58,863 (4) 92,60,253
(5) 52,19,878 (6) 43,02,999
53. मेसर्स शारदा इंडस्ट्रीज अंश इजिनीयरिंग बक्स, नागपुर
(1) क (2) 1982-83 (3) 13,96,040 (4) 23,96,500
(5) 17,52,350 (6) 8,58,543
54. मेसर्स अब्दुल हुसैन एम. अलाबक्सजी, नागपुर
(1) पफ (2) 1982-83 (3) 6,44,000 (4) 12,43,820
(5) 2,05,724 (6) 1,66,230
55. मेसर्स अब्दुल हुसैन एम. अलाबक्सजी, नागपुर
(1) पफ (2) 1983-84 (3) 12,91,626 (5) 14,40,360
(5) 3,67,856 (6) 3,25,596
56. मेसर्स जितेंद्र लिंकर काप्रोवेशन, नागपुर
(1) पफ (2) 1982-83 (3) 11,70,550 (4) 22,92,570
(5) 8,71,016 (6) 1,09,640
57. मेसर्स खरे ग्रन्थ हारकुर्से 11, शरिलगर, नागपुर
(1) पफ (2) 1982-83 (3) 7,34,950 (4) 18,19,590
(5) 5,59,716 (6) 1,78,627
58. मेसर्स भारती मीनेरल्स, नागपुर
(1) पफ (2) 1982-83 (3) 11,27,230 (4) 12,63,680
(5) 5,26,542 (6) 2,82,183
59. मेसर्स सुरेश हरिभाऊ राहाटे, नागपुर
(1) पफ (2) 1981-82 (3) 69,620 (4) 33,53,280
(5) 13,11,694 (6) 5,990
60. मे. सुरेश हरिभाऊ राहाटे, नागपुर
(1) पफ (2) 1982-83 (3) (—) 81,430 (4) 10,48,620
(5) 3,55,286 (6) —

अनुसूची—II

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX,
VIDARBHA

Nagpur, the 11th November, 1985

S.O. 570.—Following is the list of the names and other particulars of the assessee namely Individuals and Firms, AOP and Companies assessed on an income over Rs. 2 lakhs in Schedule-I and Firms, AOP and Companies assessed on an income over Rs. 10 lakhs in Schedule-II, during the financial year 1984-85 (i) Indicates Status-'I' for Individuals 'H' for Hindu Undivided Families, 'RF' for Registered Firms, 'AOP' for Association of Persons and 'Co.' for Companies (ii) for assessment year, (iii) for income returned, (iv) for income assessed, (v) for taxpayable & (vi) for tax paid by the assessee :—

SCHEDULE—I

1. Shri Shantilal Khetrapal P/o M/s. Vijay Trading Co., Sitabuldi, Nagpur. (i) I (ii) 1983-84 (iii) 2,58,890 (iv) 2,59,700 (v) 1,49,210 (vi) 1,49,210.
2. Shri Shantilal Khetrapal P/o. M/s. Vijay Trading Co., Sitabuldi, Nag. (i) I (ii) 1984-85 (iii) 2,24,250 (iv) 2,68,250 (v) 1,58,147 (vi) 92,312.
3. Shri Vijai K. Khetrapal P/o. M/s. Vijay Trading Co., Sitabuldi, Nagpur. (i) I (ii) 1984-85 (iii) 2,24,250 (iv) 2,24,250 (v) 1,28,447 (vi) 51,962.
4. Shri Ajai K. Khetrapal P/o. M/s. Vijay Trading Co., Sitabuldi, Nagpur. (i) I (ii) 1984-85 (iii) 2,24,550 (iv) 2,24,250 (v) 1,28,785 (vi) 91,962.
5. Shri C. G. Patel, Chandrapur. (i) I (ii) 1984-85 (iii) 1,96,878 (iv) 2,08,030 (v) 1,17,325 (vi) 1,17,325.
6. Shri K. J. George, Byramji Town, Nagpur. (i) I (ii) 1984-85 (iii) 2,70,130 (iv) 2,79,130 (v) 1,65,491 (vi) 1,76,404.
7. Late Smt. Naojidevi Agrawal L/H. Smt. Chandadevi Saraf, Nagpur. (i) I (ii) 1974-75 (iii) NIL (iv) 9,02,018 (v) 12,90,553 (vi) NIL.
8. Shri Narayandas Saraf, Tumsar, (i) I (ii) 1982-83 (iii) 45,540 (iv) 4,55,859 (v) 3,73,528 (vi) 14,315.
9. Shri Bhagwandas Purohit, Ghat Road, Nagpur. (i) I (ii) 1982-83 (iii) 6,08,800 (iv) 6,44,370 (v) 4,02,206 (vi) 3,79,616.
10. Shri Banwarilal Purohit, Ghat Road, Nagpur. (i) I (ii) 1982-83 (iii) 5,28,498 (iv) 5,72,990 (v) 3,55,293 (vi) 3,25,840.
11. Smt. Umadevi Agarwal, Wardha, (i) I (ii) 1982-83 (iii) 2,57,080 (iv) 2,57,080 (v) 1,46,806 (vi) 1,46,806.
12. Shri Shishirkumar Bajaj, Wardha, (i) I (ii) 1982-83 (iii) 5,49,600 (iv) 5,50,670 (v) 3,40,562 (vi) 3,40,562.
13. Shri Rahul Kumar Bajaj, Wardha, (i) H (ii) 1982-83 (iii) 3,21,400 (iv) 3,23,420 (v) 1,98,761 (vi) 1,98,761.
14. Shri Madhukumar Bajaj, Wardha, (i) H (ii) 1982-83 (iii) 2,19,990 (iv) 2,22,490 (v) 1,32,147 (vi) 1,32,147.
15. Shri B. D. Dhotre, C/o. M/s. Pramod Agencies, Akola, (i) I (ii) 82-83 (iii) 2,03,330 (vi) 2,15,070 (v) 1,19,066 (vi) 1,11,318.
16. Shri Iqbal Hussain Asgharali, Nagpur. (i) I (ii) 82-83 (iii) 2,01,332 (iv) 2,16,730 (v) 1,20,162 (vi) 1,09,999.
17. Shri Asgharali Husanali, Nagpur. (i) I (ii) 82-83 (iii) 3,49,180 (iv) 4,10,220 (v) 2,47,865 (vi) 2,07,579.
18. Shri Abdullahhai Hasanali, Nagpur. (i) I (ii) 82-83 (iii) 3,37,841 (iv) 4,18,570 (v) 2,53,376 (vi) 2,00,094.
19. Shri Abdulhussain Asgharali, Nagpur. (i) I (ii) 83-84 (iii) 2,04,360 (iv) 2,06,550 (v) 1,14,131 (vi) 1,12,686.
20. Shri Asgharali Hasanali, Nagpur. (i) I (ii) 83-84 (iii) 5,46,290 (iv) 5,56,280 (v) 3,48,362 (vi) 3,38,368.
21. Shri Iqbal Hussain Asgharali, Nagpur. (i) I (ii) 83-84 (iii) 2,55,960 (iv) 2,64,660 (v) 1,52,572 (vi) 1,46,740.
22. Shri Abdullahhai Hasanali, Nagpur. (i) I (ii) 83-84 (iii) 6,11,020 (iv) 6,76,590 (v) 4,28,571 (vi) 4,10,630.
23. Shri A. Y. Khare, Nagpur. (i) I (ii) 82-83 (iii) 74,300 (iv) 4,08,850 (v) 3,35,648 (vi) 13,575.
24. Shri Abu Kaim Diwan, Nagpur. (i) I (ii) 81-82 (iii) 20,080 (iv) 2,21,240 (v) 2,18,923 (vi) 2,200.
25. Shri Mukesh P. Burade, Nagpur. (i) I (ii) 82-83 (iii) 60,440 (iv) 3,77,130 (v) 3,01,408 (vi) 19,712.
26. Shri Surendra Kumar D. Sharma, Nagpur. (i) I (ii) 82-83 (iii) 72,400 (iv) 2,05,390 (v) 2,81,419 (vi) 12,262.
27. Shri Dinanath K. Sharma, Nagpur. (i) I (ii) 82-83 (iii) 92,310 (iv) 2,27,610 (v) 2,07,524 (vi) 18,513.
28. Shri Beniprasad V. Kanoria, Nagpur. (i) H (ii) 82-83 (iii) 1,71,074 (iv) 2,09,660 (v) 1,57,073 (vi) 1,04,112.
29. Shri Akhtar Prvez Asgharali, Nagpur. (i) I (ii) 84-85 (iii) 2,58,930 (iv) 2,64,650 (v) 1,55,124 (vi) 1,53,282.
30. Shri Suresh Haribhau Rahate, Nagpur. (i) I (ii) 79-80 (iii) 25,820 (iv) 25,63,340 (v) 11,08,183 (vi) 1,36,605.
31. Smt. Suman Ramesh Rahate, Nagpur. (i) I (ii) 81-82 (iii) 21,210 (iv) 8,29,553 (v) 8,14,686 (vi) 2,478.
32. Smt. Indirabai Haribhau Rahate, Nagpur. (i) I (ii) 81-82 (iii) 21,210 (iv) 8,29,550 (v) 8,14,686 (vi) 2,478.
33. Shri Suresh Haribhau Rahate, Nagpur. (i) I (ii) 81-82 (iii) 47,940 (iv) 11,36,960 (v) 10,35,365 (vi) 13,086.
34. Shri Sohanlal Chimanlal Kalara, Gandhibag, Nagpur. (i) I (ii) 82-83 (iii) 27,090 (iv) 3,29,110 (v) 2,62,084 (vi) 7,371.
35. Smt. Suman Ramesh Rahate, Nagpur. (i) I (ii) 82-83 (iii) — (iv) 21,140 (iv) 2,68,260 (v) 2,14,656 (vi) —.
36. Smt. Indirabai Haribhau Rahate, Nagpur. (i) I (ii) 82-83 (iii) — (iv) 27,140 (iv) 2,63,260 (v) 2,10,061 (vi) —.
37. Shri Suresh Haribhau Rahate, Nagpur. (i) I (ii) 80-81 (iii) 42,620 (iv) 6,82,460 (v) 6,36,733 (vi) 11,698.
38. Shri Suresh Haribhau Rahate, Nagpur. (i) I (ii) 82-83 (iii) — (iv) 1,720 (iv) 3,44,790 (v) 2,64,369 (vi) 2,600.
39. Shri Mahadeo Y. Wakekar, Nagpur. (i) I (ii) 83-84 (iii) — (iv) 2,17,030 (v) 1,71,095 (vi) —.
40. Shri Chandmal G. Agrawal, Gondia. (i) H (ii) 82-83 (iii) 35,510 (iv) 4,53,950 (v) 3,91,166 (vi) 7,595.
41. M/s. Ravi Oil Store, Prop.—Smt. Kavita S. Jethwani, Nagpur. (i) I (ii) 80-81 (iii) 14,980 (iv) 9,86,900 (v) 10,35,264 (vi) —.
42. M/s. Ravi Oil Store, Prop.—Smt. Kavita S. Jethwani, Nagpur. (i) I (ii) 82-83 (iii) 22,940 (iv) 18,63,580 (v) 19,39,389 (vi) —.

SCHEDULE—II

43. M/s. Ferro Alloys Corporation, Shreeram Bhavan, Tumsar. (i) Co. (ii) 81-82 (iii) 6,10,62,903 (iv) 6,16,49,669 (v) 3,64,67,718 (vi) 3,61,29,277.
44. M/s. Ferro Alloys Corporation, Shreeram Bhavan, Tumsar, (i) Co. (ii) 82-83 (iii) 3,63,09,270 (iv) 3,89,49,240 (v) 2,19,57,633 (vi) 2,04,69,353.

45. Maharashtra State Mining Corporation Ltd., Nagpur.
(i) Co (ii) 82-83 (iii) NIL (iv) 32,27,500 (v)
22,47,633 (vi) NIL.
46. M/s. Purohit & Co., Ghat Road, Nagpur. (i) RF
(ii) 82-83 (iii) 14,97,530 (iv) 15,89,060 (v)
4,04,110 (vi) 3,80,460.
47. S. G. Glass Works Pvt. Ltd., Chandrapur. (i) Co.
(ii) 82-83 (iii) 11,70,970 (iv) 18,99,110 (v)
12,90,217 (vi) 7,46,341.
48. Bajaj Steel Industries Pvt. Ltd., Nagpur. (i) Co.
(ii) 82-83 (iii) 17,39,020 (iv) 21,33,170 (v)
13,92,749 (vi) 10,69,497.
49. Jaika Automobiles Pvt. Ltd., Nagpur. (i) Co. (ii)
82-83 (iii) 63,870 (iv) 10,11,400 (v) 8,57,907 (vi)
42,554.
50. Ballarpur Industries Ltd., Ballarpur. (i) Co. (ii)
82-83 (iii) 9,64,21,440 (iv) 10,15,48,190 (v)
5,72,47,792 (vi) 5,55,99,781.
51. The Central Provinces Manganese Ore Co., Nagpur.
(i) Co. (ii) 82-83 (iii) (—) 25,67,590 (iv)
17,67,770 (v) 14,33,264 (vi) NIL.
52. Manganese Ore India Ltd., Nagpur. (i) Co. (ii)
82-83 (iii) 76,58,863 (iv) 92,60,253 (v) 52,19,878
(vi) 43,02,999.
53. M/s. Sharada Industries & Engg. Works, Nagpur.
(i) Co. (ii) 82-83 (iii) 13,96,040 (iv) 23,96,500
(v) 17,52,350 (vi) 8,58,543.
54. M/s. Abdul Husan M. Alatuxji, Nagpur. (i) RF
(ii) 82-83 (iii) 6,44,000 (iv) 12,43,820 (v) 2,05,724
(vi) 1,66,230.
55. M/s. Abdulhussain M. Alabuxji, Nagpur. (i) RF
(ii) 83-84 (iii) 12,91,626 (iv) 14,40,360 (v)
3,67,856 (vi) 3,25,596.
56. M/s. Vidarbha Liquor Corp., Nagpur. (i) RF (ii)
82-83 (iii) 11,70,550 (iv) 22,92,570 (v) 8,71,016
(vi) 1,09,640.
57. M/s. Khare & Tarkunde, 11, Shankar Nagar, Nagpur.
(i) RF (ii) 82-83 (iii) 7,34,950 (iv) 18,19,590
(v) 5,59,716 (vi) 1,78,627.
58. M/s. Artee Minerals, Nagpur. (i) RF (ii) 82-83
(iii) 11,27,230 (iv) 12,63,680 (v) 5,26,542 (vi)
2,82,183.
59. M/s. Suresh Haribhau Rahate, Nagpur. (i) RF (ii)
81-82 (iii) 69,620 (iv) 33,53,280 (v) 13,11,694
(vi) 5,990.
60. M/s. Suresh Haribhau Rahate, Nagpur. (i) RF (ii)
82-83 (iii) (—) 81,430 (iv) 10,48,620 (v) 3,55,286
(vi) (—).

का.प्र. 571:—निम्न सूची में वर्णित व्यक्तियों पर, जिसीय वर्ष 1984-85 के दौरान कम से कम रु. 5,000/- में अधिक की शास्ति लगायी गयी थी।

(i) प्रस्थिति—व्यक्तियों के लिए "व्य", हिन्दू अधिभक्षण कुटुम्ब के लिए "हि", पंजीकृत फर्म के लिए "फ", अप्रपंजीकृत फर्म के लिए "अफ", कम्पनी के लिए "क" सहकारी समिति के लिए "समिति" तथा व्यक्तियों के समुदाय के लिए "व्यसम" (ii) निर्धारण वर्ष (iii) शास्ति की राशि (4) किस धारा के अधीन शास्ति लगायी गयी, इंगित करता है :—

1. श्री प्रार.बी. बंसीलाल अखिरबंद प्रा.लि., नागपुर
(i) क (ii) 1970-71 (iii) 7,850 (iv) 271(1)(ए)
2. श्री प्रार.बी. बंसीलाल अखिरबंद प्रा.लि., नागपुर
(i) क (ii) 1970-71 (iii) 9,500 (iv) 271(1)(सी)
3. मेसर्स अग्रवाल केमीकल्स ट्रेडर्स, रेजिम ओली, नागपुर
(i) पफ (ii) 1982-83 (iii) 6,000 (iv) 273(1)(बी)

4. मेसर्स पैरामाउंट इंडस्ट्रीज, पिलकनगर, नागपुर
(i) पफ (ii) 1982-83 (iii) 5,490 (iv) 271(1)(ए)
5. मेसर्स के.सी. अग्रवाल अन्ड कंपनी, मीनाबर्डी, नागपुर
(i) पफ (ii) 1977-78 (iii) 9,640 (iv) 271(1)(ए)
6. मेसर्स के.सी. अग्रवाल एण्ड कंपनी, मीनाबर्डी, नागपुर
(i) पफ (ii) 1978-79 (iii) 7,257 (iv) 271(1)(ए)
7. मेसर्स के.सी. अग्रवाल एण्ड कंपनी, मीनाबर्डी, नागपुर
(i) पफ (ii) 1979-80 (iii) 6,570 (iv) 271(1)(ए)
8. मेसर्स ए.के., मीनाबर्डी, नागपुर
(i) पफ (ii) 1981-82 (iii) 5,010 (iv) 271(1)(ए)
9. श्री पी. व्ही. रामनाथन भागीदार मेसर्स सेंट्रल साईटिफिक व गदर, नागपुर
(i) व्य (ii) 1980-81 (iii) 8,000 (iv) 271(1)(सी)
10. मेसर्स नागपुर गैस एण्ड इंडस्ट्रीज अफ्फाएन्सेस एण्ड सर्विस, सबर, नागपुर
(i) पफ (ii) 1982-83 (iii) 8,650 (iv) 273(2)(बी)
11. मेसर्स साविक एण्ड कंपनी, सबर, नागपुर
(i) पफ (ii) 1982-83 (iii) 17,100 (iv) 271(1)(ए)
12. श्री एम.के. धोटे, वर्धा रोड, मीनाबर्डी, नागपुर
(i) पफ (ii) 1980-81 (iii) 15,150 (iv) 271(1)(सी)
13. सेंट्रल इलियम असीमिगेशन, रामनाथपेट, नागपुर
(i) पफ (ii) 1979-80 (iii) 5,170 (iv) 271(1)(ए)
14. मेसर्स डी. एम. जैन, इन्टरप्राइजेस, चंदपुर
(i) पफ (ii) 1982-83 (iii) 9,030 (iv) 271(1)(न)
15. मेसर्स डी. एम. जैन, इन्टरप्राइजेस, चंदपुर
(i) पफ (ii) 1983-84 (iii) 6,190 (iv) 271(1)(ए)
16. श्री जी.ए. बुरडकार, चंदपुर
(i) व्य (ii) 1980-81 (iii) 7,000 (iv) 140 ए(3)
17. मेसर्स चांद ट्रेडिंग कंपनी, रामनाथपेट, नागपुर
(i) पफ (ii) 1980-81 (iii) 5,365 (iv) 273(1)
18. महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि., नागपुर
(i) क (ii) 1979-80 (iii) 79,710 (iv) 271(1)(ए)
19. श्रीमती नारादेवी महेंद्रासिंग सैनी, अमरावती
(i) व्य (ii) 1977-78 (iii) 6,929 (iv) 271(1)(ए)
20. मेसर्स क्रिमेंट कर्मिषनल कारपोरेशन, अकोला
(i) पफ (ii) 1980-81 (iii) 19,469 (iv) 271(1)(ए)
21. मेसर्स कृषि वैभव एजन्सीज, अकोला
(i) पफ (ii) 1980-81 (iii) 9,050 (iv) 271(1)(सी)
22. मेसर्स राजाटे ब्रदर्स, मेहकर, जि. बुलडाणा
(i) पफ (ii) 1980-81 (iii) 7,950 (iv) 271(1)(ए)
23. श्री दिनानाथ के. शर्मा, नागपुर
(i) व्य (ii) 1980-81 (iii) 7,000 (iv) 273(2)(सी)
24. श्री दिनानाथ के. शर्मा, नागपुर
(i) व्य (ii) 1980-81 (iii) 22,555 (iv) 140 ए(3)
25. श्री दिनानाथ के. शर्मा, नागपुर
(i) व्य (ii) 1980-81 (iii) 5,701 (iv) 271(1)(सी)
26. मेसर्स अग्रवाल बाम्बू डेपोट, गोविंदा
(i) पफ (ii) 1980-81 (iii) 6,450 (iv) 271(ए)(1)
27. मेसर्स अग्रवाल बाम्बू डिपो, खोबिया
(i) पफ (ii) 1981-82 (iii) 5,706 (iv) 271(1)(सी)

28. मेमर्स ओंकारलाल बट्टीप्रसाद अग्रवाल, गोदिया
(i) पफ (ii) 1975-76 (iii) 6,080 (iv) 271 (1) (सी)
29. मेमर्स ओंकारलाल बट्टीप्रसाद अग्रवाल, गोदिया
(i) पफ (ii) 1976-77 (iii) 16,587 (iv) 271 (1) (सी)
30. मेमर्स ओंकारलाल बट्टीप्रसाद अग्रवाल, गोदिया
(i) पफ (ii) 1979-80 (iii) 6,949 (iv) 271 (1) (सी)
31. मेमर्स ओंकारलाल बट्टीप्रसाद अग्रवाल, गोदिया
(i) पफ (ii) 1980-81 (iii) 18,028 (iv) 271 (1) (सी)
32. मेमर्स ओंकारलाल बट्टीप्रसाद अग्रवाल, गोदिया
(i) पफ (ii) 1981-82 (iii) 17,442 (iv) 271 (1) (सी)
33. श्री राधेप्रियाम गुलाबचन्द अग्रवाल, गोदिया
(i) व्य (ii) 1981-82 (iii) 5,740 (iv) 271 (1) (सी)
34. श्री हेमराज हिरालाल वर्मा द्वारा मूनलाईट, नागपुर
(i) व्य (ii) 1978-79 (iii) 6,183 (iv) 271 (1) (सी)
35. श्री हेमराज हिरालाल वर्मा द्वारा मूनलाईट, नागपुर
(i) व्य (ii) 1979-80 (iii) 9,176 (iv) 271 (1) (सी)
36. श्री हेमराज हिरालाल वर्मा, द्वारा मूनलाईट, नागपुर
(i) व्य (ii) 1980-81 (iii) 11,918 (iv) 271 (1) (सी)
37. श्री हेमराज हिरालाल वर्मा, द्वारा मूनलाईट, नागपुर
(i) व्य (ii) 1981-83 (iii) 13,960 (iv) 271 (1) (सी)
38. श्री हेमराज हिरालाल वर्मा, द्वारा मूनलाईट, नागपुर
(i) व्य (ii) 1982-83 (iii) 17,436 (iv) 271 (1) (सी)
39. श्री बामुदेव हिरालाल वर्मा, द्वारा मूनलाईट, नागपुर
(i) व्य (ii) 1975-76 (iii) 7,440 (iv) 271 (1) (सी)
40. श्री बामुदेव हिरालाल वर्मा द्वारा मूनलाईट, नागपुर
(i) व्य (ii) 1977-78 (iii) 5,684 (iv) 271 (1) (सी)
41. श्री बामुदेव हिरालाल वर्मा, द्वारा मूनलाईट, नागपुर
(i) व्य (ii) 1978-79 (iii) 11,697 (iv) 271 (1) (सी)
42. श्री बामुदेव हिरालाल वर्मा, द्वारा मूनलाईट, नागपुर
(i) व्य (ii) 1979-80 (iii) 11,089 (iv) 271 (1) (सी)
43. श्री बामुदेव हिरालाल वर्मा, द्वारा मूनलाईट, नागपुर
(i) व्य (ii) 1980-81 (iii) 8,656 (iv) 271 (1) (सी)
44. श्री बामुदेव हिरालाल वर्मा, द्वारा मूनलाईट, नागपुर
(i) व्य (ii) 1981-82 (iii) 9,616 (iv) 271 (1) (सी)
45. श्री बामुदेव हिरालाल वर्मा, द्वारा मूनलाईट, नागपुर
(i) व्य (ii) 1982-83 (iii) 10,937 (iv) 271 (1) (सी)
46. मेमर्स नेशनल आटोमोबाईल्स, गड्डुडी गोवाम, नागपुर
(i) पफ (ii) 1979-80 (iii) 21,022 (iv) 271 (1) (सी)
47. मेमर्स नेशनल आटोमोबाईल्स, गड्डुडी गोवाम, नागपुर
(i) पफ (ii) 1980-81 (iii) 25,165 (iv) 271 (1) (सी)
48. मेमर्स नेशनल आटोमोबाईल्स, गड्डुडी गोवाम, नागपुर
(i) पफ (ii) 1981-82 (iii) 21,626 (iv) 271 (1) (सी)
49. मेमर्स नेशनल आटोमोबाईल्स, गड्डुडी गोवाम, नागपुर
(i) पफ (ii) 1979-80 (iii) 12,942 (iv) 271 (1) (सी)
50. मेमर्स नेशनल आटोमोबाईल्स, गड्डुडी गोवाम, नागपुर
(i) पफ (ii) 1980-81 (iii) 8,069 (iv) 271 (1) (सी)
51. मेमर्स प्रेमसागर चावला एंड कं., नागपुर
(i) पफ (ii) 1979-80 (iii) 6,477 (iv) 271 (1) (ए)
52. मेमर्स प्रेमसागर चावला एंड कं., नागपुर
(i) पफ (ii) 1979-80 (iii) 9,408 (iv) 271 (1) (सी)
53. मेमर्स प्रेमसागर चावला एंड कं., नागपुर
(i) पफ (ii) 1980-81 (iii) 8,996 (iv) 271 (1) (सी)
54. श्री सत्यवान भाटिया, नागपुर
(i) व्य (ii) 1975-76 (iii) 10,000 (iv) 271 (1) (सी)
55. रामचन्द्र गणपतराय समर्थ बै/उ रामदास एंड रमेश समर्थ, नागपुर
(i) व्य (ii) 1981-82 (iii) 6,923 (iv) 271 (1) (सी)
56. दावाभाई बोशीभाई (हीरानीभाई) झाल चेरिटेबल ट्रस्ट, कामठी
(i) समिति (ii) 1976-77 (iii) 33,313 (iv) 271 (1) (ए)
57. दावाभाई बोशीभाई (हीरानीभाई) झाल चेरिटेबल ट्रस्ट, कामठी
(i) समिति (ii) 1977-78 (iii) 19,769 (iv) 271 (1) (ए)
58. दावाभाई बोशीभाई (हीरानीभाई) झाल चेरिटेबल ट्रस्ट, कामठी
(i) समिति (i) 1980-81 (ii) 7,894 (iv) 271 (1) (ए)
59. श्री शरदचन्द्र मोतीराम बालपांडे, गणेशनगर, नागपुर
(i) व्य (ii) 1980-81 (iii) 85,544 (iv) 271 (1) (ए)
60. श्री शरदचन्द्र मोतीराम बालपांडे, गणेशनगर, नागपुर
(i) व्य (ii) 1980-81 (iii) 53,188 (iv) 271 (1) (बी)
61. श्री शरदचन्द्र मोतीराम बालपांडे, गणेशनगर, नागपुर
(i) व्य (ii) 1980-81 (iii) 40,100 (iv) 273 (2) (बी)
62. श्री शरदचन्द्र मोतीराम बालपांडे, गणेशनगर, नागपुर
(i) व्य (ii) 1980-81 (iii) 3,14,000 (iv) 271 (1) (सी)
63. श्री मंगलचंद आर. बागडी, नागपुर
(i) व्य (ii) 1981-82 (iii) 11,120 (iv) 140 ए (3)
64. श्री लक्ष्मणसिंह वर्मा, नागपुर
(i) व्य (ii) 1982-83 (iii) 10,530 (iv) 271 (1) (ए)
65. श्री लक्ष्मण सिंह वर्मा, नागपुर
(i) व्य (ii) 1982-83 (iii) 39,480 (iv) 273 (1) (बी)
66. मेमर्स स्वस्तिक कन्स्ट्रक्शन, नागपुर
(i) पफ (ii) 1982-83 (iii) 7,650 (iv) 271 (1) (ए)
67. मेमर्स पी.बी. मासुरकर, नागपुर
(i) पफ (ii) 1981-82 (iii) 5,421 (iv) 271 (1) (ए)
68. श्री पी.बी. मासुरकर, नागपुर
(i) व्य (ii) 1981-82 (iii) 5,060 (iv) 273 (1) (बी)
69. श्री मंगलचंद आर. बागडी, नागपुर
(i) व्य (ii) 1982-83 (iii) 16,674 (iv) 271 (1) (ए)
70. श्री मंगलचंद आर. बागडी, नागपुर
(i) व्य (ii) 1982-83 (iii) 28,552 (iv) 273 (1) (बी)
71. श्री मंगलचंद आर. बागडी, नागपुर
(i) व्य (ii) 1981-82 (iii) 22,240 (iv) 271 (1) (ए)
72. श्री मंगलचंद आर. बागडी, नागपुर
(i) व्य (ii) 1981-82 (iii) 42,010 (iv) 273 (1) (बी)
73. श्री मंगलचंद आर. बागडी, नागपुर
(i) व्य (ii) 1980-81 (iii) 7,310 (iv) 271 (1) (सी)
74. मेमर्स रघुबीरदास श्यामसुंदर, गोदिया
(i) पफ (ii) 1980-81 (iii) 10,170 (iv) 271 (1) (सी)
75. मेमर्स रघुबीरदास श्यामसुंदर, गोदिया
(i) पफ (ii) 1981-82 (iii) 10,090 (iv) 271 (1) (सी)

76. मेसर्स रघुवीरव्यास प्र्यामसुन्दर, गोदिया
(i) पफ (ii) 1982-83 (iii) 16,500 (iv) 271 (1) (सी)
77. मेसर्स गंगाधर रामप्रताप, गोदिया
(i) पफ (ii) 1980-81 (iii) 22,140 (iv) 273 (2) (सी)
78. मेसर्स गंगाधर रामप्रताप, गोदिया
(i) पफ (ii) 1980-81 (iii) 27,037 (iv) 271 (1) (ए)
79. मै. गंगाधर, रामप्रताप, गोदिया
(i) व्य (ii) 1979-80 (iii) 10,500 (iv) 273 (2) (सी)
80. श्री पी.बी. मासुरकर, नागपुर
(i) व्य (ii) 1977-78 (iii) 7,334 (iv) 271 (1) (सी)
81. मेसर्स स्वस्तिक इंस्ट्रुक्शन, नागपुर
(i) पफ (ii) 1981-82 (iii) 19,500 (iv) 271 (1) (सी)
82. श्री विजय खेर, नागपुर
(i) व्य (ii) 1980-81 (iii) 5,250 (iv) 271 (1) (सी)
83. मेसर्स गंगाधर रामप्रताप, गोदिया
(i) पफ (ii) 1980-81 (iii) 63,700 (iv) 271 (1) (सी)
84. मेसर्स गंगाधर रामप्रताप, गोदिया
(i) पफ (ii) 1978-79 (iii) 35,000 (iv) 271 (1) (सी)
85. मेसर्स गंगाधर रामप्रताप, गोदिया
(i) पफ (ii) 1977-78 (iii) 28,210 (iv) 271 (1) (सी)
86. मेसर्स गंगाधर रामप्रताप, गोदिया
(i) पफ (ii) 1976-77 (iii) 76,030 (iv) 271 (1) (सी)
87. मेसर्स गंगाधर रामप्रताप, गोदिया
(i) (ii) 1975-76 (iii) 75,530 (iv) 271 (1) (सी)
88. मेसर्स गंगाधर रामप्रताप, गोदिया
(i) पफ (ii) 1974-75 (iii) 85,250 (iv) 271 (1) (सी)
89. मेसर्स गंगाधर रामप्रताप, गोदिया
(i) पफ (ii) 1973-74 (iii) 74,010 (iv) 271 (1) (सी)
90. मै. मंगलचंद धार, बागडी, नागपुर
(i) व्य (ii) 1981-82 (iii) 5,35,340 (iv) 271 (1) (सी)
91. मेसर्स पी.बी. मासुरकर, नागपुर
(i) पफ (ii) 1908-81 (iii) 72,500 (iv) 271 (1) (सी)
92. मेसर्स पी. बी. मासुरकर, नागपुर
(i) पफ (ii) 1981-82 (iii) 81,600 (iv) 271 (1) (सी)
93. मेसर्स पी.बी. मासुरकर, नागपुर
(i) पफ (ii) 1982-83 (iii) 1,07,800 (iv) 271 (1) (सी)
94. श्री प्रीतमसिंग बुधसिंग होरा, गोदिया
(i) व्य (ii) 1982-83 (iii) 1,24,980 (iv) 271 (1) (सी)
95. श्री प्रीतमसिंग बुधसिंग होरा, गोदिया
(i) व्य (ii) 1982-83 (iii) 9,350 (iv) 273 (2) (एए)
96. श्री डी.बी. मलहोत्रा, नागपुर
(i) व्य (ii) 1980-81 (iii) 7,040 (iv) 273 (1) (बी)
97. श्री डी.बी. मलहोत्रा, नागपुर
(i) व्य (ii) 1981-82 (iii) 7,130 (iv) 273 (1) (बी)
98. श्री डी.बी. मलहोत्रा, नागपुर
(i) व्य (ii) 1982-83 (iii) 10,233 (iv) 273 (1) (बी)
99. श्री डी.बी. मलहोत्रा, नागपुर
(i) व्य (ii) 1978-79 (iii) 52,272 (iv) 271 (1) (सी)
100. श्री डी.बी. मलहोत्रा, नागपुर
(i) व्य (ii) 1979-80 (iii) 53,200 (iv) 271 (1) (सी)
101. श्री डी.बी. मलहोत्रा, नागपुर
(i) व्य (ii) 1980-81 (iii) 92,550 (iv) 271 (1) (सी)
102. श्री डी.बी. मलहोत्रा, नागपुर
(i) व्य (ii) 1981-82 (iii) 90,304 (iv) 271 (1) (सी)
103. श्री डी.बी. मलहोत्रा, नागपुर
(i) व्य (ii) 1982-83 (iii) 1,29,100 (iv) 271 (1) (सी)
104. श्री, पी.बी. मासुरकर, नागपुर
(i) व्य (ii) 1978-79 (iii) 6,510 (iv) 271 (1) (सी)
105. श्री राकेशसिंग निरंजनसिंग, चंद्रपुर
(i) व्य (ii) 1979-80 (iii) 8,244 (iv) 271 (1) (ए)
106. श्री राकेशसिंग निरंजनसिंग, चंद्रपुर
(i) व्य (ii) 1980-81 (iii) 7,860 (iv) 271 (1) (ए)
107. श्री राकेशसिंग निरंजनसिंग, चंद्रपुर
(i) व्य (ii) 1981-82 (iii) 9,311 (iv) 271 (1) (ए)
108. श्री राकेशसिंग निरंजनसिंग, चंद्रपुर
(i) व्य (ii) 1982-83 (iii) 8,286 (iv) 271 (1) (ए)
109. श्री लालचंद शर्मा, कामठी
(i) व्य (ii) 1979-80 (iii) 10,070 (iv) 271 (1) (ए)
110. श्री लालचंद शर्मा, कामठी
(i) व्य (ii) 1980-81 (iii) 8,036 (iv) 271 (1) (ए)
111. श्री लालचंद शर्मा, कामठी
(i) व्य (ii) 1981-82 (iii) 5,162 (iv) 271 (1) (ए)
112. मेठ्यारचंद केसरीमल पोखवाल, कामठी
(i) हि (ii) 1978-79 (iii) 7,280 (iv) 18 (1) (ए)

S.O. 571.—Following is the list of persons on whom penalty not less than Rs. 5000 was imposed during the F. Y. 1984-85 indicating Status "I" for Individual, "H" for Hindu Undivided Families, "RF" for Registered firms, "URF" for Unregistered Firms "CO" for Companies and "STY" Co-operative Society "AOP" for Association of Persons (ii) for Assessment year (iii) Amount of penalty, (iv) Section under which the penalty was imposed :

1. Shri R.B. Bansilal Abirchand Pvt. Ltd. (under liquidation) Nagpur
(i) Co. (ii) 1970-71 (iii) 7,850 (iv) 271(1)(a)
2. Shri R.B. Bansilal Abirchand Pvt. Ltd. (Under liquidation) Nagpur
(i) Co. (ii) 1970-71 (iii) 9,500 (iv) 271(1)(c)
3. M/s. Agrawal Chemicals Traders, Rashim Oli, Nagpur
(i) RF (ii) 1982-83 (iii) 6,000 (iv) 273(1)(b)
4. M/s. Paramount Industries, Tilaknagar, Nagpur
(i) RF (ii) 1982-83 (iii) 5,490 (iv) 271(1)(a)
5. M/s. K.C. Aggrawal & Co. Sitabuldi, Nagpur
(i) RF (ii) 1977-78 (iii) 9,640 (iv) 271 (a)(c)
6. M/s. K.C. Agrawal & Co., Sitabuldi, Nagpur
(i) RF (ii) 1978-79 (iii) 7,527 (iv) 271 (1)(a)
7. M/s. K.C. Agarwal & Co., Sitabuldi, Nagpur
RF (ii) 1979-80 (iii) 6,570 (iv) 271(1)(a)
8. M/s. A.K. Gandhi, Sitabuldi, Nagpur
(i) RF (iii) 1981-82 (iii) 5,010 (iv) 271(1)(a)

9. Shri P.V. Ramnathan, P/o M/s. Central Scientific Co. Sadar, Nagpur
(i) I (ii) 1980-81 (iii) 8,000 (iv) 271 (1)(c)
10. M/s. Nagpur Gas and Domestic Appliances, & Services, Sadar, Nagpur
(i) RF (ii) 1982-83 (iii) 8,650 (iv) 273 (2)(b)
11. M/s. Sadiq & Co., Sadar, Nagpur
(i) RF (ii) 1982-83 (iii) 17,100 (iv) 271 (1)(c)
12. Shri S.K. Dhote, Wardha Road, Sitabuldi, Nagpur
(i) RF (ii) 1980-81 (iii) 15,150 (iv) 271(1)(c)
13. Central Drilling Association, Ramdaspath, Nagpur
(i) RF (ii) 1979-80 (iii) 5,170 (iv) 271 (1)(c)
14. M/s. D.S. Jain, Enterprises, Chandrapur
(i) RF (ii) 1982-83 (iii) 9,030 (iv) 271 (1)(c)
15. M/s. D.S. Jain, Enterprises, Chandrapur
(i) RF (ii) 1983-84 (iii) 6,190 (iv) 271(1)(a)
16. Shri G.A. Buradkar, Chandrapur
(i) I (ii) 1980-81 (iii) 7,000 (iv) 140A (3)
17. M/s. Chand Trading Co. Ramdaspath, Nagpur
(i) RF (ii) 1980-81 (iii) 5,365(a)(iv) 73 (1)(c)
18. Maharashtra State Mining Corporation Ltd., Nagpur
(i) Co (ii) 1979-80 (iii) 79,710 (iv) 271(1)(a)
19. Smt. Taradvi Mahendra Singh Saini, Amarvati
(i) I (ii) 1977-80 (iii) 6,929 (iv) 271 (1)(c)
20. M/s. Crescent Commercial Corporation, Akola
(i) RF (ii) 1980-81 (iii) 19,469 (iv) 271(1)(a)
21. M/s. Krishi Vaibhava Agencies, Akola
(i) RF (ii) 1980-81 (iii) 9,050 (iv) 271(1)(c)
22. M/s. Rahate Bros. Mehkar, Distt. Buldhana
(i) RF (ii) 1980-81 (iii) 7,950 (iv) 271(1)(c)
23. Shri Dinanath K. Sharma, Nagpur
(i) I (ii) 1980-81 (iii) 7,000 (iv) 73 (1)(c)
24. Shri Dinanath K. Sharma, Nagpur
(i) I (ii) 1980-81 (iii) 22,555 (iv) 140A(3)
25. Shri Dinanath K. Sharma, Nagpur
(i) I (ii) 1980-81 (iii) 5,701 (iv) 271(1)(c)
26. M/s. Agarwal Bamboo Depot, Gondia
(i) RF (ii) 1980-81 (iii) 6,45 (iv) 271(1)(c)
27. M/s. Agarwal Bamboo Depot, Gondia
(i) RF (ii) 1981-82 (iii) 5,706 (iv) 271(1)(c)
28. M/s. Onkarlal Badriprasad Agrawal, Gondia
(i) RF (ii) 1975-76 (iii) 6,080 (iv) 271(1)(c)
29. M/s. Onkarlal Badriprasad Agrawal, Gondia
(i) RF (ii) 1976-77 (iii) 16,587 (iv) 271(1)(c)
30. M/s. Onkarlal Badriprasad Agrawal, Gondia
(i) RF (ii) 1979-80 (iii) 6,949 (iv) 271(1)(c)
31. M/s. Onkarlal Badriprasad Agrawal, Gondia
(i) RF (ii) 1980-81 (iii) 18,028 (iv) 271(1)(c)
32. M/s. Onkarlal Badriprasad Agrawal, Gondia
(i) RF (ii) 1981-82 (iii) 17,442 (iv) 271(1)(c)
33. Shri Radheshyam Gulabchand Agarwal, Gondia
(i) I (ii) 1981-82 (iii) 5,740 (iv) 271(1)(c)
34. Shri Hemraj Hiralal Verma, C/o Moonlight, Nagpur
(i) I (ii) 1978-79 (iii) 6,183 (iv) 271(1)(c)
35. Shri Hemraj Hiralal Verma, C/o Moonlight, Nagpur
(i) I (ii) 1979-80 (iii) 9,176 (iv) 271(1)(c)
36. Shri Hemraj Hiralal Verma, C/o Moonlight, Nagpur
(i) I (ii) 1980-81 (iii) 11,918 (iv) 271(1)(c)
37. Shri Hemraj Hiralal Verma, C/o Moonlight, Nagpur
(i) I (ii) 1981-82 (iii) 13,960 (iv) 271(1)(c)
38. Shri Hemraj Hiralal Verma, C/o Moonlight, Nagpur
(i) I (ii) 1982-83 (iii) 17,436 (iv) 271(1)(c)
39. Shri Wasudeo Hiralal Verma, C/o Moonlight, Nagpur
(i) I (ii) 1975-76 (iii) 7,440 (iv) 271(1)(c)
40. Shri Wasudeo Hiralal Verma, C/o Moonlight, Nagpur
(i) I (ii) 1977-78 (iii) 5,684 (iv) 271(1)(c)
41. Shri Wasudeo Hiralal Verma, C/o Moonlight, Nagpur
(i) I (ii) 1978-79 (iii) 11,697 (iv) 271(1)(a)
42. Shri Wasudeo Hiralal Verma, C/o Moonlight, Nagpur
(i) I (ii) 1979-80 (iii) 11,069 (iv) 271(1)(c)
43. Shri Wasudeo Hiralal Verma, C/o Moonlight, Nagpur
(i) I (ii) 1980-81 (iii) 8,656 (iv) 271(1)(c)
44. Shri Wasudeo Hiralal Verma, C/o Moonlight, Nagpur
(i) I (ii) 1981-82 (iii) 9,616 (iv) 271(1)(c)
45. Shri Wasudeo Hiralal Verma, C/o Moonlight, Nagpur
(i) I (ii) 1982-83 (iii) 10,937 (iv) 271(1)(c)
46. M/s. National Automobiles, Gaddi Gudam, Nagpur
(i) RF (ii) 1979-80 (iii) 21,022 (iv) 271(1)(c)
47. M/s. National Automobiles, Gaddi Gudam, Nagpur
(i) RF (ii) 1980-81 (iii) 25,165 (iv) 271(1)(c)
48. M/s. National Automobiles, Gaddi Gudam, Nagpur
(i) RF (ii) 1981-82 (iii) 21,626 (iv) 271(1)(c)
49. M/s. National Automobiles, Gaddi Gudam, Nagpur
(i) RF (ii) 1979-80 (iii) 12,942 (iv) 271(1)(c)
50. M/s. National Automobiles, Gaddi Gudam, Nagpur
(i) RF (ii) 1980-81 (iii) 22,069 (iv) 271(1)(c)
51. M/s. Premsagar Chawla & Co., Nagpur
(i) RF (ii) 1979-80 (iii) 6,447 (iv) 271(1)(c)
52. M/s. Premsagar Chawla & Co., Nagpur
(i) RF (ii) 1979-80 (iii) 9,408 (iv) 271(1)(c)
53. M/s. Premsagar Chawla & Co., Nagpur
(i) RF (ii) 1980-81 (iii) 8,996 (iv) 271(1)(c)
54. Shri Satyawar Bhatia, Nagpur
(i) I (ii) 1975-76 (iii) 10,000 (iv) 271(1)(c)
55. Late Ramchandra Ganpatrao Samarth, L/H. Ramdas & Ramesh Samarth, Nagpur
(i) I (ii) 1981-82 (iii) 6,923 (iv) 271(1)(c)
56. Dadabhai Doshibhai (Hiranbai) Zal Charitable Trust Kamptee
(i) AOP (ii) 1976-77 (iii) 33,313 (iv) 271(1)(a)
57. Dadabhai Doshibhai (Hiranbai) Zal Charitable Trust Kamptee
(i) AOP (ii) 1977-78 (iii) 19,769 (iv) 271(1)(c)
58. Dadabhai Doshibhai (Hiranbai) Zal Charitable Trust Kamptee
(i) AOP (ii) 1980-81 (iii) 7,894 (iv) 271(1)(a)
59. Shri Sharadchandra Motiram Balpande, Ganeshnagar, Nagpur
(i) I (ii) 1980-81 (iii) 85,544 (iv) 271(1)(a)
60. Shri Sharadchandra Motiram Balpande, Ganeshnagar, Nagpur
(i) I (ii) 1980-81 (iii) 53,188 (iv) 271(1)(b)
61. Shri Sharadchandra Motiram Balpande, Ganeshnagar, Nagpur
(i) I (ii) 1980-81 (iii) 40,100 (iv) 273(2)(b)

62. Shri Sharadchandra Motiram Balpande, Ganeshnagar, Nagpur.
(i) I (ii) 1980-81 (iii) 3,14,000 (iv) 271(1)(c)
63. Shri Mangalchand R. Bagdi, Nagpur.
(i) I (ii) 1981-82 (iii) 11,120 (iv) 140A(4)
64. Shri Laxminsingh Verma, Nagpur.
(i) I (ii) 1981-83 (iii) 10,530 (iv) 271(1)(a)
65. Shri Laxminsingh Verma, Nagpur.
(i) I (ii) 1981-83 (iii) 39,480 (iv) 273(1)(b)
66. M/s. Swastik Construction, Nagpur.
(i) RF (ii) 1981-83 (iii) 7,650 (iv) 271(1)(c)
67. M/s. P.B. Masurkar, Nagpur.
(i) RF (ii) 1981-82 (iii) 5,471 (iv) 271(1)(a)
68. Late Shri P.B. Masurkar, Nagpur.
(i) I (ii) 1981-82 (iii) 5,060 (iv) 273(1)(b)
69. Shri Mangalchand R. Bagdi, Nagpur.
(i) I (ii) 1981-83 (iii) 16,674 (iv) 271(1)(c)
70. Shri Mangalchand R. BAGDI, Nagpur.
(i) I (ii) 1981-83 (iii) 26,552 (iv) 273(1)(b)
71. Shri Mangalchand R. Bagdi, Nagpur.
(i) I (ii) 1981-82 (iii) 22,240 (iv) 271(1)(a)
72. Shri Mangalchand R. Bagdi, Nagpur.
(i) I (ii) 1981-82 (iii) 42,010 (iv) 273(1)(b)
73. Shri Mangalchand R. Bagdi, Nagpur.
(i) I (ii) 1980-81 (iii) 7,310 (iv) 271(1)(c)
74. M/s. Raghubardayal Shyamsundar, Gondia.
(i) RF (ii) 1980-81 (iii) 10,170 (iv) 271(1)(c)
75. M/s. Raghubardayal Shyamsundar, Gondia.
(i) RF (ii) 1981-82 (iii) 10,090 (iv) 271(1)(c)
76. M/s. Raghubardayal Shyamsundar, Gondia.
(i) RF (ii) 1982-83 (iii) 16,500 (iv) 271(1)(c)
77. M/s. Ganga Har Rampratap, Gondia.
(i) RF (ii) 1980-81 (iii) 22,440 (iv) 273 (2)(c)
78. M/s. Ganga Har Rampratap, Gondia.
(i) RF (ii) 1980-81 (iii) 27,037 (iv) 271(1)(a)
79. Shri Gangadhar Rampratap, Gondia.
(i) I (ii) 1979-80 (iii) 10,500 (iv) 273(2)(c)
80. Late Shri P.B. Masurkar, Nagpur.
(i) I (ii) 1977-78 (iii) 7,334 (iv) 271(1)(c)
81. M/s. Swastik Construction, Nagpur.
(i) RF (ii) 1981-82 (iii) 19,500 (iv) 271(1)(c)
82. Shri Vijay Kher, Nagpur.
(i) I (ii) 1980-81 (iii) 5,250 (iv) 271(1)(c)
83. M/s. Ganga Har Rampratap, Gondia.
(i) RF (ii) 1980-81 (iii) 53,700 (iv) 271(1)(c)
84. M/s. Ganga Har Rampratap, Gondia.
(i) RF (ii) 1978-79 (iii) 13,35,000 (iv) 271(1)(c)
85. M/s. Gangadhar Rampratap, Gondia.
(i) RF (ii) 1977-78 (iii) 17,82,10 (iv) 271(1)(c)
86. M/s. Gangadhar Rampratap, Gondia.
(i) RF (ii) 1976-77 (iii) 75,030 (iv) 271(1)(c)
87. M/s. Gangadhar Rampratap, Gondia.
(i) RF (ii) 1975-76 (iii) 75,530 (iv) 271(1)(c)
88. M/s. Ganga Har Rampratap, Gondia.
(i) RF (ii) 1974-75 (iii) 85,250 (iv) 271(1)(c)
89. M/s. Gangadhar Rampratap, Gondia.
(i) RF (ii) 1973-74 (iii) 74,310 (iv) 271(1)(c)
90. Shri Mangalchand R. Bagdi, Nagpur.
(i) I (ii) 1981-82 (iii) 5,35,340 (iv) 271(1)(c)
91. M/s. P.B. Masurkar, Nagpur.
(i) RF (ii) 1980-81 (iii) 72,500 (iv) 271(1)(c)
92. M/s. P.B. Masurkar, Nagpur.
(i) RF (ii) 1981-82 (iii) 81,600 (iv) 271(1)(c)
93. M/s. P.B. Masurkar, Nagpur.
(i) RF (ii) 1982-83 (iii) 1,07,800 (iv) 271(1)(c)
94. Shri Pritamsingh Bhatnagar Hora, Gondia.
(i) I (ii) 1982-83 (iii) 1,24,980 (iv) 271(1)(c)
95. Shri Pritamsingh Bhatnagar Hora, Gondia.
(i) I (ii) 1982-83 (iii) 9,350 (iv) 273(1)(a)
96. Shri D.B. Malhotra, Nagpur.
(i) I (ii) 1980-81 (iii) 7,040 (iv) 273(1)(b)
97. Shri D.B. Malhotra, Nagpur.
(i) I (ii) 1981-82 (iii) 7,130 (iv) 273(1)(b)
98. Shri D.B. Malhotra, Nagpur.
(i) I (ii) 1982-83 (iii) 1,02,233 (iv) 273(1)(b)
99. Shri D.B. Malhotra, Nagpur.
(i) I (ii) 1978-79 (iii) 52,272 (iv) 271(1)(c)
100. Shri D.B. Malhotra, Nagpur.
(i) I (ii) 1979-80 (iii) 53,200 (iv) 271(1)(c)
101. Shri D.B. Malhotra, Nagpur.
(i) I (ii) 1980-81 (iii) 92,550 (iv) 271(1)(c)
102. Shri D.B. Malhotra, Nagpur.
(i) I (ii) 1981-82 (iii) 90,304 (iv) 271(1)(c)
103. Shri D.B. Malhotra, Nagpur.
(i) I (ii) 1982-83 (iii) 1,09,100 (iv) 271(1)(c)
104. Late Shri P.B. Masurkar, Nagpur.
(i) I (ii) 1973-79 (iii) 6,500 (iv) 271(1)(c)
105. Shri Rakshsingh Niranjansingh, Chandrapur.
(i) I (ii) 1979-80 (iii) 8,244 (iv) 271(1)(a)
106. Shri Rakshsingh Niranjansingh Chandrapur.
(i) I (ii) 1980-81 (iii) 7,860 (iv) 271(1)(a)
107. Shri Rakshsingh Niranjansingh, Chandrapur.
(i) I (ii) 1981-82 (iii) 9,311 (iv) 271(1)(a)
108. Shri Rakshsingh Niranjansingh, Chandrapur.
(i) I (ii) 1982-83 (iii) 8,786 (iv) 271(1)(a)
109. Shri Lalchand Sharma, Kamptee.
(i) I (ii) 1979-80 (iii) 10,070 (iv) 271(1)(a)
110. Shri Lalchand Sharma, Kamptee.
(i) I (ii) 1980-81 (iii) 8,036 (iv) 271(1)(a)
111. Shri Lalchand Sharma, Kamptee.
(i) I (ii) 1981-82 (iii) 5,162 (iv) 271(1)(a)
112. Sath Pyarchand K. Srinimal Porwal, Kamptee.
(i) I (ii) 1978-79 (iii) 7,280 (iv) 18(1)(a)

वा.प्र. 572.—वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान ऐसे व्यक्तियों को सूची नंबर प्रस्तुत की जा रही है जिनका 10 लाख रु. से अधिक शुद्ध धन पर निर्धारण किया गया है। (i) प्रस्थिति—व्यक्तियों के लिए “क”, हिन्दु व्यक्तिगत कुटुम्ब के लिए “हि”, व्यक्तियों के समुदाय के लिए “व्यसमु”, स्त्रियों के लिए “व्या” (ii) निर्धारण वर्ष (iii) विश्वरणी में दर्शाया धन/निर्धारित धन (iv) निर्धारित द्वारा देय कर (v) निर्धारित द्वारा देया किया गया कर, दर्शाता है।

1. श्रीमती बर्षा प्रफुल पटेल द्वारा मयूर कापूरेशन, गोदिया

(i) व्य (ii) 1984-85 (iii) 15,82,880/16,01,400
(iv) 33,819 (v) 33,819

2. श्री एन.जी. बटाले, प्रमरावती रोड नागपुर
(i) व्य (ii) 1983-84 (iii) 4,48,631/11,05,712
(iv) 19,192 (v) 19,192
3. श्रीमती उपादेवी बी/बा राणाप्रताप सिंह, गोकुलपेट, नागपुर
(i) हि (ii) 1979-80 (iii) 4,80,290/108,4650
(iv) 14,865 (v) --
4. श्री श्री के बूटी, सिलाबर्डी, नागपुर
(i) हि (ii) 1980-81 (iii) 17,30,013/17,30,000
(iv) 57,380 (v) 57,380
5. श्री जी के बूटी, सिलाबर्डी, नागपुर
(i) हि (ii) 1980-81 (iii) 14, 25,624/14,25,640
(iv) 42,885 (v) --
6. श्रीमती इंदिराबाई बूटी, सिलाबर्डी, नागपुर
(i) व्य (ii) 1981-82 (iii) 10,98,356/39,76,600
(iv) 1,40,600 (v) 43,125
7. श्रीमती इंदिराबाई बूटी, सिलाबर्डी, नागपुर
(i) व्य (ii) 1980-81 (iii) 1,53,400/13,88,578
(iv) 24,667 (v) 17,160
8. श्री श्रीकांत खेमका, सदर, नागपुर
(i) हि (ii) 1980-81 (iii) 1,02,297/10,29,630
(iv) 14,080 (v) --
9. श्री सुशीलकुमार खेमका, सदर, नागपुर
(i) हि (ii) 1980-81 (iii) 89,811/10,01,983
(iv) 13,520 (v) --
10. श्री ई सी एड्डुलजी, नागपुर
(i) व्य (ii) 1984-85 (iii) 13,20,200/13,20,200
(iv) 23,357 (v) 23,357
11. श्री भगनभाई जी पटेल, चंद्रपुर
(i) व्य (ii) 1984-85 (iii) --/10,26,200 (iv) 14,535
(v) 14,535
12. श्रीमती लक्ष्मीबाई सी. पटेल, चंद्रपुर
(i) व्य (ii) 1984-85 (iii) --/13,92,300 (iv) 25,520
(v) 25,520
13. श्री सी.जी. पटेल, चंद्रपुर
(i) व्य (ii) 1984-85 (iii) --/19,41,530 (iv) 50,827
(v) 50,827
14. श्रीमती पंचफूलाबाई रत्नलाल सुराना, पांढरकबडा
(i) व्य (ii) 1984-85 (iii) 10,48,000/10,48,000
(iv) 15,186 (v) 15,186
15. सी. अमोला जितेन्द्र मुनोली, यवतमाल
(i) व्य (ii) 1984-85 (iii) 10,05,300/10,05,300
(iv) 13,910 (v) 13,910
16. सी. मार्णिक रमेशचंद्र मुनोली, यवतमाल
(i) व्य (ii) 1984-85 (iii) 10,01,200/10,01,200
(iv) 13,786 (v) 13,786
17. श्री हरिणचंद्र आर. मुनोली, यवतमाल
(i) व्य (ii) 1984-85 (iii) 12,60,800/12,60,800
(iv) 21,575 (v) 21,575
18. सी. प्रमोला ए. मुनोली, यवतमाल
(i) व्य (ii) 1984-85 (iii) 13,16,100/13,16,100
(iv) 23,232 (v) 23,232
19. सी. नविना जी. मुनोली, यवतमाल
(i) व्य (ii) 1984-85 (iii) 11,95,700/11,95,700
(iv) 19,620 (v) 19,620
20. सी. मेलाबाई पी. गुगना, पांढरकबडा
(i) व्य (ii) 1984-85 (iii) 12,88,250/12,88,250
(iv) 21,746 (v) 21,746
21. श्री नरेन्द्र गोधाजीराव मुखरे, तुमसर
(i) व्य (ii) 1984-85 (iii) 13,48,700/13,48,700
(iv) 24,215 (v) 24,215
22. श्रीमती अदादेवी सराफ, सरोज भवन, नागपुर
(i) व्य (ii) 1978-79 (iii) 7,62,383/11,09,460
(iv) 16,487 (v) 16,487
23. श्रीमती स्वरजलतादेवी सराफ, सरोज भवन, नागपुर
(i) व्य (ii) 1980-81 (iii) 10,37,100/10,22,218
(iv) 14,416 (v) 14,416
24. श्री नारायणदास सराफ, श्रीराम भवन, तुमसर
(i) हि (ii) 1980-81 (iii) -- 27,91,567/14,94,357
(iv) 48,465 (v) --
25. मेमसे रामकिशन सराफ, श्रीराम भवन, तुमसर
(i) हि (ii) 1980-81 (iii) -- 31,80,759/11,95,150
(iv) 33,505 (v) --
26. श्री मुरलीधर सराफ, श्रीराम भवन, तुमसर
(i) हि (ii) 1980-81 (iii) 13,31,900/13,59,493
(iv) 41,723 (v) 37,680
27. श्रीमती चंद्रादेवी सराफ, सरोज भवन, नागपुर
(i) व्य (ii) 1980-81 (iii) 29,21,933/29,21, 933
(iv) 94,854 (v) 94,854
28. श्री निशिरकुमार बजाज कमिली ट्रस्ट, वर्धा
(i) व्यसमु (ii) 1984-85 (iii) 13,19,700/13,19,700
(iv) 39,590 (v) 39,590
29. श्री संजीवनयन बजाज, कमिली ट्रस्ट, मंदर-2, वर्धा
(i) व्यसमु (ii) 1984-85 (iii) 11,52,000/ 11,52,000
(iv) 34,561 (v) 34,561
30. श्री मधुर कुमार बजाज कमिली ट्रस्ट, मंदर-1, वर्धा
(i) व्यसमु (ii) 1984-85 (iii) 23,10,600/ 23,10,600
(iv) 69,319 (v) 69,319
31. शेखर कुमार बजाज कमिली ट्रस्ट, नागपुर
(i) व्यसमु (ii) 1984-85 (iii) 30,00,600/30,00,600
(iv) 1,03,781 (v) 1,03,782
32. श्रीमती हरियानीबाई आर. हेडा, प्रमरावती
(i) व्य (ii) 1982-83 (iii) 13,60,262/13,60,262
(iv) 23,800 (v) 23,800
33. श्रीमती हरियानीबाई आर. हेडा, प्रमरावती
(i) व्य (ii) 1983-84 (iii) 13, 22, 068/13,22,068
(iv) 22, 700 (v) 22, 700
34. श्री तक्षतमल श्रीवल्लभ चांडक, प्रमरावती
(i) हि (ii) 1981-82 (iii) 10,61,855/10,61,855
(iv) 25,560 (v) 25,560
35. श्री तक्षतमल श्रीवल्लभ चांडक, प्रमरावती
(i) हि (ii) 1982-83 (iii) 11,35,964/11,35,964
(iv) 29,094 (v) 29,094

36. श्रीमती नारायणीबाई राधावल्लभजी हेडा, श्रीसदन भमरावती
(i) व्य (ii) 1984-85 (iii) 14,05,868/14 55, 868
(iv) 26, 628 (v) 26, 628
37. श्रीमती निर्मला के. मिक्वी, भमरावती
(i) व्य (ii) 1984-85 (iii) 13,53, 300/13, 53, 300
(iv) 23, 640 (v) 23, 640
38. श्री राधावल्लभजी पूरनमल हेडा, श्री सदन, भमरावती
(i) हि (ii) 1984-85 (iii) 10, 38, 030/12, 10, 500
(iv) 32, 643 (v) 32, 643
39. श्री राजेशकुमार पोरवाल, कामठी
(i) व्य (ii) 1981-82 (iii) 4, 98, 133/16, 45, 700
(iv) 37, 035 (v) 5, 676
40. श्री सुशील कुमार पोरवाल, कामठी
(i) व्य (ii) 1981-82 (iii) 2, 26, 054/13, 88, 300
(iv) 25, 399 (v) 1, 124
41. श्री संजीव कुमार पोरवाल, कामठी
(i) व्य (ii) 1981-82 (iii) 6,04,551/13,51,600
(iv) 24,278 (v) 5, 851
42. श्री राजेश कुमार पोरवाल, कामठी
(i) व्य (ii) 1981-82 (iii) 6,20,942/16,86,700
(iv) 38,085 (v) 6,063
43. श्री सुनिल कुमार पोरवाल, कामठी
(i) व्य (ii) 1981-82 (iii) 4,80,487/16,17,800
(iv) 34,640 (v) 4,970
44. श्री राजेश कुमार पोरवाल, कामठी
(i) व्य (ii) 1982-83 (iii) 4,78,035/18,72,400
(iv) 47,370 (v) 6,590
45. श्री सुशील कुमार पोरवाल, कामठी
(i) व्य (ii) 1982-83 (iii) 1,32,900/15,51,700
(iv) 29,840 (v) 1,235
46. श्री राजेश कुमार पोरवाल, कामठी
(i) व्य (ii) 1982-83 (iii) 4,07,187/17,93,700
(iv) 43,435 (v) 5,852
47. श्री संजीव कुमार पोरवाल, कामठी
(i) व्य (ii) 1982-83 (iii) 5,13,041/19,54,000
(iv) 49,000 (v) 8,060
48. श्री सुनिल कुमार पोरवाल, कामठी
(i) व्य (ii) 1982-83 (iii) 4,03,064/17,87,000
(iv) 43,100 (v) 5,295
49. श्री ए. नाथ, खेरे, नागपुर
(i) व्य (ii) 1980-81 (iii) 6,93,000/10,08,800
(iv) 13,954 (v) —
50. श्रीमती रमादेवी रुइया, नागपुर
(i) व्य (ii) 1982-83 (iii) 6,32,380/10,43,300
(iv) 15,049 (v) 6,273
51. श्रीमती रमादेवी हमा नागपुर
(i) व्य (ii) 1983-84 (iii) 7,71,900/10,87,000
(iv) 16,360 (v) 9,186
52. श्री सुनिल कुमार पोरवाल, कामठी
(i) व्य (ii) 1983-84 (iii) 3,66,656/17,52,300
(iv) 41,362 (v) 3,126

53. श्री राजेशकुमार पोरवाल, कामठी
(i) व्य (ii) 1983-84 (iii) 4,65,542/18,60,500
(iv) 46,771 (v) 4,385
54. श्री संजीव कुमार पोरवाल, कामठी
(i) व्य (ii) 1983-84 (iii) 5,66,471/19,55,900
(iv) 51,543 (v) 6,725
55. श्री राजेश कुमार पोरवाल, कामठी
(i) व्य (ii) 1983-84 (iii) 3,27,190/17,16,600
(iv) 39, 581 (v) 2, 846
56. श्री सुशील कुमार पोरवाल, कामठी
(i) व्य (ii) 1983-84 (ii) 1,01,682 14,91,900
(iv) 28, 519 (v) —
57. श्री सुशील कुमार पोरवाल, कामठी
(i) हि (ii) 1980-81 (iii) —/14,67,800 (iv) 44,895
(v) 8,130

[फा. स. बसूली/287/42प/85-86]
केदार नाथ, आयकर आयुक्त

S.O. 572.—Following is the list of persons who have been assessed on net Wealth over Rs. 10 lakhs during the Financial Year 1984-85 indicating (i) Status "I" for Individuals and "H" for H.U.F.s, "AOP" for Association of persons and "T" for Trusts (ii) Asstt. Year (iii) for Wealth returned/wealth assessed (iv) for tax payable by the assessee (v) Tax paid by the assessee.

1. Smt. Varsha Praful Patel C/o. Mayur Corporation, Gondia (i) I (ii) 84-85 (iii) 15,82,880/16,01,400 (iv) 33,819 (v) 33,819.
2. Shri S. G. Ghatate, Ausravati Road, Nagpur, (i) I (ii) 83-84 (iii) 4,48,631/11,05,712 (iv) 19,192 (v) 19,192.
3. Smt. Umadevi, L/H Ranapratap Singh, Gokulpeth, Nagpur (i) H (ii) 79-80 (iii) 4,80,290/10,84,650 (iv) 14,865 (v) —.
4. Shri V. K. Buty, Sitabuldi, Nagpur, (i) H (ii) 80-81 (iii) 17,30,000/17,30,000 (iv) 57,380 (v) 57,380.
5. Shri G. K. Buty, Sitabuldi, Nagpur, (i) H (ii) 80-81 (iii) 14,25,624/14,25,640 (iv) 42,885 (v) —.
6. Smt. Indirabai Buty, Sitabuldi, Nagpur, (i) I (ii) 81-82 (iii) 10,98,356/39,76,600 (iv) 140,600 (v) 43,125.
7. Smt. Indirabai Buty, Sitabuldi, Nagpur, (i) I (ii) 80-81 (iii) 11,53,400/13,88,578 (iv) 24,667 (v) 17,160.
8. Shri Shrikant Khemka, Sadar, Nagpur, (i) H (ii) 80-81 (iii) 1,02,297/10,29,630 (iv) 14,080 (v) —.
9. Shri Sushilkumar Khemka, Sadar Nagpur, (i) H (ii) 80-81 (iii) 89,811/10,01,983 (iv) 13,520 (v) —.
10. Shri E. C. Eduljee, Nagpur, (i) I (ii) 84-85 (iii) 13,20,200/13 20,200 (iv) 23,357 (v) 23,357.
11. Shri Maganbhai G. Patel, Chandrapur, (i) I (ii) 84-85 (iii) —/10,26,200 (iv) 14,535 (v) 14,535.
12. Smt. Lalitabai C. Patel, Chandrapur, (i) I (ii) 84-85 (iii) —/13,92,300 (iv) 25,520 (v) 25,520.
13. Shri C. G. Patel, Chandrapur, (i) I (ii) 84-85 (iii) —/19,41,530 (iv) 50,827 (v) 50,827.
14. Smt. Panchfulabai Ratanlal Surana, Pandharkawda, (i) I (ii) 84-85 (iii) 10,48,000/10 48,000 (iv) 15,186 (v) 15,186.

15. Sau. Amita Jitendra Munotiyh, Yavatmal, (i) I (ii) 84-85 (iii) 10,05,300|10,05,300 (iv) 13,916 (v) 13,910—
16. Sau. Manik Ramesh chand, Munot, Yavatmal, (i) I (ii) 84-85 (iii) 10,01,200|10,01,200 (iv) 13,786 (v) 13,786.
17. Shri Harishchand R. Munot, Yavatmal, (i) I (ii) 84-85 (iii) 12,60,800|12,60,800 (iv) 21,575
18. Sau. Pramila A. Munot Yavatmal, (i) I (ii) 84-85 (iii) 13,16,100|13,16,100 (iv) 23,232 (v) 23,232.
19. Sau. Nandini D. Munot, Yavatmal, (i) I (ii) 84-85 (iii) 11,95,700|11,95,700 (iv) 19,620 (v) 19,620.
20. Sau. Mamabai P. Surana, Randharkawda, (i) I (ii) 84-85 (iii) 12,88,250|12,88,250 (iv) 21,746 (v) 21,746.
21. Shri Narendra Godhajira, Mu Khare, Pusad, (i) I (ii) 84-85 (iii) 13,48,700|13,48,700 (iv) 24,215 (v) 24,215.
22. Smt. Chandadevi Saraf, Saroj Bhawan, Nagpur, (i) I (ii) 78-79 (iii) 7,63,383|11,09,460 (iv) 16,487 (v) 16,487.
23. Smt. Swarnaladevi Saraf, Saroj Bhawan, Nagpur, (i) I (ii) 80-81 (iii) 10,37,100|10,22,218 (iv) 14,416 (v) 14,416.
24. Shri Narayandas Saraf Shriram Bhawan, Tumsar, (i) H (ii) 80-81 (iii) — 27,91,567|14,94,357 (iv) 48,465. (v) —.
25. M/s. Ramkisan Saraf, Shriram Bhawan, Tumsar, (i) H (ii) 80-81 (iii) — 31,80,759|11,95,150 (iv) 33,505 (v) NIL.
26. Shri Murlidhar Saraf, Shriram Bhawan, Tumsar, (i) H (ii) 80-81 (iii) 13,31,800|13,59,463 (iv) 41,723 (v) 37,660.
27. Smt. Chandadevi Saraf, Saroj Bhawan, Nagpur, (i) I (ii) 80-81 (iii) 29,21,933|29,21,933 (iv) 94,854 (v) 94,854.
28. Shishirkumar Bajaj Family Trust, Wardha, (i) I, I "T" (ii) 84-85 (iii) 11,52,000|11,52,000 (iv) 39,590 (v) 39,590.
29. Sanjivnayan Bajaj Family Trust, No. 2, Wardha, (i) I "T" (ii) 84-85 (iii) 11,52,000|11,52,000 (iv) 34,561 (v) 34,561.
30. Madhirkumar Bajaj Family Trust No. 1, Wardha. (i) I "T" (ii) 84-85 (iii) 23,10,600|23,10,600 (iv) 69,219 (v) 69,319.
31. Shekharkumar Bajaj Family Trust Nagpur, (i) I "T" (ii) 84-85 (iii) 30,00,600|30,00,600 (iv) 1,03,781 (v) 1,03,781.
32. Smt. Haryanibai R. Reda, Amaravati, (i) I (ii) 82-83 (iii) 13,60,262|13,60,262 (iv) 23,800 (v) 23,800.
33. Smt. Haryanibai R. Reda, Amaravati, (i) I (ii) 83-84 (iii) 13,22,068|13,22,068 (iv) 22,700 (v) 22,700—
34. Shri Takatmal Shrivallabh Chandak, Amaravati, (i) H (ii) 81-82 (iii) 10,61,855|10,61,855 (iv) 25,560 (v) 25,560.
35. Shri Takatmal Shrivallabh Chandak, Amaravati, (i) H (ii) 82-83 (iii) 11,35,964|11,35,964 (iv) 29,094 (v) 29,094.
36. Smt. Narayanibai w/o Radhavallabhji Heda, Shree Sadan, Amaravati (i) I (ii) 84-85 (iii) 14,05,8,81|14,55,868 (iv) 26,628 (v) 26,628.
37. Smt. Nirmala K. Sikehi, Amaravati, (i) I (ii) 84-85 (iii) 13,53,300|13,53,300 (iv) 23,640 (v) 23,640.
38. Shri Radhavallabhji Purangul Heda, Shree Sadan, Amaravati, (i) H (ii) 84-85 (iii) 10,38,030|12,10,500 (iv) 32,43 (v) 32,643.
39. Shri Rakeshkumar Porwal Kamptee (i) I (ii) 81-82 (iii) 4,98,133|16,45,700 (iv) 36,035 (v) 5,676.
40. Shri Sushilkumar Porwal, Kamptee, (i) I (ii) 8-82 (iii) 2,26,054|13,88,300 (iv) 25,399 (v) 1,124.
41. Shri Sanjivkumar Porwal, Kamptee, (i) I (ii) 81-82 (iii) 6,04,551|13,51,600 (iv) 24,298 (v) 5,851.
42. Shri Rajeshkumar Porwal, Kamptee, (i) I (ii) 81-82 (iii) 6,20,942|16,86,700 (iv) 38,085 (v) 6,063.
43. Shri Sunilkumar Porwal, Kamptee, (i) I (ii) 81-82 (iii) 4,80,487|16,17,800 (iv) 34,640 (v) 4,970.
44. Shri Rajesh Kumar Porwal, Kamptee, (i) I (ii) 82-83 (iii) 4,78,035|18,72,400 (iv) 47,370 (v) 6,590.
45. Shri Sushilkumar Porwal, Kamptee, (i) I (ii) 82-83 (iii) 1,32,900|15,51,700 (iv) 29,840 (v) 1,235.
46. Shri Rajeshkumar Porwal, Kamptee, (i) I (ii) 82-83 (iii) 4,07,187|17,93,700 (iv) 43,435 (v) 5,852.
47. Shri Sanjivkumar Porwal, Kamptee, (i) I (ii) 82-83 (iii) 5,13,041|19,54,000 (iv) 49,000 (v) 8,060.
48. Shri Sunilkumar Porwal, Kamptee, (i) I (ii) 82-83 (iii) 4,05,064|17,87,000 (iv) 43,100 (v) 5,295.
49. Shri A. Y. Khare, Nagpur, (i) I (ii) 80-81 (iii) 6,93,000|10,06,800 (iv) 13,954 (v) NIL.
50. Smt. Ramadevi Rujia, Nagpur, (i) I (ii) 82-83 (iii) 6,32,380|10,43,300 (iv) 15,049 (v) 6,273.
51. Smt. Ramadevi Rujia, Nagpur, (i) I (ii) 83-84 (iii) 7,71,900|10,87,000 (iv) 16,360 (v) 9,186.
52. Shri Sunilkumar Porwal, Kamptee, (i) I (ii) 83-84 (iii) 3,66,656|17,52,300 (iv) 41,362 (v) 3,126.
53. Shri Rajeshkumar Porwal, Kamptee, (i) I (ii) 83-84 (iii) 4,65,542|18,60,500 (iv) 46,771 (v) 4,385.
54. Shri Sanjivkumar Porwal, Kamptee, (i) I (ii) 83-84 (iii) 5,66,471|19,55,900 (iv) 51,543 (v) 6,725.
55. Shri Rakeshkumar Porwal, Kamptee, (i) I (ii) 83-84 (iii) 3,27,190|17,16,600 (iv) 39,581 (iv) 2,846.
56. Shri Sushilkumar Porwal, Kamptee, (i) I (ii) 83-84 (iii) 1,01,682|14,91,900 (iv) 28,519 (v) NIL.
57. Shri Sushilkumar Porwal, Kamptee, (i) H. (ii) 80-81 (iii)—|14,67,800 (iv) 44,895 (v) 8,130.

[F. No. Recy/287/42-A/85-86]

KEDAR NATH, Commissioner of Income-tax

कार्मिक मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1986

का. धा. 373:—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधि-
नियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की धारा 7 की धारा (i) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एन० द्वारा मैसर्स
पेस्ट कंट्रोल केमिकल्स, मेन रोड, कान्नावरी, थोटा, गुन्टर-4 तथा मैसर्स
ग्रेड कंट्रोल केमिकल्स, शांता कार्यालय, कमर्शियल रोड, काकीनाडा को
भी अन्योन्यनियम कायदा का निम्नलिखित मदों के लिए घुसक के रूप
में प्रयोग करते हुए, घुसरोक्षण के लिए अधिचरण के रूप में 11 फरवरी,
1986 से एक और वर्ष की अवधि के लिए मान्यता देती है :-

(1) लेब रॉलिंग मशीन की भूरी, प्रॉर

(2) हड्डी का बूग, छुर और सींग

[कायदा सं. 5 (12)/83- ई आई एंड ई पी]
टी और नागराजन, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 15th February, 1986

S.O. —In exercise of powers conferred by sub-Section
(1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspec-
tion) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government
hereby recognises for a further period of one year with effect
from 11th February, 1986 M/s. Pest Control Chemicals,
Main Road, Kannavari, Thota Gunter-4 and also branch of
M/s. Pest Control Chemicals at Commercial Road, Kakinada

as an agency for the fumigation using Aluminium Phosphide as a fumigant for the following items :—

1. De-oiled Rice Bran; and
2. Crushed Bones, Hooves and Horns.

[F. No. 5 (12)/83-FL&EP]

T. R. NAGARAJAN, Under Secy.

(मुख्य निर्यातक, आयात एवं निर्यात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1986

आदेश

का.सा. 574:—मैसर्स रिलायन्स टेक्स्टाइल इंडस्ट्रिज लि. 222, मेकर चैंबर-4 तृतीय मंजिल, नारिमान प्वाइंट, बम्बई-400021 को आई डी वी आई/आई एस सी आई से विदेशी मूद्रा के अधीन पंजीकृत माल मशीनरी का आयात करने के लिए 46, 78, 73,800/- रुपए (छयासीस करोड़ अठहत्तर लाख अठहत्तर हजार आठ सौ रुपये मात्र) के लिए एक आयात लाइसेंस सं. पी/सीजी/2098300/ एस/टर्म्सपूर्व/95/एच/85/सीजी-1/ एलएस, दिनांक 13-1-1985 दिया गया था।

इस फर्म ने ऊपर उल्लिखित लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारा करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई या अस्थायित्व हो गई है। आगे यह भी बताया गया है कि लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति सीमा शुल्क प्राधिकारी, बम्बई के पास पंजीकृत कराई गई थी और इस प्रकार सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति के मूल्य का प्राणिक उपयोग कर लिया गया है।

2. धरने तक के समय में आईसेंसधारी ने पंजीकृत और महानगरीय मजिस्ट्रेट, बम्बई के सामने विधिवत शपथ लेकर स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं तदनुसार सन्तुष्ट हूँ कि आयात लाइसेंस सं. पी/सीजी/2098300, दिनांक 13-5-85 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति फर्म द्वारा खो गई/ अस्थायित्व हो गई है। तथा संशोधित आयात (नियंत्रण) अधिनियम, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9 (अग) के अधीन प्रवर्तन अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स रिलायन्स टेक्स्टाइल इंडस्ट्रिज लि., बम्बई को जारी की गई मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति सं. पी/सीजी/2098300, दिनांक 13-5-1985 एतद्वारा रद्द की जाती है।

3. शेष मूल्य 3, 82, 48, 352/- रुपए मात्र के लिए उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति पाटी की प्रतिलिपि से जारी की जा रही है।

[स. सीजी-1/1640/23/ 84-85/710]

पात्र श्रेक, उपा मुख्य निर्यातक, आयात निर्यात के मुख्य निर्यातक,
आयात-निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

New Delhi, 30th January, 1986

ORDER

S.O. 574.—M/s. Reliance Textile Industries Ltd., 222, Maker Chambers-IV, Third Floor, Nariman Point, Bombay-400021 were granted an Import Licence No. P/CG/2098300/ S/WP/95/H/85/CG. ILS dated 13-5-1985 for Rs. 46,78,72,800/- (Rupees Forty Six Crores Seventy Eight Lakhs Seventy Two Thousand and Eight Hundred only) for import of Capital Goods Machinery under Foreign Exchange Loan from I.D.B.I.L.F.C.I.

The firm has applied for issue of Duplicate Copy of Customs purposes copy of the above mentioned Licence on the ground that the original Customs purposes copy of the Licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Customs purposes copy of the Licence has registered with Customs Authority, Bombay and as such the value of Customs Purpose copy has been utilised partly.

2. In support of their contention, the Licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Registrar and Metropolitan Magistrate, Bombay. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes copy of Import Licence No. P/CG/2098300 dated 13-5-1985 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9 (cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Customs Purposes copy No. P/CG/2098300 dated 13-5-1985 issued to M/s. Reliance Textile Industries Ltd, Bombay is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs purpose copy of the said Licence is being issued to the party separately for the balance value of Rs. 3,83,48,352/- only.

[No. CG. I/1640/23/84-85/710]

PAUL BECK, Dy. Chief Controller of Imports and
Exports For Chief Controller of Imports and
Exports.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1986

आदेश

का.सा. 575:—आई डी वी आई ए केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद (पक्रा संख्या) नियम, 1952 के नियम 8 के उपनियम (2) के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग और कंवर्त कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. सा. 2897/आई डी. आर. ए. तारीख 1 जून, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त आदेश में, क्रम सं. 7 और उरते संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :-

"7- श्री एफ. एफ. आफ, उपाध्यक्ष,
विक्रय और विपणन,
मैसर्स, टाटा आयात लिमिटेड कं. लि.
बम्बई हाउस,

24, होमी मोदी स्ट्रीट, मुम्बई-400023"

[फा. सं. 14 (3)/85- का प्र सु/ई जी. जी.]

ए. पी. सखन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 31st January, 1986

ORDER

S.O. 575 IDRA.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 8 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 2897/IDRA, dated the 1st June, 1985, namely :—

In the said Order for serial number 7 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

"7. Mr. F. F. Shroff, Vice President, Sales & Marketing, M/s. Tata Oil Mills Co. Ltd., Bombay House, 24 Homi Mody Street, Bombay-400023."

[F. No. 14 (3)/85-DPR/EOG]

A. P. SARWAN, Joint Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1986

का.प्र. 576:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक-हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन. के. एक. बी. से एन. के. 124 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस उपयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

यहाँ कि उक्त भूमि में हितवन्त कोई व्यक्ति, उस भूमि के नाबे पाइप लाइन बिछाने के लिए आशेष सक्षम प्राधिकार, तेल तथा प्राकृतिक गैस उपयोग, निर्माण और देखभाल प्रमाण, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित यह भी बयान करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की भाँति।

अनुसूची

एन. के. एक. बी. से एन. के. 124 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य - गुजरात जिला - मेहसाणा तालुका - विरमगम

गांव	स. नं.	हेक्टेयर एघार ई	सेन्टीयर	
तेलावी	241/पा	0	03	72
	243	0	04	20
	243	0	04	68
	243	0	08	38
कार्टट्रेक		0	00	72
	226/1	0	11	76
	226/4	0	09	60
	225/7	0	03	00

[सं. O-12016/7/86-बी एन जी- 4]

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 30th January, 1986

S.O. 576.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from NKFB to NK-124 in Gujarat State Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land shall, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra (390 009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from N. NKFB to NK-124

State : Gujarat Distt : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village:	Survey No.	Hectare	Area	Centiare
Telavi	241/P	0	03	72
	243	0	04	20
	243	0	04	68
	243	0	06	38
	Cart track	0	00	72
	226/1	0	11	76
	26/4	0	09	60
	225/7	0	03	00

[N. O-12016/7/86-ONG-1-4]

का. प्र. 577.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. प्र. सं. 1828 तारीख 26-5-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के कारण तेल और प्राकृतिक गैस उपयोग में सभी व्यक्तियों से राजस्व में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को विहित होगा।

अनुसूची

जे. धार. जे. से सालोरा-9 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य - गुजरात जिला- मेहसाणा तालुका - कड़ो

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	एघार ई	सेन्टीयर
मेरठा	161	0	11	70
	163	0	16	80

[सं. O-12016/33/84 - बी एन जी - 4]

बी. के. राजगोपालन, डी. स्क. अधिकारी

S.O. 577.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1826 dated 26-5-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances

SCHEDULE

Pipeline from JRI to JHALORA 9

State : Gujarat (District: Mehsana Taluka : Kadi)

Village	Survey No.	Hectare	Area	Conti- are
Merda	161	0	11	70
	163	0	16	80

[N.O-12006/33/84-CNG-D4]

P.K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1986

का.प्र. 573:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारा क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वक्षण करने के अपने प्राणय की सूचना देती है;

इन अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. सी-1 (ई)/III/ई.धार./302-1085 तारीख 11 अक्टूबर, 1985 का निर्माण वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि., (राजस्व अनुभाग), कोयला एस्टेट, मिथिन माइन्स-नागपुर-440001 के कार्यालय में या कमन्डर, शाहडोल (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में प्रेषित कोयला नियंत्रण, 1-काउंसिल हाउस रूट, वायफता के कार्यालय में दिया जा सकता है।

इन अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितवृद्ध कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निश्चित सभी शक्तियों, शर्तों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, राजस्व अनुभाग, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि., कोयला एस्टेट, सिविल लाइंस, नागपुर-440001 को भेजेगा।

अनुसूची

करफाली ब्लॉक

सोहागपुर कोयला क्षेत्र

जिला शाहडोल (मध्य प्रदेश)

पूर्वक्षण के लिए अधिसूचित भूमि

क्र. सं.	ग्राम	साधारण संख्या	पटवारी हल्का संख्या	सहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणियाँ
1.	घनपुरी	474	98	सोहागपुर	शाहडोल	142.06	भाग
2.	सरईकापा	940	98	सोहागपुर	शाहडोल	268.910	भाग
3.	अहिरगवा	29	100	सोहागपुर	शाहडोल	30.250	भाग
4.	गोपालपुर	254	100	सोहागपुर	शाहडोल	168.736	भाग
5.	करफटी	72	99	सोहागपुर	शाहडोल	196.529	भाग
6.	देवगवा	458	99	सोहागपुर	शाहडोल	0.530	भाग
7.	सिरौजा	988	99	सोहागपुर	शाहडोल	119.000	भाग
8.	बरतला	676	91	सोहागपुर	शाहडोल	438.635	भाग
9.	नोगवा	536	92	सोहागपुर	शाहडोल	208.648	भाग
10.	खलनाथ	771	92	सोहागपुर	शाहडोल	120.394	भाग

क्र. सं.	ग्राम	साधारण सं.	पट्टाधारी हस्ता सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणियां
11.	छिरिहटी	315	99	मोहागपुर	शहडोल	216.815	भाग
12.	कम्पाटमेंट सं. बुरहुरैज 55 XXIX (पी)		--	--	दक्षिण शाहडोल मंडल	103.730	भाग
13.	कम्पाटमेंट सं. बुरहुरैज 56 XXIX (पी)		--	--	दक्षिण शाहडोल मंडल	133.540	सम्पूर्ण
14.	कम्पाटमेंट सं. बुरहुरैज 57 XVII (पी)		--	--	दक्षिण शाहडोल मंडल	42.080	सम्पूर्ण
15.	कम्पाटमेंट सं. 58 XVIII (पी)	बुरहुरैज	--	--	दक्षिण शाहडोल मंडल	83.760	सम्पूर्ण
16.	कम्पाटमेंट सं. 59 IX (पी)	बुरहुरैज	--	--	दक्षिण शाहडोल मंडल	250.900	सम्पूर्ण
17.	कम्पाटमेंट सं. 60 VII (पी)	बुरहुरैज	--	--	दक्षिण शाहडोल मंडल	107.214	सम्पूर्ण
18.	कम्पाटमेंट सं. 62 XXX	बुरहुरैज	--	--	दक्षिण शाहडोल मंडल	0.500	भाग
कुल क्षेत्र :					2632.431 हेक्टर (लगभग) या 6504.87 एकड़ (लगभग)		

सीमा वर्णन

- क-ख रेखा बिन्दु "क" से शुरुआत होती है और धनपुरी ग्राम से होकर जाती है, नरगारा नाला को पार करती है, फिर सरईकापा और मरफरी ग्रामों से होकर जाती है और बरहुरैज ग्राम में बिन्दु "ख" पर मिलती है।
- ख-ग रेखा करहटी, बेवगां ग्रामों से होकर जाती है और बेवगां ग्राम में बिन्दु "ग" पर मिलती है।
- ग-घ रेखा बेवगां, शिरौजा, छिरिहटी ग्रामों से होकर जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है।
- घ-ङ रेखा बेलहा नाला और छिरिहटी ग्राम की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है, छिरिहटी, खलनाथ और बरहुरैज ग्रामों से होकर जाती है, फिर बरहुरैज, बरहुरैज ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ङ" पर मिलती है।
- ङ-च रेखा बरहुरैज ग्राम से होकर जाती है, बरहुरैज और चित्तुहना, गोपालपुर और चित्तुहना ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और गोपालपुर, महीरगां, धनपुरी, सरईकापा ग्रामों से होकर जाती है और धनपुरी ग्राम में बिन्दु "च" पर मिलती है।
- च-क रेखा धनपुरी ग्राम से होकर जाती है और उसी ग्राम में शुरुआत बिन्दु "क" पर मिलती है।

[पं. 43015/30/85-सी.ए.]

टी.सी.ए. श्रीनिवासन, निदेशक

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 29th January, 1986

S.O. 578 :—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan bearing No. C-1(E) III/ER/702-1085 dated 11th October 1985 of the area covered by this notification can be inspected at the Office of the Western Coalfields Limited (Revenue Section), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001 or at the Office of the Collector, Shahdol (Madhya Pradesh) or at the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Western Coalfields Limited, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001 within ninety days from the date of publication of this notification.

THE SCHEDULE

KARKATI BLOCK

SOHAGPUR COALFIELD

DISTRICT SHAHDOL (MADHYA PRADESH)

(Lands notified for prospecting)

Sl.	Village	General Number	Patwari Halka Number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Dhanpuri	474	98	Sohagpur	Shahdol	142.260	Part
2.	Saraikapa	940	98	Sohagpur	Shahdol	268.910	Part
3.	Ahirkawan	29	100	Sohagpur	Shahdol	30.250	Part
4.	Gopalpur	254	100	Sohagpur	Shahdol	168.736	Part
5.	Karkati	72	99	Sohagpur	Shahdol	196.529	Part
6.	Deogawan	458	99	Sohagpur	Shahdol	0.530	Part
7.	Siraunja	988	99	Sohagpur	Shahdol	119.000	Part
8.	Bartara	676	91	Sohagpur	Shahdol	438.635	Part
9.	Naugawan	536	92	Sohagpur	Shahdol	208.648	Full
10.	Khalnath	771	92	Sohagpur	Shahdol	120.394	Part
11.	Chhirihti	316	99	Sohagpur	Shahdol	216.815	Part
12.	Compartment Number 55 XXIX (P)	Burhar Range	—	—	South Shahdol Division	103.730	Part
13.	Compartment Number 56 XXIX (P)	Burhar Range	—	—	South Shahdol Division	133.540	Full
14.	Compartment Number 57 XVII (P)	Burhar Range	—	—	South Shahdol Division	42.080	Full
15.	Compartment Number 58 XVIII (P)	Burhar Range	—	—	South Shahdol Division	83.760	Full
16.	Compartment Number 59 IX (P)	Burhar Range	—	—	South Shahdol Division	250.900	Full
17.	Compartment Number 60 VII (P)	Burhar Range	—	—	South Shahdol Division	107.214	Part
18.	Compartment Number 62 XXX	Burhar Range	—	—	South Shahdol Division	0.500	Part

Total Area:

2632.431

hectares
(approximately)

or

6504.87
acres
(approximately)

Boundary description:

- A—B** Line starts from point 'A' and passes through village Dhanpuri crosses Nargara Nalla, then proceeds through villages Saraikapa and Karkati and meets in village Karkati at point 'B'.
- B—C** Line passes through villages Karkati, Deogawan and meets in village Deogawan at point 'C'.
- C—D** Line passes through villages Deogawan, Siraunja, Chhirihti and meets at point 'D'.
- D—E** Line passes along the common boundary of Baisaha Nala and village Chhirihti, proceeds through villages Chhirihti, Khalnath and Bartara, then proceeds along the common boundary of villages Chauradih, Bartara and meets at point 'E'.
- E—F** Line passes through village Bartara, proceeds along the common boundary of villages Bartara and Chituhla, Gopalpur and Chituhla, then proceeds through villages Gopalpur, Ahirgawan, Dhanpuri, Saraikapa and meets in village Dhanpuri at point 'F'.
- F—A** Line passes through village Dhanpuri and meets in the same village at starting point 'A'.

[No. 43015/30/85-CA]

T.C.A. SRINIVASAN, Director

परिवहन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1986

शुद्धि-पत्र

का. आ. 579:—इस मंत्रालय की दिनांक 17 दिसम्बर, 1985 की अधिसूचना सं. ई-11011/4/85-हिन्दी में पैरा-II भारतीय होटल निगम लिमिटेड के अंतर्गत क्रम सं. 2 पर "सेंटार होटल, बम्बई" के स्थान पर, "भारतीय होटल निगम लिमिटेड, बम्बई" पढ़ा जाए।

[संख्या ई-11011/4/85-हिन्दी]

कृष्ण कुमार शर्मा, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Civil Aviation)

New Delhi, the 24th January, 1986

CORRIGENDUM

S.O. 579.—In this Ministry's notification No. E. 11011/4/85-Hindi dated 17th December, 1985 in para II under Hotel Corporation of India Ltd., at Sl. No. 2 please read "Hotel Corporation of India Ltd., Bombay" instead of "The Centaur Hotel, Bombay".

[No. E. 11011/4/85-Hindi]

K. K. SHARMA, Senior Hindi Officer

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(युवा कार्यक्रम और खेल विभाग)

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1986

का. आ. 580:—इस विभाग की दिनांक 13 जून, 1983 की तथा-संशोधित समसंख्यक अधिसूचना का एतद्वारा निम्नानुसार आंशिक तौर पर और संशोधन किया गया है:—

सदस्यों की सूची के क्रम संख्या 3 में वित्तीय सलाहकार, खेल विभाग के स्थान पर "वित्तीय सलाहकार, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग—श्री एस. बालाचन्द्रन" प्रतिस्थापित किया जाए।

[संख्या एफ. 13-1/81-डी-1(एस.पी.)]

ए. भट्टाचार्य, उप सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Youth Affairs and Sports)

New Delhi, 23rd January, 1986

S.O. 580.—This Department's notification of even no. dated 13th June, 1983 as modified is hereby further partially modified as follow:

In the list of members at sl. no. 3, Financial Advisor Department of Sports may be substituted by "Financial Adviser, Deptt. of Youth Affairs and Sports—Shri S. Balachandran".

[No. F. 13-1/81-D.I.(SP)]

A. BHATTACHARYYA, Dy. Secy.

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1986

कां.आ. 581:—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने अलंगानलूर टेलीफोन केन्द्र, तमिलनाडु में दिनांक 16-2-1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-7/86-पी०एच०बी०]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunication)

New Delhi, the 24th January, 1986

S.O. 581.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.S. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General Department of Telecommunication, hereby specifies 16-2-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Alanganallur Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-7/86-PHB]

कां.आ. 582:—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने अलंगानलूर तथा कालकण्डी टेलीफोन केन्द्रों, केरल में दिनांक 16-2-1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-8/86-पी०एच०बी०]

S.O. 582.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunication, hereby specifies 16-2-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Alanallur & Kalkandi Telephone Exchange, Kerala Circle.

[No. 5-8/86-PHB]

का. आ. 583:—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महादेशक, दूरसंचार विभाग ने सीरिसिल्लि टेलीफोन केन्द्र, आन्ध्र प्रदेश, में दिनांक 16-2-1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-9/86-पी.एच.बी.]

S.O. 583.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunication, hereby specifies 16-2-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Sircilla Telephone Exchange, Andhra Pradesh Circle.

[No. 5-9/86-PHB]

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1986

का. आ. 584:—स्थायी आदेश सं. 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महादेशक, दूरसंचार विभाग ने कोरिकादावू टेलीफोन केन्द्र, तमिलनाडू में दिनांक 16-2-86 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-11/86 - पी.एच.बी.]

New Delhi, the 30th January, 1986

S.O. 584.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunication, hereby specifies 16-2-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in KORIKADAVU Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-11/86-PHB]

का. आ. 585:—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महादेशक, दूरसंचार विभाग ने वल्लिजाबाद टेलीफोन केन्द्र, तमिलनाडू में दिनांक 16-2-1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-12/86- पी.एच.बी.]

S.O. 585.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunication, hereby specifies 16-2-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in WALAJABAD Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-12/86-PHB]

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1986

का. आ. 586:—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महादेशक, दूरसंचार विभाग ने कल्लूरानी टेलीफोन केन्द्र, तमिलनाडू में दिनांक 20-2-1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-15/86-पी.एच.बी.]

New Delhi, the 6th February, 1986

S.O. 586.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunication, hereby specifies 20-2-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Kalloorani Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-15/86-PHB]

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1986

का. आ. 587:—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महादेशक, दूरसंचार विभाग ने कदायाम टेलीफोन केन्द्र, तमिलनाडू में दिनांक 21-2-1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-17/86-पी.एच.बी.]

New Delhi, the 7th February, 1986

S.O. 587.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunication, hereby specifies 21-2-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Kadayam Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-17/86-PHB]

का. आ. 588:—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महादेशक, दूरसंचार विभाग ने गंडमनाइकानुर टेलीफोन केन्द्र, तमिलनाडू दिनांक 21-2-1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-18/86-पी.एच.बी.]

के. पी. शर्मा, सहायक महादेशक (पी.एच.बी.)

S.O. 588.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunication, hereby specifies 21-2-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Gandamauaickanur Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-18/86-PHB]

K. P. SHARMA, Assistant Director General (PHB)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1986

का. प्रा. 589.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सैमर्स राजेन्द्रा रोलिंग्स, डोर नं. 10-3-98 बी, मोरामपुदी रोड, राजामुंदर (आ. प्र.) नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[स. एम.-35019 (481)/85-एम. एम.-2]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 29th January, 1986

S.O. 589.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rajendra Rollings, Door No. 10.3.98 B, Morampudi Road, Rajahmundry, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[S-35019(481)]85-SS-II]

का. प्रा. 590.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सैमर्स श्री वेकटाणवरा राइस दाल एण्ड गिनिनिंग मिल, कुसीचेदन दामी तहसील, प्राकशम, कम्बा, आन्ध्र प्रदेश नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एम.-35019 (482)/85 एम. एम.-2]

S.O. 590.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Venkateswara Rice Dall and Ginning Mill, Kurichedu Dassi, (TQ), Prakasham, Dist. Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[S-35019(482)]85(SS-II)]

का. प्रा. 591.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सैमर्स इंटर सोड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, इंडस्ट्रियल इस्टेट मराजपुर निजामाबाद आ. प्रदेश और इसकी-8 रेडडी होस्टल काम्प्लैक्स निजम रोड, एडिज़म हैदराबाद-1 में स्थित शाखा नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एम.-35019 (483)/85 एम. एम.-2]

S.O. 591.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Indur Seed Company Private Limited, Industrial Estate, Sarangapur Nizamabad, Andhra Pradesh including its branch at 8-Reddy Hostel Complex, Tilak Road, Abids, Hyderabad-1, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[S-35019(483)]85-SS-II]

का. प्रा. 592.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सैमर्स बेंकटणवरा लेमिनेशन एण्ड प्रैसिंग प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नं. 3, आई डी ए. बालानगर, हैदराबाद-500037, आ. प्र. नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एम.-35019 (484)/85 एम. एम.-2]

S.O. 592.—Whereas appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Venkateswara Laminations and Pressing Private Limited Plot No. 3 I.D.A., Balanagar, Hyderabad-500037, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[S-35019(484)]85-SS-II]

का. प्रा. 593.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सैमर्स बा. सतीश कुमार एण्ड कम्पनी सर्वेन्ट्स एण्ड कमीशन एजेंट XVIII/141 टी. जी. रोड एडोनी-518301 आन्ध्र प्रदेश नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एम.-35019 (485)/85 एम. एम.-2]

S.O. 593.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs V. Satish Kumar and Company, Merchants and Commission Agents XVIII/141, T.G.L. Road Adoni-518301, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[S-35019(485)]85-SS II]

का. आ. 594.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स टेक्निकी, पो. बॉक्स नं. 4800 महादेवापुरा पोस्ट व्हाइट फील्ड रोड, बंगलूर-48 और इसका 150/7 अपर पाइप लाइन, शेसादरीपुरम, बंगलूर-20 में स्थित कार्यालय नामक स्थापन के संबंध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एम.-35019 (486)/85 एम. एम.-2]

S.O. 594.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Tecnico, Post Box No 4800, Mahadevapura Post, Whitefield Road, Bangalore-48 including its office at 150/7, Upper Pipe Line Sheshadripuram, Bangalore-20, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[S-35019(486)]85-SS-II]

का. आ. 595.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स चन्द्रशेखर स्वामीजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी. एम. ए. ई. सोमाईटी, हराफनाहाली, बेलारी कस्बा-583131 नामक स्थापन के संबंध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एम.-35019 (487)/85 एम. एम.-2]

S.O. 595.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Chandrashekar Swamiji College of Pharmacy, TMAE Society, Harapanahally, Bellary Dist.-583131, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[S-35019(487)]85-SS II]

का. आ. 596.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राजमने सर्विस व्हाइट फील्ड रोड, महादेवापुरा पोस्ट बंगलूर-560048 नामक स्थापन के संबंध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एम.-35019 (488)/85 एम. एम.-2]

S.O. 596.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Rajamane Services, White Field Road, Mahadevapura Post, Bangalore-560048, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[S-35019(488)]85-SS-II]

का. आ. 597.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्रीवल्लभ हुड्डी, व्हाइटफील्ड (पोस्ट) सदरामंगला (गांव) बंगलूर-66 और इसकी 150/7, अपर पाइप लाइन, शेसादरीपुरम, बंगलूर-20 में स्थित शाखा नामक स्थापन के संबंध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एम.-35019 (489)/85-एम.एम.-2]

S.O. 597.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sriplas, Hoody, Whitefield (Post) Sadaramangala (Village) Bangalore-66, including its branch at 150/7, Upper Pipe Line Sheshadripuram, Bangalore-20, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[S-35019(489)]85-SS-II]

का. आ. 598.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स व्हाइट फील्ड एण्ड स्ट्रीट्स, पो. बा. नं. 4800, महादेवापुरा पोस्ट व्हाइट फील्ड रोड, बंगलूर-48, और इसकी 41-43, गिरीने रोड, बंगलूर-1 में स्थित शाखा नामक स्थापन के संबंध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एम.-35019 (490)/85-एम.एम.-2]

S.O. 598.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Whitefield Industries P.B. No. 4800, Mahadevapura Post, Whitefield Road, Bangalore-48 including its office at 41-43, Levelle Road, Bangalore-1, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[S-35019(490)]/85-SS-II]

का. प्रा. 598.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स व्हाइटफील्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड नं. 2, पांचवी क्रॉस एच सिद्धा रोड, बंगलूर-37 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संक्रा. एम-35019(491)/85-एम.एस.-2]

S.O. 599.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Electro Chemical Metal Finishes No. 2, 5th Cross H. Siddiah Road, Bangalore-27, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[S-35019(491)]/85-SS-II]

का. प्रा. 600.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डी. पी. ट्विस्टिंग वर्क्स प्राइवेट लि. नं. 67-68, जवाहर रोड, नं. 1, उद्योग नगर, उधना, डिस्ट्रिक्ट सुरत नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एम-35019(514)/85-एम.एस.-3]

S.O. 600.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs D. P. Twisting Works, Plot No. B-67-68 Jawahar Road No. 4 Udyog Nagar, Udhna, Dist. Surat, have agreed that the Provision of the Employees' Provident Funds and Misc. Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[S-35019(514)]/85-SS-II]

का. प्रा. 601.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री सीत्था रामा कंसर्न्स (राइस मिल) मंडापेटा 535-308 ई. जा. कम्परा आन्ध्र प्रदेश प्रांत नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एम-35019(516)/85-एम.एस.-II]

S.O. 601.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Seetha Rama Concerns (Rice Mills) Manadapeta-533308 E.G. District, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[S-35019(516)]/85-SS-II]

का. प्रा. 602.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आरुबिन्दो पब्लिक स्कूल, 33, सलाई रोड, त्रिची-3 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एम-35019(517)/85-एम.एस.-2]

S.O. 602.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Aurobindo Public School 33, Salai Road, Trichy, have agreed that the Provision of the Employees' Provident Funds and Misc. Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[S-35019(517)]/85-SS-II]

का. प्रा. 603.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हनुमन्ट शिवा लिमिटेड, बॉल-102, कम-8, मोहान्नी (पंजाब) नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एम-35019(520)/85-एम.एस.-II]

S.O. 603.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Incomnet India Limited, B-162/Phase VIII, Mohali (Punjab), have agreed that the Provision of the Employees' Provident Funds and Misc. Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[S-35019(520)/85-SS-II]

का. आ. 604.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स के.पी. शारंग प्रोडक्ट्स 12, गाईडको इंडस्ट्रियल स्टेट, हुसर, धर्मापुरी, डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारियों भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[स. एम.-35019(526)/85-एम.एस.-2]

S.O. 604.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs K.P. Wire Products, 12, Sidco Industrial Estate, Hosur Dharmapuri, District, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[S-35019(526)/85-SS-II]

का. आ. 605.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स युनिसेल इण्डस्ट्रीज 37/41, शांतिदास गांधी मार्ग, देवीकरन मैसन (प्रिन्स स्ट्रीट) बम्बई-2 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारियों भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है;

[स. एम.-35019(30)/85-एम.एस.-2]

S.O. 605.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Uniseal Industries, 37/41, Shantidas Gandhi Marg, Devkaran Mansion, (Princess Street), Bombay-2 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(30)/85-SS-II]

का. आ. 606.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि म्यूथु गिंट इंडस्ट्रियल मार्फ्टको प्लाट नं. डी-9 इंडस्ट्रियल इस्टेट, थोप्पु, या मद्रास-625006 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारियों भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एम-35019(56)/86-एम.एस.-2]

S.O. 606.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Mutha Paint Industries Pvt. Ltd., Sidco Plot No. D-9, Industrial Estate, Thoppu, P.O. Madurai-625006 have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(56)/86-SS-II]

का. आ. 607.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि अलम एण्ड एलाईड कैमिकल्स प्रा. लि. ए-1, शक्ति को-ओप, इंडस्ट्रियल इस्टेट, पोलाची -642003, तमिलनाडु नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारियों भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एम-35019(57)/86-एम.एस.-2]

S.O. 607.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Alum and Allied Chemicals Pvt. Ltd., A-1, Sukthi Co-op. Industrial Estate, Pollachi-642003, Tamil Nadu have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(57)/86-SS-II]

का. आ. 608.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रबड़ इन्जीनियर्स एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड 234, जे.ए. रोड, मिरामपुर, हुबली और 1-पा, प्रभुन पतेत कलकत्ता-1 स्थित हैड ऑफिस नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारियों भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[स. एम.-35017(107)/85-एम.एस.-2]

S.O. 608.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Rubber Equipment and Engineering Co. (P) Ltd. 234, G.T. Road, Serampore, Hooghly including its Head Office at 4-C, Garstin Place, Calcutta-1 have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(107)|85-SS-II]

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1986

का. प्रा. 609:—केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (क) के अनुसरण में श्री टी. अंजैया के स्थान पर श्री पी. ए. संगमा, श्रम राज्य मंत्री को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है ;

अतः, जब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.प्रा. 545 (अ), दिनांक 25 जुलाई, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, “(केन्द्र सरकार द्वारा धारा 4 के खण्ड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट)” शीर्षक के नीचे मद 1 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

श्री पी. ए. संगमा,
श्रम राज्य मंत्री,
श्रम मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली ।

[संख्या यू. 16012/1/86-एस.एस. 1]

New Delhi, the 30th January, 1986

S.O. 609.—Whereas the Central Government has, in pursuance of clause (a) of Section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri P. A. Sangma, Minister of State in the Ministry of Labour as Chairman of the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri T. Anjaiah ;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 545 (E), dated the 25th July, 1985, namely :—

In the said notification, under the heading “(Nominated by the Central Government under clause (a) of section 4)”, for the entry against Serial Number 1, the following entry shall be substituted, namely :—

Shri P. A. Sangma,
Minister of State
in the Ministry of Labour,
Government of India,
New Delhi.

[No. U-16012/1/86 SS-II]

का.प्रा. 610.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैमर्स इंडियन रेयर अर्थस लि., उद्योग मंडल, केरल के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के

प्रवर्तन से 1 अक्टूबर, 1985 से 30 गितम्बर, 1986 तक की जिसमें यह लागू भी सम्मिलित है, की अवधि के लिये छूट देती है ।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्:—

- (1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्जित किये जायेंगे ;
- (2) इस छूट के होने हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसूचिणाएं प्राप्त करने रहेंगे, जिनको पाने के लिये वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदेस अभिवायों के आधार पर हकदार हो जाते ;
- (3) छूट प्राप्त अवधि के लिये यदि कोई अभिदाय पहले ही संवेत किये जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किये जायेंगे ;
- (4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इस में इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्रकृत में और ऐसी विशिष्टियां सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ;
- (5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदाधिकारी,—

- (1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को मर्यापित करने के प्रयोजनों के लिये, या
- (2) यह अभिलिखित करने के प्रयोजनों के लिये कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिये रखे गये थे या नहीं, या
- (3) यह अभिलिखित करने के प्रयोजनों के लिये कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसूचिणाओं को, जो ऐसी प्रसूचिणाएं हैं जिनके प्रतिकृतिस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, तैयार और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या
- (4) यह अभिलिखित करने के प्रयोजनों के लिये कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उद्देश्यों का का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिये मशकत होगा,—

- (क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
- (ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिनियम में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उनके भारमायक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखावहियां और अन्य दस्तावेजों, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
- (ग) प्रधान नियोजन या अव्यवहित नियोजक की, उनके अधिकारी या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदाधिकारी के पास यह

विष्वाङ्क करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[सं-एस-38014/3/84-एस एस -1]

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में छूट की भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदनपत्र पर कार्यवाही करने में समय लगा था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट की भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 610.—In exercise of the powers conferred by Section 88 read with Section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the regular employees of M/s. Indian Rare Earths Ltd., Udyogmandal, Kerala from the operation of the said Act for a period of one year with effect from 1st October, 1985 upto and inclusive of the 30th September, 1986.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

- (1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates ;
- (3) The contribution for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;
- (4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;
- (5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—
 - (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or
 - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
 - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or
 - (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory,

be empowered to—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate

employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

- (d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[File No. S-38014/3/84-SS-II]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not effect the interest of anybody adversely.

का० प्रा० 611.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पशुली फरवरी, 1986 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध बिहार राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

- (1) बोकारो औद्योगिक क्षेत्र की सीमाओं में आने वाले क्षेत्र, किन्तु उन क्षेत्रों को छोड़कर जहाँ मीतर्स बोकारो इस्पात लिमिटेड के एकक स्थित हैं, और

- (2) राजस्व थाना, जरीडीह, जिला धनबाद में मारफारी (16), गोरावाली (14), सिमबाबर (25), नारकारा (25) और नाकारा (26) के राजस्व ग्राम।

[सं एस-38013/1/86-एस एस -1]

S.O. 611.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st February, 1986 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Bihar, namely :—

- (i) area within the limits of Bokaro Industrial area but excluding the areas wherein the units of M/s. Bokaro Steel Limited are situated ; and

- (ii) revenue villages of Marafari (16), Gorawali (14), Simbabar (25), Narkara (25) and Nakara (26) in revenue thana Jaridih in district Dhanbad.

[No. S-38013/1/86-SS-II]

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1986

का० प्रा० 612.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मीतर्स नाकारा लॉरी यूरीमेयनारसंग संगम, सेलम में रोड संनकारी-837301 समिलताहू और इसकी (1) 1-6-15 की 4 सेलम में रोड (2) 1-6-15-की-5 सेलम में रोड और (3) प्रकामपेटाई संनकारी में स्थित शाबाएँ। नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी अधिनियम विधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस.-35019(58)/86-एस.एस.-2]

New Delhi, the 31st January, 1986

S.O. 612.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Sankari Lorry Urimaiyalargal Sangam, Salem Main Road, Sankari-637301, Tamil Nadu including its Branches at (1) 1-6-15B.4 Salem Main Road, (2) 1-6-15B.5 Salem Main Road and (3) Akkanai-pettai Sankari have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(58)/86-SS-II]

का. भा. 613.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इन्स्ट्रुमेंट इनोवेशन्स 48/49 चिंदमणि विनयगार कोयल स्ट्रीट, मद्रास-60008 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस.-35019(59)/86-एस.एस.-2]

S.O. 613.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Instrument Innovations 48/49, Chindamani Vinayagar Koil Street, Madras-600087 have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(59)/86-SS-II]

का. भा. 614.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री श्रीनिवासा कलेंडरिंग मिल, 30-पी वीरापथरा चेट्टी स्ट्रीट इरोड-638001 तमिलनाडु नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस.-35019(60)/86-एस.एस.-2]

S.O. 614.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Sri Srinivasa Calendering Mill, 30-P, Veerapathra Chetty Street Erode-638001 Tamil Nadu have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(60)/86-SS-II]

का. भा. 615.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स के. एस. वैयापुरी बक्तर एण्ड सन्स चिन्नामनली स्ट्रीट इडापडी-637101 रोयल कस्बा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा- (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस.-35019(61)/86-एस.एस.-2]

S.O. 615.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs K. S. Vaipuri Bakhtar and Sons, Chinnamanali Street, Idappadi-637101 Salem Dt. Madras have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(61)/86-SS-II]

का. भा. 616.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मधेश्वर कलेंडरिंग मिल, 34-सी, 7 कावेरी रोड विरापन्थातरम इरोड-638004 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(62)/86-एस.एस.-2]

S.O. 616.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Madheshwar Calendering Mills 34-C, 7 Canvery Road, Veerappancharam Erode-638004 have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(62)/86-SS-II]

का. भा. 617 :—मैसर्स इण्डियन एक्सप्रेस (मदुराई) प्रा. लि. कालवटी कालीन-682001 (के. आर/3220) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 19 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के नियमित कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहवृद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपावृद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम का सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक निधि आयुक्त, केरला को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आवि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमानित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वास्तव आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उल्लेख फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उल्लेख फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेद्य रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संवेद्य होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिनी की प्रतिस्वर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, केरला के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तयुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिस स्थापन पहले अपना भूका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी राशि से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारिख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा द्वारा नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की वशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितया या विधिक वारिसों की जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितयों/विधिक वारिसों का बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस-35015(336)/65-एस.एस.-2]

S.O. 617.—Whereas Messrs. Indian Express (Madurai) Pvt. Limited Calvetty, Cochin-682001 (K.K/5220) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Kerala maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer

of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Funds or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Kerala and where any amendment is likely to exert adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(336)/85-SS-II]

का. आ. 618 :—दि मंगलौर कैथोलिक को. प्रा. बेंक लि. सेंट अलुयासिस कालेज रोड, हैम्पनकेटा मंगलौर (के.एन/6480) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम

के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी भिक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूत हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपलब्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक निधि आयुक्त, मंगलौर को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमानित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुबाव, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थान में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वास्तव आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेद्य रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामानिर्देशी को प्रतकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मंगलौर के पूर्व अनुरोधन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक

भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना घुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत वश में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्दार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दश में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर निश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(337)/85-एस.एस-2]

S.O. 618.—Whereas Messrs. The Mangalore Catholic Co-operative Bank, Limited, St. Aloysius College Road, Hampamkatta, Mangalore (K.N/6480) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Mangalore maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Mangalore and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(337)/85-SS-II]

का. आ. 619 :—दि विजयवाड़ा को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लि. विजयवाड़ा, जिला फिण्डा, (आन्ध्रा प्रदेश (ए. पी./2364) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो

कर्मचारी निधेय सहवृद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इतकी पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अन्तर्गत है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपावृद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उप-बन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुन्टूर को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभागों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वास्तविक अवस्था प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दर्भ करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिनी की प्रतिकर के रूप में दोनों दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुन्टूर के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत वशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हुकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014(338)/85-एस. एस.-2]

S.O. 619.—Whereas Messrs. The Vijayavada Co-operative Central Bank Limited, Vijayavada Krishna District, (Andhra Pradesh) (AP/2364) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Guntur maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an

establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Guntur and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(338)/88-SSII]

का. आ. 620 :- कालसा पम्पम प्रा. लि. 173. जी. आई. डी. सी. एस्टेट नरोदा, अहमदाबाद (जी.जे. 6438) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक सकारण हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहवृद्ध बीमा स्कीम, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें प्राप्त हो सकते हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रख जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तथा उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वास्तव आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनजमे हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संश्लेष्य रकम उस रकम से कम हो जो कर्मचारी को उस दशा में संश्लेष्य होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशित की प्रतिफल के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययक्त हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सन्नि-
विष्ट करेगा।

[मंजूरा एस-35014/339/85-एस:एस 2]

S.O. 620.—Whereas Messrs. Calama Pumps Private Limited, 173, G.I.D.C. Estate, Naroda, Ahmedabad (GJ/6438) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under Clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees

under the said Scheme are enhanced, so that benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Funds Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014 (339)/85-SS-II]

का. आ. 621 :—मैसर्स कालामा औरज लिमिटेड डा. लौलानी, जिला किर्णोजार, उड़ीसा (ओ आर/80) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबुब बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुजय है।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपादक अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों को प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उड़ीसा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे

लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केंद्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभागों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बात का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाह्य आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उड़ीसा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का गतिव्यक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना रकबा है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत की दशा में, उन मत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस. 35014(2)/86-एस एस.-2]

S.O. 621.—Whereas Messrs. Bolani Ores Limited, P.O. Bolani, District-Keonjhar, Orissa (OR/80) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Orissa maintain such accounts and provides such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme immediately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Guntur and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(2)/86-SS-II]

का. आ. 622 :—मैसर्स बीडिया (इंडिया) लिमिटेड, 8/9 माहल, तमकर रोड, पी. वी. नं. 7300 बंगलौर-73) (के एन/4062) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी एकक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनकल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप संहिता बीमा स्कीम, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3337 तारीख 27-8-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 18-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 17-9-88 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसी लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के सण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रसारण में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अन्वाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सम्मिलित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संवेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिनी की प्रतिफल के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युकृत्युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम के दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशिनी या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती

तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशित/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्वाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण वादे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014(121)/81-एस. एस.-21]

S.O. 622.—Whereas Messrs Widia (India) Limited, 8/9th Mile Tumkur Road, P.B. No. 7300, Bangalore-73 (KN/4063) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3337 dated the 27-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-9-1985 upto and inclusive of the 17-9-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/121/81-PF. II (SS. II)]

का. आ. 623—मैसर्स दूरवाणी केबल्स प्राइवेट लिमिटेड, मारुथी मेशन, तीसरी मंजिल, 19/7, कन्नियम रोड, बंगलूर-560052 (के एन/4661) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4078, तारीख 12-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 4-12-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 3-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे मंला रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभागों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद सस्थान के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जानी की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदस्य रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदाय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता था, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आगत, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम में, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पॉलिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकर की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशित/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एम-35014/244/82-पी. एफ.-2 (एस. एस.-2)]

S.O. 623.--Whereas Messrs Doorvani Cables Private Ltd., Maruthi Mansion, 3rd Floor-19/7, Cunningham Road, Bangalore-52, (K.N/4661) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4876 dated 12-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 4-12-1985 upto and inclusive of the 3-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under

the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/244/82-PF. II (SS. II)]

का. आ. 624 :-संसर्ग दिल्ली क्लोथ एण्ड जनरल मिल्स कं. लिमिटेड, बाड़ा हिन्दू राब, दिल्ली-110006 (डी एल/2294) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों का उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निधेय सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4255 तारीख 26-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 18-12-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 17-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे

लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदायों आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रतय तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम पुराने दर्ज करेगा और उसकी बाह्य आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिसे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देश्य होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिनी को प्रतिफल के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन वने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यत्नियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निश्चित तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में

असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिक्रम के दशा में, उन मृत सदस्यों के नामान्वेशिती या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निवेशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/253/82-एस. एस-2/पी. एफ-2]

New Delhi, the 3rd January, 1986

S.O. 624.—Whereas Messrs The Delhi Cloth and General Mills Company Limited, Bara Hindu Rao, Delhi-110006 (DL/2294) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4255 dated the 26-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-12-1985 upto and inclusive of 17-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under

the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/253/82-PF. II (SS. II)]

का. जा. 625 :—मैसर्स एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड पी. ओ. ओखला इण्डस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110020 (डी एन/127) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुभूत है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. जा. 3936 तारीख 6-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपादध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 27-11-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 20-11-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसे विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तर्गण, निरीक्षण प्रभागों-संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी दायित्व आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्वत करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उप-लब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में स्मृति रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेद्य रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संवेद्य होती, अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के वैधिक वारिस/नामनिर्देशिनी की प्रतिफल के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का योज्यव्यक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो वह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत सारणी के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में

असफल रहता है, और पालिसी का व्ययगत हो जाना दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या वैधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिनी/वैधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति में एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/(441)/82-एस. एस-2/पी. एफ.-2]

S.O. 625.—Whereas Messrs The Associated Cement Companies Limited, P.O. Okhla Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110020 (DL/127) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3936 dated the 6th November, 1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 27th November, 1985 upto and inclusive of the 26th November, 1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S: 35014/441/82-PF. II (SS. II)]

का. आ. 626 :—मैसर्स ग्रेफाइट इंडिया लि. विप्लवश्रियरिवा इन्डस्ट्रियल एरिया हवाइट फील्ड रोड, बंगलूर-560048 (कर्नाटक/5305) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनशेष हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 900 तारीख 21-12-1982 के अन्तर्गण में और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 12-2-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 11-2-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी गतिविधियां प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के सण्ड (25) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का दहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के स्वस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी डाकन आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मन्दत करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेष हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में मन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधि वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का गतिव्यक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में

संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों की जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशित/विधिक वारिसों को उक्त राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एम-35014(450)/82-पीएफ. -2(एस.एस. 2)]

S.O. 626.—Whereas Messrs Graphic India Limited, Visvesvaraya Industrial Area, White Field Road, Bangalore-560048 (K-N/5305) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 900 dated the 21st December, 1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 12th February, 1986 upto and inclusive of the 11th February, 1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

1493 GI185-7

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium, the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/450/82-PF II (SS. II)]

का. आ. 627.—ससन टैक्सटाइल लिमिटेड लि. पो. बाक्स नं. 288, बड़ौदा (गजरात/4578) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थान कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रवर्धन जलनस्थ अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की भाग 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थान के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक उत्कृष्ट हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहवृद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की भाग 17 की उपधारा धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती है और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 627 तारीख 23-12-1982 के अन्तर्गत में और इससे उपरबद्ध कर्मचारी में विनिर्दिष्ट शक्तियों के अधीन रहते हुए, उक्त स्कीम को, 12-2-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 11-2-1986 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उद्देश्यों के पश्चात् से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियाँ भेजेंगी और ऐसे लेखा रखेंगी तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेंगी जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेंगे जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभागों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेंगे।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थान में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेंगे और उसकी वांछित आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्तुष्ट करेंगे।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समूचित रूप में वृद्धि किये जाने के व्यवस्था करेंगे जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस वंश में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिवत वारिस/नाम निर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेंगे।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने में पूर्ण कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का ग्विनयुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चंका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी गति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा

निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए निम्नी व्ययिष्ठम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिवत वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशित/विधिवत वारिसों को उस राशि का संदाय करेगा और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. 35014(457)/82-पी.एफ.-2(एस.एस.2)]

S.O. 627.—Whereas Messrs Sussav Textiles Bearings Limited, P.B. No. 286, Baroda-390001 (GJ/4578) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 917 dated the 23rd December, 1982 and subject to conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 12th February, 1986 upto and inclusive of the 11th February, 1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/457/82-PF. II (SS. II)]

का. आ. 628.—संसर्ग मध्य प्रदेश राज्य एगो इन्डस्ट्रीज डिवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 3 मंजिल, पंचानन, मालवीय नगर, भोपाल (मध्य प्रदेश/1636) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केंद्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निधि सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञ है ;

अतः केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 906 तारीख 21-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 12-2-1986 में तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 11-2-89 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखाता तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केंद्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के रूप में (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थान में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वास्तव आवश्यकता प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्तुष्ट करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि किये जाने के व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन फायदे उन फायदों में अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञ है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस वृत्ति में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिनी वगैरे प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसमें स्थापन पहले अपना चका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी गति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी करणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उका स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदा के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशित/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय करता है और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(360)/82-पी.एफ. 2(एस.एस. 2)]

S.O. 628.—Whereas Messrs Madhya Pradesh State Agro-Industries Development Corporation Limited, 3rd Floor, Panchanan, Malaviya Nagar, Bhopal-3 (MP/1636) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 906 dated the 21-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 12th February, 1986 upto and inclusive of the 11th February, 1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in

his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/360/82-PF. II (SS. II)]

का. आ. 629.—मंसर्स डेली कॉलेज, इन्दौर (मध्य प्रदेश) (एम. पी./3973) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 915 तारीख 23-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 12-2-88 से तीन वर्ष की अवधि के लिए, जिसमें 11-2-89 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केंद्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध समुचित रूप से वृद्धि की जाति की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदाय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दश में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन को कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिस स्थापन पहले अपना चूका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत दश में, उन मूल सदस्यों के नाम निर्देशितियां या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिनी/विधिक वारिसों को उक्त राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दश में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014(463)/82-पी.एफ.-2 (एस. एस-2)]

S.O. 629.—Whereas Messrs The Daly College, Indore (MP) (MP/3973) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 915 dated the 23-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 12-2-1986 upto and inclusive of the 11-2-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him

as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme: appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/463/82-PF.II(SS.II)]

का. आ. 630 :—मैसर्स-सुसन टैक्सटाइल बियरिंग लिमिटेड पो. बॉक्स नं. 288 बड़ौदा-39000 (गुजरात/4808) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 914 तारीख 23-12-1982 के अनुसारण में और इससे उपा बद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शक्तों के अधीन रहते हुए, उक्त

स्थापन को, 12-2-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 11-2-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणों भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का उत्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद संस्थान के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहलें ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंजूर करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उरु रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विविध वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उक्त सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह खुद की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पानिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी ध्येतिपूर्ण की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकर्ता राशि के हकदार नाम निर्देशित/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के मार्ग के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014 (460)/82-पी. एफ-2 (एस.एम.-2)।

S.O. 630.—Whereas Messrs Sussan Textiles Bearing Limited, P.B. No. 288, Baroda-300001 (GI/4808) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A), of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 914 dated the 23-12-82 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 12-2-1986 upto and inclusive of the 11-2-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in

his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund, Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of insurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/460/82-PF. II(SS.II)]

का. आ. 631 :—मैसर्स भारत फोर्ज कम्पनी लिमिटेड, मुन्धरा एन-411001 (एस. एच./8004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिलाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुभूत हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 744 तारीख 18-12-1982 के अन्वय में और इससे उदाहरण अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त

इससे उपावध अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 29-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 28-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देनी है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रक्केगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभागों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की दहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वास्तव आदर्शक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सम्मिलित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अन्कल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अन्वये हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन मन्वेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में मन्वेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का गन्विष्यक अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उन

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति में कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पानिसी व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि, यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिनी/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[मं. एस-35014(368)/82-एफ-2 (एम एस-2)]

S.O. 631.—Whereas Messrs Bharat Forge Company Limited, Mundhava, Pune-411001 (MH/8004) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Emp-India in the nature of life insurance which are more 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act)

And whereas, the Central Government is satisfied that sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 744 dated the 18th December, 1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 29-1-1986 upto and inclusive of the 28-1-1989.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 744 dated the 18-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 29-1-1986 upto and inclusive of the 28-1-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S.35014/368/82-PF.II(SS.II)]

का. आ. 632 :—मैसर्स एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, किस्तना सीमेंट वर्क्स, पिन कोड-522502 गुण्टूर जिला, आन्ध्र प्रदेश (ए पी/9) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जं उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

1493 GI185—8

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3933 तारीख 6-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपायद्व अन्तःसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को 27-11-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 26-11-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अन्तःसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजन कय जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वाचन आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्तुष्ट करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उप-बन्ध फायदे दोगुण जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपबन्ध फायदों में सम्मिलित रूप से वर्द्ध की जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिवक वारिस/नाम-निर्देशित को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यत्नयुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे

स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशित/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्रवृत्ति के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014(387)/82-एस. एस.-2]

ए. के. भट्टराई, अवर सचिव

S.O. 632.—Whereas Messrs The Associated Cement Companies Ltd., Kistna Cement Works, PIN Code 522502, Guntur District, Andhra Pradesh (AP/9) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3933 dated the 6-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 27-11-1985 upto and inclusive of the 26-11-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient

features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/387/82-PF. II(SS. II)]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1986

का. प्रा. 633.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, सेंट्रल कोलफील्ड लि. की कुजु कोलियरी के प्रबंधन में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण में, 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-1-1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 30th January, 1986

S.O. 633.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No 2, Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kuju Colliery of M/s. Central Coal-

fields Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 21st January, 1986.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 9 of 1983

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kuju Colliery of Central Coalfields Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri R. S. Murthy, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri S. Bose, Secretary R.C.M.S. Union

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dated, Dhanbad, the 15th January, 1986

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012(288)/82-D.III(a), dated the 12th January, 1983.

SCHEDULE

"Whether the management of Kuju Colliery of Messrs Central Coalfields Limited, Post Office Kuju, District Hazaribagh are justified in terminating the services of Shri Gopal Prasad, Pump Khalasi with effect from 2nd September, 1981? If not, to what relief is the workman concerned entitled and from which date?"

The case of the workmen is that the concerned workman Shri Gopal Prasad was a permanent employee of Kuju Colliery of M/s. CC Ltd. He had worked as Pump Khalasi for over 10 years prior to his illegal termination by the management. The concerned workman had gone on leave with effect from 22-12-80. During the leave he had gone to his village home where he became indisposed and was treated locally. The concerned workman duly intimated the management at Kuju regarding his inability to report for duty due to his illness. The management did not send any communication to the concerned workman intimating the refusal of his petition for leave. The concerned workman received a charge sheet to which he replied. Thereafter the management remained silent. While the workman was still sick, he received a letter dated 2-9-81 by post intimating that his services have been terminated by the management. On receiving the letter of termination of his services the concerned workman went to Kuju colliery with medical certificate and reported personally to the Manager of Kuju Colliery and asked for permission to resume his duties but he was not allowed to resume his duties. The union of the workmen also took up the matter of the concerned workman with the management but to no avail. Thereafter the union of the workmen raised an industrial dispute before the ALC(C) Hazaribagh which held a conciliation proceeding but the conciliation ended in failure and thereafter on a report of failure of the conciliation the appropriate Government referred the dispute for adjudication to this Tribunal. It is submitted on behalf of the concerned workman that the action of the management in terminating his services was against the service conditions and was arbitrary and illegal and hence it could not be justified. It is prayed that the concerned workman be placed in his original post and he may be paid his back wages from September, 1981 when the concerned workman had returned to the colliery and had reported for duty before the colliery Manager.

The case of the management is that the concerned workman was in the habit of absenting from work frequently in an unauthorised manner and for long period without any

permission and satisfactory cause. The concerned workman started absenting from duty continuously without permission and without satisfactory cause with effect from 22-12-80 which is a misconduct under Standing Order 17(i)(n) of Model Standing Orders applicable to the establishment in the coal mines by which the workers of Kuju Colliery are governed. The management sent a charge sheet dated 24/28-1-81 to the concerned workman bringing to his notice his misconduct and calling for his explanation and asking him to resume his duties. The concerned workman did not respond to the said charge sheet. Thereafter the management again sent the concerned workman another charge sheet dated 10/11-8-81 bringing to his notice that he was absenting continuously with effect from 22-12-80 without permission and without satisfactory cause and asking him to resume his duties immediately and to submit his explanation. The said charge sheet was received by the concerned workman but he neither resumed his duties nor submitted his explanation to the charge sheet. After waiting for some time the management terminated his services by an order dated 2-9-81 by which the termination was to take effect from the same date. The concerned workman was guilty of misconduct under the Standing Orders and as such the management was justified in terminating his services for the misconduct. The sponsoring union raised the dispute before the ALC(C) Hazaribagh on 26-8-82 nearly a year after the termination of the services of the concerned workman. The concerned workman had not made any representation to the management even after receiving order of termination of his services on 10-9-81. It was revealed during the conciliation proceeding that the concerned workman was claiming his absence due to sickness and had absented on that account. Admittedly the concerned workman had absented from duty without permission and without satisfactory cause for more than 8 months and the same constituted a misconduct under the Model Standing Order and the management was not required to hold any formal enquiry and was entitled to terminate the services of the concerned workman.

The only question to be determined in this case is whether the termination of the services of the concerned workman was justified.

The management and the workman have each examined one witness in support of their respective cases. The management produced documents which have been marked Ext. M-1 to M-6 series. The workmen produced two documents which have been marked Ext. W-1 and W-2.

It is the admitted case of the parties that the concerned workman absented from duty with effect from 22-12-80 without permission. The management has produced the attendance Register Ext. M-6 to M-6/2 which is the attendance register of Civil Section of Kuju Colliery. It will appear from Ext. M-6/1 that the concerned workman was absenting from 22-12-80. The other attendance registers Ext. M-6 & M-6/2 are not in respect of the relevant period. WW-1 Gopal Prasad is the concerned workman. He has stated that in December, 1980 he was ill and thereafter he went to his village home after working till 20-12-80 in the colliery. On perusal of the Attendance Register Ext. M-6/1 it will appear that 21-12-80 was a Sunday which was a rest day for the concerned workman and accordingly "R" has been noted against the name of the concerned workman on 21-12-80. He has further stated that after receiving the letter of dismissal he went to the colliery and met Gopal Babu. It appears therefore that the concerned workman was absenting from 22-12-80 till the date of termination of his services because it was only after receipt of termination that he came to Kuju Colliery. Thus there is no dispute about the fact that the concerned workman had remained absent for over 10 days. It is stated by the management that the concerned workman had absented without permission or any application. The concerned workman WW-1 has not stated that he had sent any application for leave when he had fallen sick in his village home nor he has filed any copy of such application to show that he had sent any application for leave. The question, therefore, is whether the concerned workman had absented on account of some reasonable ground.

The case of the management is that the charge sheet had been sent to the concerned workman by his village address

and that the second chargesheet of which Ext. M-2 dated 10/11-8-81 is office copy of the original. The management has filed postal registration receipt to show that chargesheet dated 11-8-81 was sent to the concerned workman by Regd. Post. The concerned workman also has accepted that he had received one charge-sheet through post at his village home. He has further stated that he had sent reply to the charge sheet through post under certificate of posting. The copy of the reply of the charge-sheet is marked Ext. W-2 and it is dated 21-8-81. Ext. W-1 dated 21-8-81 is the certificate of posting showing that a letter was sent, to the Manager of Kuju Colliery. The management has no doubt denied the receipt of the explanation to the chargesheet sent by the concerned workman. In view of the fact that the workman possesses the certificate of posting Ext. W-1 dated 21-8-81 shows that the concerned workman had sent his reply to the charge-sheet vide Ext. W-2 dated 21-8-81. The second chargesheet was registered on 11-8-81 and as such it was quite possible for the concerned workman to send its reply vide Ext. W-2 dated 21-8-81. There is no evidence to show that Ext. W-1 and W-2 are not authentic documents. It is clear therefore that the concerned workman had given his explanation to the charge sheet dated 11-8-81. The explanation to the chargesheet Ext. W-2 shows that the concerned workman had received the charge-sheet on 19-8-81 when he was still sick. He has stated in Ext. W-2 that he was unable to move and was under the treatment of some doctor and that he would join his services as soon as he would recover from his illness. It was prayed that his services should not be terminated as he would join soon after the recovery from his illness. It will thus appear that the concerned workman had explained to the management vide Ext. W-2 dated 21-8-81 in reply to the chargesheet Ext. M-2 dated 11-8-81 that he was unable to join his services as he was sick and that he would join his services as soon as he would recover from the disease. Admittedly no reply was sent to the concerned workman in response to Ext. W-2. The concerned workman is a Villager and it was not possible for him to understand the significance of his absence from duty and thought that as he was sick he could remain absent from duty. It appears therefore that the concerned workman has explained his absence from duty due to illness. It appears to be a reasonable ground.

Originally the management after chargesheeting the concerned workman did not hold any domestic enquiry and terminated his services vide Ext. M-5 dated 2-9-81. Absence for over 10 days without leave or permission is a misconduct under the Standing Orders of the Company and as such an order of dismissal could be passed only after the establishment of the charge in the domestic enquiry. The learned Advocate appearing on behalf of the management at the very outset submitted that no domestic enquiry was held by the management into the charges of misconduct against the concerned workman and as such he should be given chance to adduce fresh evidence before the Tribunal and the prayer of the management was allowed. As there was no enquiry made by the management, the management was allowed to produce his evidence to establish the charge.

The concerned workman has asserted that he was sick during the period of his absence and that he had explained the reason of his absence in the reply to the chargesheet. The management has not adduced any evidence to show the falsity of the claim of the concerned workman that he was sick during the period of his absence. In view of the above I hold that the concerned workman has been able to explain the reasons of his absence from his duty and taking the fact that he is a simple villager, his non-filing of an application for leave may be condoned.

The concerned workman had received the letter of his termination dated 2-9-81 at his village home and thereafter he went to the colliery. MW-1 is unable to deny about the said fact. MW-1 has stated that he cannot say if the concerned workman had come in the colliery after the issuance of the termination letter. Thus there is no evidence on behalf of the management to positively deny the fact that the concerned workman had not reported at Kuju Colliery after the receipt of the letter of termination of his services. The concerned workman therefore cannot get wages for the period prior to his reporting for duty at Kuju Colliery

As the concerned workman has been able to explain his absence from duty the management of Kuju of M/s. CC. Ltd is not justified in terminating the services of the concerned workman with effect from 2-9-81 and as such the concerned workman is reinstated in service with effect from 2-9-81 and is entitled to all his back wages from the month of October, 1981 as he had reported for duty sometime after receiving the letter of his termination dated 2-9-81. The concerned workman, however, will not be entitled to his wages for the period of his absence but he will get the continuity of his service.

This is my Award.

DI : 15-1-86

I. N. SINHA, Presiding Officer
[No. I-20012(288)|82-D-III(A)]

का. मा. 634—औद्योगिक विवाद प्रवर्धन विधायक, 1947 (1947 का 14)
की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत कोकिंग कोल लि. की बसुरिया कोलियरी के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2 धनबाद के पचाट का प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार का 21-1-1986 का प्राप्त हुआ था।

S.O. 634.—in pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bussuriya Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 21st January, 1986.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 64 of 1985

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)-(d) of the I.D. Act., 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bussuriya Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri B. Joshi, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri Lalit Burman, Vice President, United Coal Workers Union.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 13th January, 1986

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. I-20012(28-D) III(A), dated, the 28th May, 1985.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bussuriya Colliery in Kusunda Area No. VI of Messrs. Bharat Coking Coal Limited, P.O. Kusunda, Distt. Dhanbad in superannuating Shri Ram Bilash Dusadh, Prop Mazdoor with effect from 18-10-1983 is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled?"

The case of the workmen is that the concerned workman Shri Rambilash Dusadh was working as Prop Mazdoor. He was originally appointed in Alkusa Colliery and was subsequently transferred and posted at Bussuriya Colliery. He was given an identity card No. 64221 by the management of Alkusa Colliery where he was originally appointed in which his date of birth was mentioned as 1-7-1930. According to the said entry the date of superannuation of the concerned workman should be 1-7-1990 on attaining the age of 60 years.

The management of Bassuriya Colliery issued a notice dated 17-9-83 proposing to superannuate the concerned workman with effect from 18-10-83. On receipt of the said notice the concerned workman submitted an application dated 19-9-83 to the Superintendent Bassuriya Colliery objecting to his superannuation and demanded that the notice of superannuation be withdrawn. The management did not take any action on the application of the concerned workman. Thereafter the Vice President of the United Coal Workers Union took up the case of the concerned workman and wrote a letter dated 10-10-83 to the Agent, Bassuriya colliery demanding that in view of the discrepancy regarding the age of the concerned workman recorded in different records of the company, the concerned workman should be referred to the medical board of the company for assessment of his age and in the meantime he should be allowed to continue in the employment till the decision of the Medical Board. The management did not take any action even on the said letter of the Vice President of his union and finally stopped the concerned workman from duty with effect from 18-10-83. The management however had assured the union that necessary action was being taken for referring the case of the concerned workman to the medical board for assessment of his age but actually no action was taken in the matter. Thereafter the union of the workmen served a notice dated 26-11-83 and 5-5-84 to the Agent Bassuriya Colliery that since no action was taken by the management for sending him to the Medical Board, the union had no option but to raise an industrial dispute. Accordingly the union raised an industrial dispute before the ALC(C), Dhanbad vide representation dated 29-5-84. The dispute could not be resolved before the ALC(C), Dhanbad on a report of failure of conciliation sent to the appropriate Government the present reference was made for adjudication to the Tribunal. It is submitted that the action of the management of Bassuriya Colliery in superannuating the concerned workman from his service from 18-10-83 is neither justified nor proper and that the management acted with malafide intention by refusing to refer the case of the concerned workman to the Medical Board for the assessment of his age in violation of standing decision of the JBCCI. It is prayed on behalf of the concerned workman that the concerned workman should be reinstated in his post with full back wages and all other benefits from the date of stoppage of his work till the date of his reinstatement.

The case of the management is that the age of the concerned workman was 48 years on 17-10-71 as per the entry made in Form B Register which is statutory register maintained in the normal course of business. The said entries were duly authenticated by the concerned workman. The concerned workman reached the age of superannuation in the year 1983 and as such he was superannuated with effect from 18-10-83. After the receipt of the letter of superannuation, the concerned workman made a representation that his date of birth has been entered in the identity card as 1-7-1930 and therefore he should not be superannuated from 18-10-83. On examination of the identity card and the relevant register it was detected that the col. in the identity card regarding the date of birth and age was blank due to negligence on the part of the clerk concerned of the management and that subsequently manipulation was made in the age column of the identity card by entering the date of birth as 1-7-1930. The management therefore did not put any reliance on the said entry of the identity card. Form B Register is the basic document and all other documents are secondary in nature and the age recorded in the Form B Register is binding on the concerned workman. If there is any difference in any secondary document which is consistent with the basic documents namely Form B Register, the entries in the basic document has to prevail. The concerned workman failed to adduce any material to establish the genuineness of his claim and as such the management rejected his demand. The management had not ever assured the union or the concerned workman that the concerned workman would be sent to Medical Board for assessment of his age. The management had relied on the age of the concerned workman recorded in Form B Register and as such he did not refer the concerned workman to a medical board for determination of his age. On the above plea it is submitted on behalf of the management that their action is justified.

The only point for consideration is whether the concerned workman had attained the age of superannuation with effect from 18-10-83.

The management and the workmen each examined one witness. The management produced documents which have been marked Ext. M-1 to M-3. The documents produced on behalf of the workmen have been marked Ext. W-1 to W-6.

The management bases his claim for superannuating the concerned workman with effect from 18-10-81 on the basis of the entry of his age in Form B Register. Ext. M-2 is Form B Register of Ganshadih colliery in which there is neither the mention of age nor the date of birth of the concerned workman in Sl. No. 2156. WW-1 is the concerned workman Rambilash Dusadh. He has stated that he was originally employed in Ganshadih colliery in the year 1971 as Prop Mazdoor and that the said Ganshadih Colliery after nationalisation was merged with Alkusa Colliery. He has stated that he had worked in Ganshadih Colliery/Alkusa Colliery till sometime in 1975 till he was transferred to Dhansar Colliery. He has stated that he worked in Dhansar Colliery for about 5 months and thereafter he was transferred to Bassuriya Colliery. There is no denial of the fact that Ganshadih Colliery had merged with Alkusa Colliery after nationalisation. Thus it will appear that there was no mention of age or date of birth of the concerned workman in Form B Register of Ganshadih Colliery where he was first appointed. Ext. M-1 is the identity card of Alkusa Colliery. The name of the concerned workman Rambilash Dusadh is in Sl. No. 64721 of this register. In this register also there is no mention of age or date of birth of the concerned workman and the column meant for the date of birth/age is blank. Ext. M-3 is Form B Register of Bassuriya Colliery in which the name of the concerned workman is entered in Column No. 672. On perusal of the entry in Ext. M-3 it will appear that the age of the concerned workman is mentioned in it as 48 years. Thus it is on the basis of this entry of the age of the concerned workman on which the management is putting his reliance. MW-1 Nandalal who is working as Time Keeper in Bassuriya Colliery has stated on the point as to how the age of the concerned workman was entered in Ext. M-3. He has stated that the workman after appointment used to give all the particulars on the basis of which the management used to record in Form B Register and the age also used to be recorded in the said register as declared by the workman. He has stated that on the transfer of a workman to another colliery he was to show his identity card of his previous employer of the colliery and thereafter Form B Register used to be filled up on the basis of the entries in the identity card. He has further stated that on a transfer from one colliery to other L.P.C. used to be sent by the former to the latter in which there was also the entries of the particulars including the age/date of birth. He has stated that when the concerned workman was transferred to Bassuriya Colliery from Alkusa Colliery there was no entry of his age or date of birth either in his identity card or in the DPC. It further appears from his evidence that when he did not see the entry of the age of the concerned workman in his identity card or the LPC, he made an enquiry from the concerned workman and on his declaration that he was aged 52 years at that time in 1975, he recorded the age of the concerned workman as 48 years on the date of his appointment i.e. on 17-10-71. He has stated that the relevant entry in Form B Register Ext. M-3 is in his writing. It is clear, therefore that either the age or date of birth of the concerned workman had not been mentioned in Form B Register when he was originally appointed and that the age in Ext. M-3 was recorded by a clerk of the management when the concerned workman was transferred to Bassuriya Colliery on the statement of the concerned workman. However, the concerned workman WW-1 has denied that his age was recorded on his statement when he was transferred to Bassuriya Colliery. It is clear therefore that the Register in Form B Ext. M-3 was not written in due course of official business. In cross-examination MW-1 has stated that he was not authorised to fill up the blank column of date of birth in the identity card of the concerned workman when he found the column blank and that he did not take any step to get the date of birth in the identity card of the concerned workman when he found it blank. Earlier MW-1 had stated that he had recorded the age of the concerned workman as 48 years on the date of appointment and as such he could have entered the said age in the identity card of the concerned workman if it was blank but he did not do so. He neither informed the Personnel Department of Alkusa Colliery that the age of the concerned workman was not mentioned in his L.P.C. He has stated

in the last para of his cross-examination that he had no authority to record the age of a workman on the basis of his statement. It is clear therefore that MW-1 had made the entry in Form B Register without any authority and as such it cannot be said that the said age has been duly written by an authorised person. The management under the circumstances cannot give an authenticity of such entry in Form B Register, as the same has been entered by an unauthorised person. Ext. W-6 is the identity card of the concerned workman. In Column meant for date of birth there is entry of age which shows the date of birth of the concerned workman as 1-7-1930. It is stated by the management that it is a subsequent entry as the said column was blank when the identity card was issued. Ext. M-1 is the identity card register of Alkusa Colliery in which there is no mention of the age or date of birth of the concerned workman and as such it appears that the date of birth in Ext. W-6 is not in accordance with the identity card register. The fact that there is no entry of the date of birth or age of the concerned workman in identity card register of Alkusa Colliery the entry of date of birth of the concerned workman in Ext. W-6 which has been issued by Alkusa Colliery appears to be an entry made subsequent to the entries in Ext. M-1. In this view of the matter the date of birth mentioned in Ext. W-6 also appears to be of a very doubtful nature.

In view of the discussion made above it is clear that the age/date of birth as stated by either of the parties does not appear to be correct. Under the circumstances the only course open is to get the age of the concerned workman assessed by the medical board of the company which was being requested by the union on behalf of the concerned workman from the very beginning. The authenticity of the age stated in Form B Register in respect of the concerned workman has lost its force because of the entry by an unauthorised person and this has not authenticated by any officer of the management. As such the management is directed to constitute a medical board for the management of the age/date of birth of the concerned workman within one month of the date of publication of the Award. The question of superannuation will be determined on the assessment of the age/date of birth of the concerned workman by the Medical Board. The concerned workman will be reinstated in his service from the date of the stoppage of his work if medical board finds that he had not attained the age of 60 years at the time of his stoppage of work and the management will pay him all the back wages and continue him in service till he attains the age of superannuation on the age/date of birth assessed by the Medical Board.

The reference is answered accordingly.

Dt : 13-1-86.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012(28)/85-D-III(A)]

का. मा. 635—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारत कोलिंग कोल लि., की जोमगोर कोलियरी के प्रबंध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2 धनबाद के पंचाद को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-1-1986 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 635.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jealgora Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 21st January, 1986.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 10 of 1984

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1) (d) of the I. D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Jealgora Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen :

Shri B. K. Ghose, Member, Executive Committee, Jants Mazdoor Sangh.

On behalf of the employers :

Shri R. S. Murthy, Advocate.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal

INDUSTRY : Coal.

Dated, Dhanbad, the 13th January, 1986

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour & Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012(327)/83-D.III(A), dated the 11th April, 1984.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Jealgora Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. P.O. Jealgora, District Dhanbad (Bihar) in stopping from work Shri Amanat Mia, Mason, with effect from 8-11-81 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled and from which date?"

The case of the workmen is that the concerned workman Shri Amanat Mia was working as a Mason in Jealgora Colliery since the private management which was nationalised with effect from 1-5-72. He was in the employment of the colliery when it was nationalised and therefore his services was taken over by BCCL in which the ownership of the colliery vested after the nationalisation. He was transferred from Jealgora Colliery to the head office of M/s. BCCL in Koyala Nagar Dhanbad in 1981 temporarily for sometime. Subsequently he was retransferred to Jealgora Colliery from Koyala Nagar office and he was allowed to join at Jealgora Colliery on 4-11-81. The management of Jealgora Colliery verbally stopped him from work from 8-11-81 on the ground that the service record had not reached the colliery office from Koyala Nagar Town Administration department. On the repeated approach by the concerned workman, the management of Jealgora Colliery wrote a letter to the then Dy. Manager Town Administration Koyalnagar for an information as to the date of birth of the concerned workman and made over a copy of the letter dated 10-11-81, to the concerned workman. Thereafter the management of Jealgora Colliery kept silent in spite of repeated representation from the concerned workman till a dispute was raised before the ALC(C), Dhanbad. During the conciliation proceeding before the ALC(C), Dhanbad the management in their comment stated that the concerned workman was superannuated from 8-11-81 on the basis of records available at Jealgora Colliery. It was further stated by the management in their comment that the records of Jealgora Colliery showed the date of birth of the concerned workman as 1-7-1921 and that he should have been superannuated with effect from 1-7-81 while he was working in Town Administration Department at the Koyala Nagar itself. The management had failed to produce Form B Register during conciliation proceeding before the ALC(C) although the management had produced the identity card register in which it was found that the column in respect of date of birth of many workmen were blank. The concerned workman had attested the entry in the Identity card register against his name but at that time the column in respect of date of birth was blank and it appears that it was subsequently filled up with a convenient date to refute the workmen's demand. The concerned workman had represented before the management of Town Administration Koyala Nagar on 19-12-80 that the correct date of his birth was 1-7-27 and the records of the management should be corrected accordingly if there was any difference from it. The management of Town Administration did not communicate the decision and transferred the concerned workman to Jealgora Colliery where he was

stopped from 8-11-81. The action of the management in stopping the concerned workman from work with effect from 8-11-81 was not justified and he was entitled to reinstatement in service with full back wages and continuity of employment till he reaches the age of superannuation on 1-7-1987.

The case of the management is that the age of superannuation fixed by the management for its employees is 60 years. As per Form B Register and identity card register the date of birth of the concerned workman is 1-7-1921 and the said entries were duly attested by the concerned workman after they were explained over to him. The records of the C.M.P.F. also indicate the date of birth of the concerned workman as 1-7-1921. In normal course the workman should have been superannuated with effect from 1-7-1981 when he had attained the age of superannuation but due to oversight and lapse on the part of the staff of the management this was not done. The concerned workman had been transferred to the head office of M/s. B.C.C.L. in Koyala Nagar Dhanbad from Jealgora Colliery for sometime. Subsequently he was transferred back to the Jealgora Colliery and he reported for duty at Jealgora Colliery on 4-11-81. It was detected at that time that the workman concerned had attained the age of superannuation much earlier and therefore his employment was discontinued with effect from 8-11-81. The concerned workman had no legal right to continue to work under the management after 30-6-81. According to the conditions of service the concerned workman stood automatically superannuated from 1-7-81 but as he had continued to work even after 30-6-81 till 7-11-81 due to inadvertence, he was paid the wages for that period also but the same cannot give him any right to claim continued payment on any ground whatsoever. The concerned workman was verbally informed, that and he was being superannuated from 8-11-81. The concerned workman knew full well that his date of birth was 1-7-21, and he had at no time produced any document that his date of birth was 1-7-1927. It is submitted on behalf of the management that their action in stopping the concerned workman from work with effect from 8-11-81 was justified and as such entitled to no relief.

The only question for determination is whether the date of birth of the concerned workman was 1-7-1921 or 1-7-1927.

The management examined two witnesses and the workmen examined one witness in support of their respective case. The workmen produced document which are marked Ext. W-1 to W-4 and the documents produced on behalf of the management have been marked as Ext. M-1 to M12.

The management has based his case on the basis of the entry of the date of birth of the concerned workman in the Form B Register and Identity Card Register. The workmen dispute the correctness of the entry of the date of birth of the concerned workman in those registers. Before discussing the other evidence it would be worthwhile to first examine the entries in Form B Register Ext. M-1 and the Identity Card Register of Jealgora Colliery. Ext. M-2. It will appear from Sl. No. 26112 of Ext. M-1 which is an entry in the Form B Register of Jealgora Colliery that the date of birth of the concerned workman was noted as 1-7-21 and age 59 years in column No. 4. There is I.T.I. of the concerned workman in column No. 9. From Ext. M-2 which is an entry in the identity card register, it will appear that 1-7-21 is noted as date of birth of the concerned workman Amanat Mia. MW-1 and MW-2 have been examined regarding the entry in Form B Register Ext. M-1. MW-1 Shri A. K. Singh is presently working as Senior Personnel Officer and he had joined Jealgora Colliery as Welfare Officer in 1977. He has stated that Jealgora colliery is a coking coal mines which was nationalised with effect from 1-5-72 and at the time of nationalisation the management of BCCL got the old Form B Register which was being maintained by the erstwhile management. He has proved the entry Ext. M-1 in the Form B Register regarding the concerned workman and has stated that the date of birth of the concerned workman is shown as 1-7-21 in it. He has further stated that the age of retirement of the employees of BCCL is 60 years. In cross-examination he has stated that Ext. M-1 was a photo

copy of Form B Register which was being maintained by the erstwhile management and were taken at the time of nationalisation. He was unable to say as to when the age and sex column of Ext. M-1 was filled in. As is apparent, on perusal of Ext. M-1, this witness has stated that the date of birth of Amanat Mia is filled up in the column of age and sex but in respect of other workmen in that page there is no mention of date of birth. MW-2 Shri Y. N. Gupta is working as a Clerk in Jealgora Colliery. He has also stated that after nationalised in 1971 BCCL received Form B Register of Jealgora Colliery and he produced the original Form B Register. In cross-examination he has stated that in Form B Register the date of birth of the other workmen except Amanat Mia is not noted but in other pages the date of birth of other workers is noted in the Form B Register. He has further stated that the ink in respect of the entry regarding the date of birth of Amanat Mia is different from the other particulars filled against his name. He has stated that Form B Register was prepared by Nanigopal Babu. According to him also the old Form B Register of the company is still continuing and no new Form B Register have been prepared by BCCL. Thus it is clear that Form B Register which has been produced in the case and of which the relevant entry is Ext. M-1 was an entry made by the erstwhile management and that must have been prior to 1972. It is clear therefore that the entry according to the management regarding the date of birth of the concerned workman was 1-7-1921 and that it was not entered by the management of BCCL. It is very significant to note on perusal of Ext. M-1 that the age of the concerned workman is noted as 59 years and his date of birth is also noted in different ink as 1-7-21. If the age of the concerned workman was noted as 59 years by the erstwhile management prior to the handing over of the Form B Register to BCCL in 1972, the concerned workman would have retired only after a year of the receipt of Form B Register. It is not the case of the management that the age 59 has been interpolated at the instance of the concerned workman. It will also appear on perusal of the the age of the Form B Register in which there is the entry of the name of concerned workman that only the age of other person has been noted and no date of birth has been noted against their name. It has not been explained as to how the age of Md Hanif has been recorded as 68 years and that of Nuddhi Harin as 64 years and that of Jenu as 62 years at the time when the Form B Register was handed over to BCCL because if those workmen were aged more than 60 years they would not have continued in the service after they had attained the age of 60 years. The management has not been able to explain as to when and on what date the said age of the workmen was noted. The entire entry of age in the said page appears to be false and meaningless.

It is stated on behalf of the management that the entry in the identity card register Ext. M-2 was made on the basis of the statement of the concerned workman Jealgora Colliery was nationalised. If really there was entry of the date of birth of the concerned workman in the Form B Register as altered by the management there was absolutely no reason for the management to ask about the date of birth from the concerned workman for making an entry in the identity card register. It follows therefore that as there was no entry of the date of birth of the concerned workman in Form B register the management made an entry in the identity card register after making an enquiry from the concerned workman. The Identity card register Ext. M-2 will show Sl. No. of Form B Register regarding the concerned workman as 206157 and also the date from which he was admitted to C.M.P.F. It will thus appear that Form B Register was consulted at the time of making the entries in Ext. M-2 regarding the concerned workman and as such there was no sense in making any enquiry regarding the date of birth of the concerned workman from the concerned workman. It is obvious that the date of birth in Ext. M-2 has been recorded as 1-7-21 on the basis of the entry of date of birth in Form B Register.

MW-2 has stated that the Agent, Jealgora Colliery had enquired from the Dy. Manager Town Administration regarding the date of the birth of the concerned workman recorded in the office vide Ext. W-1. Ext. W-1 is a letter

dated 10-11-81 under the signature of the Agent, Jealgora Colliery to the Deputy Manager, Town Administration. The Agent enquired the date of birth of the concerned workman recorded in the office of the Town Administration as the concerned workman had been transferred from these to Jealgora Colliery. Form B Register was being maintained by Jealgora Colliery and if there was any entry of the date of birth of the concerned workman in Form B Register there was absolutely no reason for the Agent of Jealgora Colliery to have the date of birth of the concerned workman from the office of the Town Administration Koyala Bhawan. It is clear therefore that there was no entry of the date of birth of the concerned workman in Form B Register and that was the reason why the Agent Jealgora Colliery was making an enquiry about the date of birth of the concerned workman.

It will appear from Ext. M-2 that the concerned workman was admitted to C.M.P.F. from 1-1-50. The management has not filed copy of the C.M.P.F. applications of the concerned workman nor any attempt has been made to call for the C.M.P.F. application of the concerned workman from CMPF Office which would have shown as to what was the date of birth of the concerned workman recorded in 1950 and that would have decided the matter regarding the date of birth of the concerned workman. It is not expected from the concerned workman that any copy of the application is maintained by him and it appears that the management has failed to adduce the most important evidence regarding the date of birth of the concerned workman which would have set the controversy at rest.

On the discussion made above it will appear that the date of birth of the concerned workman as 1-7-21 recorded in Form B Register or Identity card register is not reliable and was not noted at the relevant period and as such it is difficult to put reliance on the said entry.

The concerned workman WW-1 has stated that the date of his birth was 1-7-27. He has produced an affidavit dt. 19-12-80 in which he has stated that his actual date of birth according to the horoscope is 1-7-1927. In cross-examination WW-1 has stated that the date of his birth stated in affidavit was not based on any document. It is clear therefore that he had no horoscope in which the date of his birth was noted as 1-7-27. Thus it appears that the date of birth stated by the concerned workman stated in the affidavit was not based on any document and the said date also appears to be unreliable.

In view of the above discussion, as none of the parties have led evidence to show the date of birth as alleged by them, I think that the matter could be set at rest only by assessment of the age of the concerned workman by the Medical Board constituted by the management and the date of superannuation of the concerned workman will accordingly be fixed.

In the result the management is directed to constitute a medical board within one month from the date of publication of the Award and get the age of the concerned workman assessed. After the assessment of the date of birth of the concerned workman by the medical board, the date of birth and age so assessed by the Medical Board will form the basis for the superannuation of the concerned workman on completion of 60 years. On assessment of such age, the concerned workman will be entitled to superannuation on attaining the age of 60 years and the management will pay him all his wages from the date of stoppage of his work i.e. from 8-11-81 till he attains the age of 60 years after reinstating him from the date of the stoppage of his work. The justification of the action of the management will depend upon the assessment of the age of the concerned workman by the Medical Board.

This is my Award

Date : 13-1-86.

Y. N. SINHA, Presiding Officer
[No L-20012(327)/83-D.III(A)]
A. V. S. SARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1986

का. आ. 636.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, इलाहाबाद बैंक, कानपुर के प्रबंधन में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-1-86 का प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 31st January, 1986

S.O. 636.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Allahabad Bank, Kanpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 21st January, 1986.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL
CUM-1 LABOUR COURT KANPUR

Industrial Dispute No. 252 of 1985

Reference No. L-12012(287)/84. D-II(A) dt. 27th June 1985

In the matter of dispute between

Shri Girish Chandra Bajpai,

C/o. Shri D. N. Awasthi President 127/558/2 Block W/1,
Saket Nagar, Kanpur, 208014.

AND

The manager, Allahabad Bank, City Office, Kanpur.

APPEARANCE

Shri J. C. Dhavan representative—for the workman.

Shri N. C. Pande representative—for the management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/287/84-D. II(A) dt 27th June 1985, has referred the following dispute for adjudication;

Whether the action of the management of Allahabad Bank Kanpur in terminating the services of Shri Girish Chandra Bajpai, sub staff General Ganj Branch, Kanpur with effect from 5-1-1984, is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?

2. The case of the workman Shri Girish Chandra Bajpai is that he was appointed as peon cum farrash on 27-6-79 by the management bank against the permanent vacancy to perform the duties of permanent nature as assigned by the bank management. That the workman worked w.e.f. 27-6-79 to 4-1-84 with the bank management; to their entire satisfaction. The services of the workman Shri Girish Chandra Bajpai were terminated w.e.f. 5-1-84 without giving any notice or pay notice as required in terms of para 522(i) of the Sastri Award or without assigning any reason for termination. It is further alleged by the workman that bank management did not issue any letter of appointment to the workman as is desired under para 495 of the Sastri award nor served any notice of the termination as provided in para 522 (i) of the sastri award. It is alleged by the workman that the bank management first of all terminated his services on 30-12-79 in contravention with the provision of 522(4) of Sastri Award and then the services of the workman were reinstated on 1-1-80 and after serving upto 15-12-80 his services were again terminated. It is further alleged by the workman that the services were appointed and reinstated w.e.f. 2-1-81 and after that the workman worked upto 31-12-80 and completed 261 days within consecutive 12 months and his services were covered under section 25-B of the I.D. Act. But the bank management again contravened the provisions of sec 25-F (abc) by terminating the services of the concerned workman amounting

to unfair labour practice. It is further alleged by the workman that the bank management did not pay the entire scaled salary and allowance to the workman and in the case of workman the bank management very much violative in observing the mandatory provisions of rule 77 of the ID Act. In the end the workman has prayed that he be reinstated in service.

3. The bank management has contested the claim of the workman and has filed the written statement alongwith the chart of number of working days of the concerned workman. The management has raised preliminary objection that the case is not spoused through union and that no demand notice was served upon the management before initiating proceedings before the authorities. The bank management has further alleged that the reference order is bad in law. It has been averred by the management that the services of the workman were taken from time to time purely on the temporary basis on agreed terms, and that the concerned workman was never engaged or appointed against any permanent vacancy as alleged. It is further alleged by the bank management that the workman concerned was engaged temporarily for temporary nature of work as and when exigencies arose. It is alleged that the workman was paid his salary wages agreed with him. It is further alleged that the management is prepared even now to consider the workman for the permanent absorption as sub staff provided he applies in terms of settlement dt. 13-6-82 arrived at with the recognised body of the bank's employees. In the end it is alleged that the workman concerned is not entitled to claim any relief.

4. In the instant case the parties have filed rejoinder and its reply in support of their contention. 16-12-85 was the date fixed in the instant case for filing the joint inspection report but on 16-12-85 inspection report could not be filed hence it was ordered that it be filed on the next date i.e. on 20-12-85. On 20-12-85, parties filed terms of settlement in this case and requested that the award be given in the light of terms of settlement. The terms of settlement is duly verified and is dated 20-12-85, which reads as follows :

1. It is agreed that the workman concerned Shri Girish Chandra Bajpai will be absorbed a fresh with prospective date hereafter in the permanent cadre of peon cum farash.
2. It is further agreed that the workman concerned said Sri Girish Chandra Bajpai voluntarily relinquishes his claim of back wages and/or benefits following the principle of no work no wages.
3. It is further agreed that said Sri Girish Chandra Bajpai will be absorbed as aforesaid within fifteen days of this settlement.
4. Thus this fully and finally resolves the entire matter of dispute under reference.
5. This terms of settlement is signed on behalf of the management by Shri M. K. Verma authorised representative and Shri J. C. Dhawan for the workman.

6. I, therefore, taking into consideration the terms of settlement and request of the parties to decide the case in the light of terms of settlement, give my award accordingly.

Let six copies of this award be sent to the government for publication.

Dated : 16-1-86

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
[No. L-12012/287/84-D. II(A)]

का. अ. 637.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध 1493 GI/85—9

में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-1-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 637.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 21st January, 1986.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM, LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 214 of 83

Reference No. L-12012/259/82-D. II(A) dt. 28-6-83.

In the matter of dispute between

Shri Padam Singh C/o Shri V. K. Gupta 2/363, Namnair, Agra.

AND

The Regional Manager State Bank of India Region II, Laurus Hotel, Agra.

APPEARANCE

Shri V. K. Gupta—for the workman.

Shri P. K. Gupta—for the management.

AWARD

1. The central government vide its notification no. L-12012/259/82-D. II.A. dt. 26-6-83 has referred the following dispute for adjudication;

Whether the action of the management of State Bank of India in relation to their Jalesar Branch under the control of the Regional Manager, Agra in terminating the services of Shri Padam Singh, Temp. Sub staff from 27-5-81 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?

2. That the workman in the instant case is an ex service man and that on being discharged from the defence service he was appointed under the bank management as a guard on 29th November 80 at its Jalesar branch against a regular and permanent vacancy and that the workman worked at Jalesar branch till 27th May 81 when the services of the workman were terminated verbally without any notice and without any specific reasons. When enquired, the workman was told that his appointment is under consideration at Head Office of the bank management and he may be asked to rejoin after hearing from the head office, but from that day nothing was done. The bank management has not followed any provisions of the law of land while terminating the services of the workman and is illegal. In the end it is prayed that the workman be reinstated in service with full back wages.

3. The management has contested the claim of the workman and has filed written statement in support of its stand. It is averred by the management that it is wrong and denied that the services of workman were terminated illegally by the bank. It is also wrong that Shri Padam Singh was entitled to a notice or retrenchment compensation because he was appointed on a temporary basis as in interim arrangement. It is further averred that the appointment of the workman was under consideration at the head office level. It is not disputed that the workman was appointed in the bank services on 29-11-80. It is further averred that Shri Singh was appointed due to transfer of one guard from Jalesar to Islamnagar Branch and an interview was held by local head office Kanpur (now at Lucknow) for the appointment of guard some time in 1980 and appointed of S/Shri Ajit Singh and Tara Chand at Jalesar branch vide their NL No. R-II/42849 dt. 12th December, 1980 was made. In the

and it is alleged that the claim of the workman be rejected being illegal and not maintainable.

4. In the instant case affidavit evidence was filed on behalf of the management and rejoinder was also filed by the workman. On 2-10-85 joint inspection report was also filed by the parties and the case was fixed for 18-11-1985 at Lucknow Camp for cross of the management witness. On that date i.e. 18-10-85 the representative for the workman informed that the whereabouts of the workman is not known to him and the workman is not turning up despite information hence he has nothing to say and withdraws the case.

5. The following orders were passed on today, Shri V. K. Gupta representative for the workman states that the workman is not turning up despite information hence he has nothing to say and withdraws from the case. There is no address of workman except of the union representative Shri V. K. Gupta. The case is decided ex-parte against the workman for want of evidence. Let no claim award be published to Govt.

6. In the instant case the workman is not pressing his claim and the representative for the workman also withdraws himself from the case, the award is being against the workman holding that the action of the bank management in relation to their Jaleswar Branch under the control of the Regional Manager, Agra in terminating the services of Shri Padam Singh, Temu Sub staff from 27-5-81 is justified. The result is that the workman is not entitled to any relief.

7. I therefore, give my award accordingly.

Let six copies of this award be sent to the government for publication.

Dated : 16-1-86

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
[No. L-12012/259/82-D. II(A)]

का. प्र. 638—प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूच में केन्द्रीय सरकार, कानपुराव बैंक के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुसूच में विदित प्रोद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रोद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार की 21-1-86 का प्राप्त हुआ था।

S.O. 638.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Allahabad Bank, Kanpur and their workmen which was received by the Central Government on the 21st January, 1986.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT KANPUR INDUSTRIAL DISPUTE NO. 214 OF 1984

Reference No : L-12012/105/84-D.II(A) dated 19-11-84
In the matter of dispute between :

Shri Munni Lal Chaudhary C/o The State Asstt. General Secretary U.P. Bank Employees' Union, 36/1, Kailash Mandir, Kanpur.

AND

The Deputy General Manager, Allahabad Bank Hazratganj, Lucknow.

Appearance :

Shri V. N. Shekhari—representative for the workman.

Shri Rajeev—representative for the management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification no. L-12012/105/84-D-II(A) dated 19th November 1984 has referred the following dispute for adjudication;

Whether the action of the management of Allahabad Bank Kanpur Main Branch in retaining him from service Shri Munni Lal Chaudhary, Peon/Bill Collector w.e.f. 23-4-84 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?

2. It is common ground that the workman Shri M. L. Chaudhary was a sub staff in the management bank and was retired w.e.f. 23-4-84. It is further not disputed that the workman was appointed in the year 1966. It is alleged that the management wrongly recorded the date of birth of the workman as 24-4-84. The workman obtained a Life Insurance Policy and in reply to a query by said LIC regarding the date of birth of the workman, the management intimated the date of birth of the workman as 24-4-26. This discrepancy was brought to the notice of the head office of the management before retirement of the workman but to no avail and thus the retirement of the workman is premature and illegal. That as a matter of fact, the date of birth of the workman according to the school leaving certificate is 27-7-78 which the workman submitted to the management but he took no note of the same.

3. The management in their written statement reiterated that the date of birth of the workman was rightly recorded in the banks record as 24-4-24 and was rightly retired on 23-4-84 on attaining the age of 60 years which is the age of superannuation.

4. In the rejoinder the workman ascertained that the bank write a wrong notional date on the basis of a certificate of an unauthorised doctor, moreover, the bank itself in reply to a letter of LIC intimated them on 7-3-63 that the date of birth of the workman was 24-4-1926.

5. In support of its contention the management has filed two documents one is copy of the banks circular dated 23-6-83 which speaks that in view of the guide lines received from Indian Banks Association once the date of birth furnished by an employee at the time of appointment is accepted and entered in the service records by appropriate authority the same shall not be subject to any alteration and the second document filed by the management is photo copy of the card report which is in the nature of service book giving father's name, qualification, date of birth and date of appointment and the emoluments on the date of entry. In this card report the father name of workman is recorded as late Shri Ghasite Chaudhary, his date of birth is as 24-4-1924, verified from the doctor's certificate and accepted by him that his qualification was upto sixth class.

6. On the other hand the workman has filed as many as 14 documents, paper no. 1 is the General Manager's letter to the management branch the Mall Kanpur to the Assistant Manager Administration stating that though Shri M. L. Chaudhary was retired on 23-4-84 on completion of 60 years of age, during sorting out records of the branch the management hand over a letter dt. 7-3-63 wherein a query made by LIC, the date of birth of the workman was given as 24-4-26, hence at the instance of the local bank employees union he was forwarding that letter for appropriate action. The second document is photo state copy of the said letter referred in paper no. 1 Ext. W-4 has also been filed in which the date of birth of the workman is recorded as 24-4-26. The workman has also filed acceptance of proposal by LIC for insurance in which the date of the workman is recorded as 49 in the year 75 which is in conformity with the date of birth as 1926. After retirement the workman moved the management for taking him back in service as he should have been retired in the year 1988, the letter is Ext. W-5, the workman has moved the application with the management Ext. W-1 on 7-2-83 wherein he mentioned for the first time that he was in possession of a school-leaving certificate and according to which his date of birth is 2-9-1928. In reply to which the management given him letter Ext. W-5 asking him to explain why he did not advise the bank his correct date of birth when he has record for the same and he was required to submit the original school leaving certificate, on that the chief manager forwarded the school leaving certificate to the Deputy General Manager, Lucknow to advise him in the matter Ext. W-2 is the photo copy of the school leaving certificate of workman giving that the workman studied in EIR B School Babopurwa Kanpur

from 3-7-33 and left the school on 30-6-39 giving his date of birth as 27-7-28. The certificate is signed by the principal on 6-7-39. Other papers filed by the workman are the proceedings before the ALC Central.

7. In support of its contention the management examined one Shri S. N. P. Awasthi on affidavit who is an officer of the management bank at The Mall Kanpur. He has stated therein that in the records maintained in regular course, the date of birth of the workman is recorded as 24-4-24 and he was rightly retired on attaining the age of superannuation i.e. 60 years on 23-4-84. In cross examination he stated that the report of the medical officer mentioned in Ext. W-3 is not traceable. It is further stated that the report card was not maintained by him but was maintained in Head Office. According to him report card file is a confidential document and its copy was not given to the workman. He further stated that except the card report no other list of officials is maintained except the gadation list which has been filed and is maintained in Zonal Office of the bank management. In the end he stated that the initial application of the workman for appointment indicating his date of birth is maintained by head office and that he has not brought the same. If the workman wanted any particular document he should have summoned it from the management.

8. On the other hand the workman has filed his affidavit. He has testified the averments of the statement of claim and rejoinder as correct and relied on them. In cross examination he stated that during study he stayed with his maternal uncle at Baboo Purwa in Loco Railway Colony Kanpur whereas his parents lived in civil lines. He states that the school of baboo purwa was for the wards of the staff of railway employees. He further stated that he took an Insurance policy in the year 1962-63 regarding which his date of birth was taken from the bank and on maturity of first policy he took another policy and in that policy the same date of birth was entered. He however, admits that policy papers of his first policy were given to him in which his date of birth was wrongly written. He states that he represented to the bank management in writing but do not have its copy. The original must be in the bank. If it was so the workman should have summoned the same from the management. He further states that he had given an application for appointment in which his date of birth was given as 27-7-28. If it was really so he should have summoned that paper which was very material document but the workman has admitted that he has not summoned that document from the bank. He admits that he was sent for medical examination at the time of his appointment and that certificate was given by doctor. He further stated that he had school leaving certificate Ext. W-2 soon after he left the school in 1939 but admits that he had not given the document to the Life Insurance Officials and further admits that he did not show that paper to any one except that when demanded by the management. This speaks against the workman. School leaving certificate was a very valuable document regarding the age and he should have produced the same as proof of age at the time of taking LIC Policy. Further the second opportunity he got was when policy papers were given to him. He should have raised objection and got it corrected. It does not appear to reason why the workman kept tied with the school leaving certificate and produced the same only when demanded by the management. He had denied the management's suggestion that the school leaving certificate was not with him when he joined the bank and that he got it prepared later when the bank demanded it.

9. There is presumption regarding old entries made in records maintained in regular course of business, that presumption is rebuttable if rebutted by cogent and reliable evidence. The workman's age recorded at the earliest opportunity in the workman's report card is 24-4-24. This document was prepared as early as 1-8-61. There does not appear to be any earthy reason why the management deliberately recorded a wrong date. Further it shows that at the time of entry in service he was got medically examined which is not mainly done at the time of appointment. It does not mean that he was got medically examined for purpose of age particularly. It may be mentioned here that at age 37 or even at the time of retirement of workman it would not be possible by medical science to give approximate age except from the physical features because medical science of anything age from ossification of bones is not possible at that 1493 GI/85—10.

age. Secondly when this card report was available it appears that by some mistake the age year of birth mentioned in Ext. W-2 was mentioned as 24-4-26. This document was prepared and about two years after the workman's entry in service the earliest opportunity the workman had to get this wrong date of birth corrected was when policy papers were given to him after he was insured in the year 62-63. The workman did not raised any objection then. That mistake was according to him repeated when he obtained second policy in the year 75 but at that time also the mistake was not got corrected. Thus the presumption of correctness of age in the card report stands un rebuttal. Further the workman could have produced the Principal with original record to show that the school leaving certificate was a genuine document and was issued as early as on 6-7-39 but the workman did not produce him or the document for the reasons best known to him.

10. In these circumstances, I see no reason to interfere in the date of birth recorded in the card report as early as 1961.

11. The result is that I hold that the action of the management of Allahabad Bank Kanpur Main Branch in retiring from service Shri Munni Lal Chaudhury Peon/Bill Collector w.o.f. 23-4-84 is justified.

12. I, therefore, give my award accordingly.

Let six copies of this award be sent to the Government for publication.

DATE : 16-1-86

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
[No. L-12012/105/84-D. II (A)]

का. मा. 639—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के प्रसूचन में केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक वाराणसी के प्रबंधक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच प्रमुख में निश्चित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कासपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 21-1-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 639.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India, Varanasi and their workmen, which was received by the Central Government on the 21st January, 1986.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Reference No. L-12012/268/83-DII(A) dt. 4th July, 1984

Industrial Dispute No. 54 of 1984

In the matter of dispute between :

Shri D. K. Singh, House No. S-6/74 Uttam Niwas
Orderly Bazar Varanasi Cantt

AND

The Chief Regional Manager, State Bank of India,
Regional Office Varanasi.

APPEARANCE :

Shri V. V. Mangavadhakar representative—for the workman.

Shri Mahesh Chandra representative—for the Management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/268/83-D.II(A) dt. 4th July, 1984, has referred the following dispute for adjudication :

Whether the action of the Management of State Bank of India, Region III, Varanasi in relation to their Shivpur Branch in discharging from service Shri D.K. Singh, Clerk, w.e.f. 7-7-83 is justified? If not to what relief the workman concerned entitled?

2. It is common ground that on 14-6-76, the workman Shri D. K. Singh was working as clerk incharge for issuing drafts at Management's Rajadarwala Branch at Varanasi. On that day one M/s. Sajid Husain applied for preparation of bank draft for Rs. 9.10 paise only in favour of a particular party of Tanda in District Faizabad (UP). The said bank draft was issued on 14-6-76. According to the workman, the date of issue in the bank draft was altered from 14-5-76 to 10-7-76 and the amount was also changed from Rs. 9.10p to Rs. 9010. The said changed draft with changed date of issue as 10-7-76 was presented at Tanda branch of the bank management on 12-7-76 and the amount paid to the party endorsed therein, the draft was paid without advice from the issuing bank. The advice regarding bank draft issued on 14-6-76 reached at Tanda branch on 25-6-76 but that was not taken into consideration as the amount and date of issue mentioned in the advice did not tally with the draft which was paid on 12-7-76.

3. The workman was suspended on 28-10-77 while working as clerk at Obra branch of the bank management but no charge sheet was served on him or enquiry held and ultimately he was reinstated at his post of clerk on 25-11-78. The management had filed a civil suit on 7-12-77 against said M/s. Sajid Husain who had applied for the draft and on firm M/s. Ramkishan Kanhaiya Lal including its partners Ram Karan and Smt. Pyari Devi. About a year later on 2-11-79 the workman Shri D. K. Singh, was served with a charge sheet signed by the then branch manager in which he was charged having altered the demand draft in favour of M/s. Kanhaiya Lal Ram Karan payable at Tanda branch of the bank management in district Faizabad (UP) will fully and knowingly from Rs. 9.10p to Rs. 9010/-, thus exposing the bank to grave financial risks and avoidable litigation. It may be mentioned here that when the civil suit filed by the bank management the workman was in service. The enquiry on the said charge was set up on 26-2-80 and proceedings started on 8-12-81 at 12 noon and concluded next day i.e. on 9-12-81 at 2 a.m. with a break for one hour. According to the workman in the enquiry report reliance was placed on unproved documents and proceedings were conducted in a hurried manner and the enquiry officer acted as prosecuting officer rather than an independent quasi judicial officer and on the basis of the said hurried enquiry held the workman guilty of the charges framed against him and in consequence of enquiry his services were terminated on 8-7-82 by way of termination simplicitor after paying him retrenchment compensation and salary of one month in lieu of notice. The termination order was also illegal as the workman was appointed by the Deputy Secretary and Treasurer equivalent to the General Manager in the Organisation whereas the services of the workman were terminated by Regional Manager Varanasi an officer much lower in rank than the appointing authority which was illegal. After termination of the workman from the service, the workman was made a party in the civil suit on 17-9-82.

4. The management in its reply has averred that it is a discharge simplicitor of the workman under para 521 (10)(c) of Sastri Award. According to the management, the forgery was detected while marking of the outstanding in the draft paid without advice register, the beneficiary of the bank draft refused to return the said amount received by them by virtue of the aforesaid forgery and it was on that account that a civil suit for recovery of the said money was filed and the management has also lodged a first information report with the police when the fraud came to the notice of the bank management. The management obtained opinion of the hand writing expert regarding the alteration, who reported that the altered portion resembled the hand writing of the writer of the entire draft and it was on that count that the workman was chargesheeted and departmental enquiry held against him. The disciplinary authority who was Regional Manager I Varanasi keeping in view the age of the workman past service record condoned his misconduct and ordered for his discharge simplicitor in terms of para 521 (10)(c) of the Sastri Award which order the disciplinary authority passed on 7-7-82. The management has also taken the plea of loss of confidence in the workman.

5. The workman has filed rejoinder to the written statement filed by the management and has stated therein that the expert was never produced for cross examination before the enquiry officer thus his report is not worthy of reliance. The rejoinder is not by way of explaining the points raised in written statement but is a lengthy 14 paged statement involving argumentative points.

6. In support of its case, the management has filed 16 documents of which Ext. M-1 to Ext. M-20 are admitted.

7. On the other hand the workman has filed 24 documents out of which one is certified copy of the plaint of the civil suit filed by the management which is marked as ext. M-13 and the other is the certified copy of the report of the hand-writing expert. This certified copy which is substantively the same as Ext. M-11 filed by the management. Rest of the documents are the photo copy of letters of the management which are not denied. In order to justify that the discharge of service of the workman Shri D.K. Singh, management besides documents examined one Shri R.N. Agrawal on affidavit. Despite those documents admitted by the workman and filed by the management, witness proved all other documents filed by the management, witness proved all other documents pertaining to the case. He has averred in his affidavit that in view of the opinion of the hand writing expert that the alteration in the amount appeared to be the hand writing of the workman he was proceeded against him departmentally and charge sheet for misconduct which charge was established. It may be mentioned here that though the management on the basis of hand writing expert's report proceeded against the workman, the expert was never examined before the enquiry officer enabling the workman to cross examine him. Thus no reliance on the report of the hand writing expert could be placed.

8. In his affidavit the witness has admitted that the workman was suspected to have complicity in the forgery, he was not impleaded in the civil suit as till then it was not clear that he was also involved in the forgery and that the workman was made a party in the civil suit only after it was established in the enquiry that alteration in the draft was made by the workman and that the termination of services of workman by way of discharge simplicitor under para 521(10)(c) of the Sastri Award.

9. In cross-examination the witness admits that Regional Manager Region I terminated the services of the workman. He has further deposed that the post of Deputy Secretary cum-Treasurer of 1972 is equivalent to the present post of Chief General Manager. He further stated that under the General Manager there are two General Managers one is CGM (Planning) and the other is CGM (Operation) and there are Regional Managers and Chief Regional Managers under the General Managers. The witness has no knowledge about the officials working at Tanda Branch of the bank Management. He further does not know if any investigation was done at Tanda branch regarding the fraud in question. He also admits that the draft in question was paid at Tanda branch without advice from the branch i.e. Ex-advice on the date of payment and that the advice was for Rs. 9.10 paise only. He has no knowledge as to what happened to the first information report lodged by the management with the local police.

10. On the other hand the workman has examined himself on affidavit and filed 10 annexures with it. The charge sheet dated 21-11-79 was signed by the branch manager and was served on him on 21-11-79. As given in the hand book of staff matters Volume II para 523A filed as annexure II with the affidavit, the charge sheet should invariably be signed by disciplinary authority and in the same book a proforma charge sheet given as annexure at page 716 photo copy of which is annexure III with the affidavit, the same should be signed by the disciplinary authority.

11. In his affidavit the workman has averred that the enquiry was conducted in a hurried manner on 8-12-81 and concluded at 2 O'clock in the night on 9-12-81 with a break of one hour at 3.50 p.m. It is further averred that the workman request for producing the hand writing expert for cross-examination by defence as well as for seeking opinion of another hand writing expert on draft in question was also turned down by the enquiry officer. The workman has filed annexure V alongwith his affidavit which is photo copy of Chapter L-1 of the hand book for staff matters Lucknow

Circle Vol. III which lays down that the members of the award staff shall not be dismissed from the service of the bank by an authority lower than the appointing authority.

12. He has further averred that the two opinion given by the hand writing expert one on 10-10-77 and other on 4-11-79 are in consonant. The workman has denied in cross-examination that date was changed from 14-6-76 to 10-7-76 and amount Rs. 9.10 to Rs. 9010 by him and that the changed portion was not in his hand writing. He has further stated that hand writing expert's opinion was given to him during the enquiry but the expert was not produced before the enquiry officer for cross-examination by the management despite demand for the same. He admits that the post of Dy. Secretary and Treasurer was not existing at the time of his termination by the bank management and stated that the same was redesignated as General Manager. In the end he has said that in his case it is a punishment and not discharge simplicitor under para 521(10)(c) of the Sastri award because charge sheet and enquiry has been referred in it.

13. Ext. M-18 is the discharge letter dt. 7th July, 1982 given to the workman. In para 521(10)(c) of Sastri Award; first sentence of this para deals with awarding punishment by way of disciplinary action. It is the second and third sentence occurring in that clause which is material here and which I reproduce as follows;

Whether soonafter extending circumstances exists, the misconduct may be condoned and in such case misconduct is of gross type he may merely discharge with or without notice of on payment of pay and allowances in lieu of notice.

If it was the intention of the management to discharge the workman under the 521(10)(c) of Sastri Award, the punishing/disciplinary authority should have given a speaking order mentioning the extenuating circumstances and stating that as the misconduct charge is a great type he is being discharged simplicitor on payment of one month's pay. If the management wanted to discharge the workman in the next sentence of the said para of the Sastri award which lays down as follows;

Such discharge may also be given where the evidence is found to be insufficient to sustain the charge and where the bank does not for reason or other think it expedient to retain the employee in question any longer in service.

In this case also the order should have been speaking or that the evidence is insufficient to sustain the charge yet for reasons recorded. The management does not considered it expedient to retain the workman in service, only discharge in such cases shall not be deemed to be disciplinary action.

14. In the instant case the very perusal of the term ination order Ext. M-18 punishing authority observes as follows;

Although the charge against you are grave and warrant dismissal from service. You are hereby on account of age and past service discharged from banks service condoning your misconduct.

The word "WARRANT DISMISSAL" in the above sentence shows that after applying his mind to the enquiry proceedings and the charge he too was of the opinion that on the basis of the Enquiry Officer's opinion he should have been dismissed. There is nothing in the order that the evidence for substantiating the charge was person or that any of the extenuating circumstances existed. Thus this order cannot be called to be an order of discharge simplicitor amounting to disciplinary action rather as the observation was that considering the charge, enquiry proceedings only dismissal was warranted yet he was considered liniently under this para is lacking loss. I accordingly hold that the discharge order is not a discharge simplicitor but by way of punishment.

15. As this punishment was by way of discharge simplicitor was after considering the enquiry proceedings in which the enquiry report of the hand writing expert was filed, the mind of the punishing officer and enquiry officer were approached on that ground as the hand writing expert observed that the forgery appeared to have been committed by the writer of the entire draft as there was simprarity in the

original hand writing of the workman and that of the forged hand writing. It is the principle of natural justice that no one should be condoned unheard. If the enquiry officer or the disciplinary authority wanted to rely on the hand writing expert's report he should have been brought before the enquiry officer to prove his report and then an opportunity should have been afforded to the workman to cross-examine him. In the absence of cross-examination the enquiry report should have been afforded to the workman to cross-examine him. In upon an unproved document.

16. The workman at the enquiry stage wanted to obtain report of another hand writing expert which was repelled and the enquiry officer observed as follows;

Had he in doubt in regard to the opinion of the hand writing expert he was at liberty to seek his independent report from any hand writing expert particularly at the stage when Shri Singh "Workman" and his defence counsel both were given sufficient opportunity to personally peruse original drafts, the objection is therefore, over ruled.

The presenting officer stated to the enquiry officer that his statement that alteration have been made in the hand writing of the workman was purely based on the opinion of the hand writing expert

17. The Disciplinary authority in his discharge order has observed as follows;

Nevertheless even if the hand writing expert opinion produced in the enquiry on behalf of the bank is not fully relied. The testimony of the bank witness who was the official incharge during the material time and under whom the employee had been working and the employee's hand writing only proved that the alteration in the draft in question are in hand writing of the employee.

It may be mentioned here that the officer incharge Shri Dubey has simply stated on perusal of the photostat PExt-1 and 5 the hand writing seems to be similar to that of Shri D.K. Singh's hand writing. The enquiry officer himself has not relied on the statement of Shri Dubey officer incharge and has observed that there is no question of similar hand writing if the original draft was prepared in the hand writing of the workman Shri D.K. Singh which is already admitted and if the document exhibited is true photo copy of the original draft and the hand writing is that of Shri Singh and not similar to that of Shri Singh. He further observes that;

His statement is pregnant with the idea that of written matters in the draft seems to be similar to be the hand writing of Shri Singh. He was however, required to specifically state whether alteration in the amount were in the hand writing of Shri Singh or not.

Thus the statement of Shri Dubey Officer incharge is ambiguous and statement of the bank witness to the charges against Shri Singh do not have any weight. If the enquiry officer has not relied on statement of officer incharge Shri Dubey on the point that the altered hand writing of the draft is that of Shri Singh, there is no question of the disciplinary authority relying upon the testimony of officer incharge.

18 I have gone through the expert report and his observation he has taken photo of the writing on the disputed draft for purposes of comparison with the admitted hand writing which was not proper. The writing of the name of the beneficiary M/s. Kanhaiya Lal Ram Kumar on the draft is the writing of the workman is not disputed. After printed word rupees word nine and ten only is not disputed and is rather admitted. What is disputed is that after word nine he had written paisa which has been erased an word thousand replaced in the space. In this word thousand the hand writing expert has comared "Th" of thousand and "Th" carrying at No. 2 and 11 of admitted writing ext. 9 and has observed thus;

Mode of production with the continuation of horizontal strokes and turns of letters "Th" & "Te" of the disputed writing is similar to that of admitted writing marked A2 to A-11.

The pictorial effect of 'in' and occurring at serial no. 2 and 11 in the admitted hand writing ext. M-9 is not similar to 'in' or thousand in the draft. In the draft thousand appears to have not been in normal stroke but at laboured stroke with a view to prepare similar pictorial effect. The vertical stroke of word 'in' in the admitted writing of ext. M-9 at nos. 2 and 11 ends in a notch which is not there in the admitted writing on the draft. The horizontal stroke to complete letter 'n' again begins with a notch and turns in a different way to complete 'n' as depicted in admitted writing ext. M-9 than that occurring in the disputed writing. On this count also the hand writing opinion was no worthy of reliance and the discharge order meted out to the workman on the ground that the charge was grave and after perusal of the enquiry proceedings and findings warranted dismissal was uncalled for. Had this observation in the first paragraph of the punishing order not been there and the discharge order had simply been as mentioned in para 2 it could be said that the discharge order was passed as there was no sufficient evidence to establish the charge. As the two paragraphs in the punishing order are contained in the same letter there could be only one and only one inference that the management punished him with termination though saying that it was a simple discharge under para 521 10 (c) of Sastri Award.

19. Thus discharge from the service of the workman being punishment after enquiry on the charge passed on insufficient evidence.

20. It has been brought to my notice that the charge sheet was not signed by the Disciplinary authority. The management's own document staff circular no. 101 of 1981 shows that award staff posted at Varanasi Regional Manager is the disciplinary authority. The charge sheet Ext. M-2 in the instant case was not signed by the disciplinary authority but was signed by the branch manager. The workman has filed his appointment letter Annexure 1 alongwith his affidavit evidence showing that he was appointed by Dy. Secy.-cum-Treasurer of the bank management. The management witness Shri R. N. Agrawal has admitted that the post of Dy. Secy.-cum-Treasurer occurring earlier is now equivalent to Chief General Manager and under CGM there are two General Managers one for operation and the other is for Planning and that there are CRM and RMS under the general managers. Under para 19.14 of the Bipartite Settlement it has been laid down that the chief executive officer or the principal officer in India of a bank or a alternate officer at the head office or the principal office appointed by him for the purpose shall decide which officer shall be empowered to hold enquiry and take disciplinary action in the case of each office or establishment. He shall also decide officer higher in status for officer authorised to take disciplinary action shall be empowered to deal with and dispose any appeal or order passed in the disciplinary matters. The names of such officer who are empowered to pass the original orders or hear an appeal shall from time to time displaced on notice board.

21. According to the staff circular No. 101 of 1981 issued by the General Manager Operation it was the Regional Manager I who was the disciplinary authority and he was the proper officer to have been passed the punishment Ext. M-18 and not the Chief General Manager being equal to the post of Dy. Secretary-cum-Treasurer. He should have signed the charge sheet also which utmost was an irregularity. In these circumstances and for the reasons discussed above I hold that the action of the management of the State Bank of India Region III Varanasi in relation to their Shivpur Branch in discharging from Service Shri D.K. Singh, clerk w.e.f. 7-7-82 is not justified.

22. The result is that the workman is entitled to be reinstated in service with full back wages.

23. I, therefore, give my award accordingly.

24. Let six copies of this award be sent to the Government for publication.

R.B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

Dt. 16-1-86

[No. L-12012/268/83-D. II(A)]

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1986

कां० 640—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, अलाहाबाद बैंक, लखनऊ के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कामगारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करता है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-1-86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 6th February, 1986

S.O. 640.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Kanpur, as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the Allahabad Bank, Lucknow and their workmen, which was received by the Central Government on the 21st January, 1986.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL—
CUM-LABOUR COURT, KANPUR

I.D. No. 213 of 1984

Reference No. L-12012/93/84-D.II(A) dt. 19-11-84
In the matter of dispute between;

Shri Ram Baboo C/o Shri S. M. Tewari, Authorised
representative for the workman C/o Shri P. N.
Tewari, 165 Sobatiabagh, Allahabad.

AND

The Dy. General Manager, Allahabad Bank, Hazratganj,
Lucknow.

APPEARANCE :

Shri V. N. Sekhari—for the workman.

Shri Rajiv—for the management.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/93/84/D.II(A) dated 19-11-84, has referred the following dispute for adjudication;

Whether the action of the management of Allahabad bank Lucknow in relation of their Kaisarganj Branch Distt. Bahraich in terminating the services of Shri Ram Baboo Ex. temporary peon-cum-farrash w.e.f. 30.4 April, 1982 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?

The case of the workman is that he was appointed by the bank management as peon-cum-farrash in Kaisarganj branch in District Bahraich and worked there more than 240 days in the preceding 12 calendar months prior to his retrenchment on 30-4-82. It is further alleged that the bank management has terminated his services without assigning any reason and that no appointment letter and termination letter was given to the workman and that the workman was also not given retrenchment compensation before his termination on 30-4-82. According to the workman the bank management has violated the mandatory provisions of the Sastri award as well as Sastri award and Industrial Dispute Act. In the end it is requested by the workman that he may be reinstated in service with full back wages.

The case of the workman was contested by the management bank on the ground that the workman never raised any demand and that the tribunal has no jurisdiction to adjudicate upon the matter under reference. It is further averred by the bank management that the workman was not given permanent employment as he was not illegible as per the settlement dated 13-5-82 arrived between bank management and Allahabad Bank Employees Coordination Committee and lastly it is prayed that the claim of the workman is not maintainable hence be rejected.

The workman has filed rejoinder and has reiterated the stand taken in the statement of claim.

The case was fixed for cross of the management witness on 24-10-85 and on 24-10-85 the management filed application to the effect that they are filing settlement in this case hence time may be allowed to them. On the request of the management the case was adjourned to 25-11-85 for filing the settlement. On 25-11-1985 parties filed the terms of settlement duly signed by Shri V. N. Sekhari and Shri Rajeev and was also verified by the parties. The terms of settlement is dated 25-11-1985 and it reads as follows:

- (1) It is agreed that the workman concerned Shri Ram Baboo will be absorbed with prospective date hereafter in the permanent vacancy of peon-cum-farrash in terms of settlement dated 30-5-82 arrived at between the management of Allahabad Bank and All India Allahabad Bank Employee's Coordination Committee.
- (2) It is further agreed that the workman concerned said Shri Ram Baboo voluntarily relinquishes his claim of back wages, dues of past services, or any right or claim or any benefits connected with past services, under this reference.
- (3) It is further agreed that Shri Ram Baboo will submit Bank's printed application form duly completed seeking permanent employment in the Bank's service in the cadre of Peon-cum-Farrash within a week of this settlement.
- (4) It is further agreed that Shri Ram Baboo will be absorbed as aforesaid within 20 days of submission of duly completed Bank's printed application.
- (5) Thus this fully and finally resolves the entire dispute in reference No. 213 of 1984.

As the parties in this case have filed settlement and requested to give award in the light of above, I, therefore, taking into consideration the terms of settlement give my award holding that the workman will be absorbed in the bank's service after 20 days of submission of the application.

I, therefore, give my award accordingly.

Let six copies of this award be sent to the Government for publication.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
[No. L-12012(93)/84-D.II.A]

Dated : 16-1-86.

कां० प्रा० 641 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार श्री चार्जिंग तिथिपति द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, हैदराबाद, के प्रबंधक के खिलाफ उक्त अधिनियम की धारा 33क के अधीन शायर की गई शिकायत के सम्बंध में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद, का पंचाद, जैसे कि अनुबंध में है, प्रकाशित करती है। यह पंचाद केन्द्रीय सरकार को 22-1-86 को प्राप्त हुआ।

S.O. 641.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure in respect of complaint under section 33A of the Act filed by Shri Y. V. Tirupathi against the management of State Bank of India, Hyderabad, which was received by the Central Government on the 22nd January, 1986.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD.

Miscellaneous Petition No. 292 of 1985

IN

Industrial Dispute No. 20 of 1983.

BETWEEN

Sri Y. V. Tirupathi, Workman of State Bank of India, Hyderabad. (A.P.)—Petitioner.

AND

The Management of State Bank of India, Hyderabad. (A.P.)—Respondent.

APPEARANCES :

Shri P. Venkateshwar Rao, President, State Bank of India Staff Association, Hyderabad Circle for Workman.

Sri K. Chalapathi Rao, Law Officer, State Bank of India, Local Head Office, Hyderabad for the Management.

AWARD

This is a complaint filed under Section 33-A of the Industrial Disputes Act, 1947 by one Y. V. Tirupathi, complainant that the Bank has been guilty of contravention of provisions of Section 33 of the I.D. Act for the reasons disclosed in the affidavit. Therefore it is requested that the Tribunal to decide the complaint and pass such orders as necessary.

2. It is mentioned that the complainant Sri Y. V. Tirupathi aged about 32 years as the workman in this dispute and that he raised a dispute against the non-regularisation of service in 1973 by the Management. According to him the Management adopted a method of appointing him for some period and laying him for sometime and each year when he was employed he was asked to give written application atleast two months in advance before the actual date of employment requesting that he may be given further posting in the next Branch; that his employment is likely to be terminated by a particular date and this procedure was being done every time and finally on 3-5-1985 at about 1.30 p.m. when he went with a written application the Officer concerned instead of accepting the application as usual was a little tight lipped and asked him with crisp tone to hand over to the Officer in the Personnel Department as they were handling my Industrial Dispute. Then he approached the office of the Personnel Department and said that he would not be given any employment as per the existing practice, pending Industrial Dispute.

3. The Management filed a counterstating that the application is not maintainable under Section 33-A of the I.D. Act. According to him there is no violation of Section 33 of the I.D. Act. It is mentioned even on the reading of the Petition they do not appear to be any Act which can be brought under Section 33 of the I.D. Act. It is their case that he never worked for 240 days in any year and he being appointed for specific period at a time depending upon the period of leave which the permanent employee has applied for ceased to be in service by afflux of time due to termination. The claimant is a party in I.D. No. 20 of 1983. Hence the question of filing an application under Section 33A does not arise. There is no relationship of master and servant between the Bank and the applicant except that he was taken in service for a short period from 1973 intermittently on temporary basis. There are no alteration of service of conditions after the reference is made in I.D. No. 20/83. It is not obligatory on the part of engaging some persons the principal of Section 25H of the I.D. Act will apply only in the case of retrenched employee under Section 25F of the I.D. Act. It is not open to the applicant to invoke the provisions of Chapter VA and it is not applicable to him.

4. It is interesting to note that both sides admit I.D. No. 20 of 1983 is pending before this Tribunal and I.D. No. 20 of 1983 is a reference made by the Central Government under Sections 7A and 10(1)(d) of the I.D. Act for adjudication by this Tribunal to the following effect:

"Whether the action of the management of State Bank of India, Hyderabad in relation to its Chirage All Lane Branch, Hyderabad in not regularising the service of Sri Y. V. Tirupathi as Messenger in the Bank and terminating his services with effect from 16-12-1982 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

In that I.D. No. 20 of 1983 were both sides hotly contested. It is found that the action of the Management of State Bank of India in not regularising the services of Y. V.

Tirupathi as Messenger in the Bank and terminating his services with effect from 16-12-1982 is not justified and that he is entitled for all the attendant benefits as a permanent employee from 16-12-1982 onwards. Actually even after the said termination on 16-12-1982 which is the subject matter of the reference under I.D. No. 20 of 1983, it is found that after this dispute is referred he was again employed from 1-9-1983 to 18-3-1984 for 209 days and from 7-11-1984 to 25-5-1985 for about another 200 days. Now the complaint is that his termination is likely to end on 25-5-1985 which was not denied and that he sought for extension with the same employment is likely to expire on 7-11-1985 and he put in an application on 3-9-1985 in advance as was the practice and that the Management was rigid on the ground that I.D. No. 20 of 1983 is pending and that wanted the Personnel Manager that he should not be given any more employment as per the existing practice. First of all the fact that he was an employee in a permanent vacancy and that he was first appointed on 5-7-1973 and that he was terminated without even giving 14 days notice and further that there was violation of Section 25F and 25B of the I.D. Act and that there was violation of Circulars 94/78 and 91 dated 16-11-1979 and also Circular 85/76 after Sundera-money's case were all fully discussed in I.D. No. 20/83 and it was held after analysing the evidence of both sides that the action of the Management in not regularising Sri Y. V. Tirupathi while his juniors were subsequently appointed were appointed on permanent basis was not in order and that his termination with effect from 16-12-1982 was not justified. Therefore to say that this application is not in violation of Section 33 and therefore this application under Section 33A of the I.D. Act is not maintainable is not correct. When the main dispute is pending and it is referred and numbered as I.D. No. 20 of 1983 and admittedly when he was being continued even after 16-1-82 on the simple ground that he completed 200 days by virtue of a circular 91 dated 24-9-1981 which is an amendment to Circular 91 dated 16-11-1979. Therefore he should not be kept in service for more than 200 days was being adopted but there is Circular 94/78 that such person who have completed 270 days irrespective of the period should be preferred in giving employment whenever vacancies arise. If so having allowed him to continue after the reference atleast for period of 200 days and having extended his period upto 7-11-1985 it is strange that they do not want to give him any appointment. It amounts to violation of Circular 94 of 1978 and also violation and alteration of conditions of service since he was in service at the time when the reference is made which is numbered as I.D. No. 20/83. In the said circumstances this complaint under Section 33A is maintainable. In the light of the said Award in I.D. No. 20/83 which is already passed, it must be held that he is perfectly justified in filing a complaint under Chapter VA of the I.D. Act, and the same is maintainable and it is also upheld and the Management is directed to post him forthwith employment by dispensing the services of any junior by applying the principle of last come first go in the order of seniority.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him, corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 24th day of December, 1985.

Appendix of Evidence

NIL

J. VENUGOPALA RAO, Industrial Tribunal

[No. L-12025/10/83-D.II.A]

N. K. VERMA, Desk Officer

Dated : 30-12-85.

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1986

कां० प्र० 64 :— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूचन में, केन्द्रीय सरकार, कलकत्ता। पलन ब्यास के प्रबंधन से सम्बन्धित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुसूचन में विविध औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार की 21 जनवरी 1986 की प्राप्त मुद्रा का।

New Delhi, the 31st January, 1986

S.O. 642.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Calcutta Port Trust and their workmen, which was received by the Central Government on the 21st January, 1986.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 22 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Shri Justice N. G. Chowdhury ...Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of Employer.—Shri D. K. Mukherjee, Industrial Relation Officer.

On behalf of Workmen.—Shri G. K. Singh, Vice-President of the Union.

STATE : West Bengal.

INDUSTRY : Port.

AWARD

By Order No. L-32012/24/80-D. IV (A) dated 13-5-1981 Government of India, Ministry of Labour referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the management in relation to the Calcutta Port Trust, Calcutta are justified in denying with effect from the 14th June, 1960 the post of Telephone Clerk/LDC to Shri Permanand Pandey designated as a Junior Clerk in the Security Section ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. The question has obviously three implications, namely (i) that Shri Permanand Pandey was a Junior Clerk on 14-6-1960, (ii) on the said date the post of Telephone Clerk/LDC was in existence and lying vacant and (iii) the management without any justification ignored the eligibility or claim otherwise of Shri Pandey for the last mentioned post.

3. Salient undisputed facts of this case are as follows : Shri Permanand Pandey was appointed as a Watchman attached to the security section of Calcutta Port Trust on 15-9-1959. He was specifically posted as a Watchman in the office on 14-6-1960. He was allowed a special allowance of Rs. 30 per month along with some other watchmen for performance of semi-clerical duty and also telephone duty from 1-5-1969. The two unions operating in the field raised dispute as to whether or not discharge of telephone duty required creation of special post, if so, how many posts were to be created and how the posts should be filled up. For a decision on the above questions an arbitration agreement was signed on 19-5-1975 by the management of Calcutta Port Trust and the workmen represented by Calcutta Port Shramik Union and National Union of Waterfront Workers. The Arbitrator gave his award on 29-5-1976, the said award was published in the Gazette of India on 26-6-1976. Shri Pandey, the Watchman was promoted to the post of Junior Clerk with 11 other watchmen on the basis of the arbitration award on 26-6-1976. He was adjusted as a Junior Clerk (LDC grade) and allowed the pay scale of L.D.C. from 1-11-1980. Shri Pandey was again adjusted as L.D.C. (special grade) along with other Junior Clerks of L.D.C. grade on the basis of memorandum of settlement with retrospective effect from 26-6-1976. From the dispute referred to the Tribunal and the dates given above it emerges that (1) Shri Pandey's initial appointment was not as a Clerk but as a Watchman. The difference between the nature of the two types of ser-

vices is obvious; A security Section Watchman works outdoor while a clerk works indoor at the desk. (ii) There was a total change as to the class of service Shri Pandey was rendering on 26-6-1976. Before that date Shri Pandey was not a clerk, he was a Watchman and as a Watchman he rendered some unusual or unexpected service of clerical nature and attended telephone from 14-6-1960 to 1-5-1969. For the above work Shri Permanand Pandey received a special allowance of Rs. 30 per month in addition to his grade pay as a Watchman. In the above context Shri Pandey should not have any grievance but the union sponsoring his case claims that Shri Pandey should have been appointed as a Telephone Clerk/LDC with effect from 14-6-1960. The reason given in support of such claim seems to be that on the relevant date i.e., 14-6-1960 Shri Pandey was already designated as a Junior Clerk. It is further contended that the management was not justified in denying Shri Permanand Pandey the post of Telephone Clerk/LDC with effect from 14-6-1960. We have already noted that on 14-6-1960 Shri Pandey was not a Junior Clerk even then he was a Security Watchman. Further the post of Telephone Clerk/LDC was not in existence on 14-6-1960 so the dispute referred to the Tribunal must be found against Shri Permanand Pandey and the question framed must be answered in the negative.

My predecessor in office prima facie found that the preliminary question regarding resjudicata against Shri Pandey, I do not enter into that question as that seems to be unnecessary in my view.

4. In course of arguments with the help of a series of documents marked as exhibits both the parties tried to explain to this Tribunal how the problem of creating additional clerical posts arose; who were functioning in the additional posts and what designation they held and how the manner of selection of candidates for the posts created was tackled. I do not go into these details because they have little relevance to the dispute referred to the Tribunal. The documents and arguments only cause confusion. I have clearly spelt out the question of implications of the dispute referred to the Tribunal and undisputed facts. I have already answered the question referred to the Tribunal in the negative.

An award be made and published in terms of my answer.
Dated, Calcutta,

The 15th January, 1986.

N. G. CHOWDHURY, Presiding Officer

[No. L-32012/14/80-D. IV (A)]

K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1986

का० आ० 643:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार गणेश क्वारी वर्क्स शकखाना इन्दावरना, जिला बरख क्वारी के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच प्रमुख में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, अहमदाबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केंद्रीय सरकार को 21 जनवरी, 86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 5th February, 1986

S.O. 643.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Ahmedabad, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Ganesh Quarry Works, P.O. Indravarna, District Bharuch Quarry Owners and their workmen, which was received by the Central Government on the 21st January 1986.

BEFORE SHRI G. S. BAROT, PRESIDING OFFICER,
INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT AHMEDABAD

Reference (ITC) No. 33 of 1984

Adjudication.

BETWEEN

The Ganesh Quarry Works, Nani Raval, P.O. Indravarna, Tal. Nandod, Distt. Bharuch.

AND

The workmen employed under it.

In the matter of termination of the services of Shri Subhashbhai Jethabhai Tadv.

APPEARANCES :

None—for the employer.

None—for the workmen.

AWARD

This Industrial Dispute between the Ganesh Quarry Works, Nani Raval, P.O. Indravarna, Tal. Nandod, Distt. Bharuch, ("the employer" to be brief) and the workmen employed under it, has been referred for adjudication to this Industrial Tribunal by the Central Government vide Ministry of Labour & Rehabilitation, Order No. L-29012/1/84-D.III(B) dated 16-6-1984. The dispute, as mentioned in the schedule appended to the order of reference, is as under:—

"Whether the action of the management of Messrs. Ganesh Quarry Works, P.O. Indravarna, Distt. Bharuch, Quarry Owners, in terminating the services of Shri Subhashbhai Jethabhai Tadv, workman, with effect from 1-10-82 is legal and justified? If not, what relief is the workman concerned entitled?"

2. Soon after the reference was received, notices were issued to the parties whereby the sponsoring Union was asked to file its statement of claim by 28-8-84 and the employer was asked to file its written statement by 28-9-84. However, no statements were received from the parties. Thereupon, the matter was fixed for hearing on 5-12-84 and notices to that effect were issued to both the parties. It appears from the rojnama that on 5-12-84, neither of the parties remained present, and the matter had therefore to be adjourned to 6-2-85 and further adjourned to 4-4-85. It is clear from the record that the Registered notices issued to the parties advising them of the date of hearing viz. 4-4-85 were duly served on both the parties. However, on 4-4-85 while Shri Mathurbhai C. Patel appeared for the employer, nobody was present for the Union. Nevertheless, in order to give further opportunity, the matter was adjourned to 23-4-85, then to 14-10-85 and finally to 1-11-85. However, on none of these dates, anybody remained present for either of the parties. It is very clear from this that neither of the parties is interested in this matter. Atleast the Union which has sponsored this case should have cared to remain present and made its submissions, if any. However, it has not even filed its statement of claim. Under these peculiar circumstances, there is no point in keeping this matter pending further. Thus, the present reference stands disposed of. No order as to costs.

G. S. BAROT, Presiding Officer

[No. L-29012/1/84-D.III(B)]

SHASHI BHUSHAN, Under Secy.

Dated : Ahmedabad, 31-12-1985.

